चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 27 जुलाई –02 अगस्त 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

व्यापमं घोटाले का ख़ुलासा करने वालों की

जान ख़तरे में है

देश का हृदय प्रदेश कहलाने वाले मध्य प्रदेश पर इन दिनों हर खास-ओ-आम की नज़र टिकी हुई है. वजह यह कि इस राज्य में हुए व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. तकरीबन पचास लोगों के प्राणों की आहुति लेने वाले व्यापमं घोटाले की कथा अनंत है. सीबीआई जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता. लेकिन, इस घोटाले को सीबीआई के घाट तक पहुंचाने वाले व्हिसिल ब्लोअर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स और सूचना के सिपाहियों ने किस हद तक जान की बाजी लगाकर काम किया, किन-किन चुनौतियों ने उनका रास्ता रोका, उसी को इस बार अपनी कवर स्टोरी का विषय बनाया है चौथी दुनिया ने. जानिए व्यापमं की पूरी कहानी, इन्हीं व्हिसिल ब्लोअर्स की ज़ुबानी...

जनता को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है

सिद्धार्थ वरदराजन

यह बात पिछले दो-तीन सालों से चल रही है कि हिंदुस्तान में जो व्हिसिल ब्लोअर हैं, उन्हें महफूज रखने के लिए क़ानूनी प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है. व्यापमं की मिसाल सबके सामने है, जिसमें 47 लोगों का इंतकाल हुआ. 47 में से 47 यानी सारे मामले रहस्यमय तो शायद नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी मिसालें मीडिया में आ चुकी हैं, जहां पर वाकई ऐसा लगता है कि लोगों का कत्ल हुआ. कत्ल के बाद कवरअप हुआ और जिस तरह से सियासी दबाव सब पर पड़ा है, उससे मुझे लगता है कि इस बाबत एक सख्त क़ानून लागू करने के लिए कोर्ट का इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गुनाह के साथ सियासतदां और सत्ताधारी नेताओं की मिलीभगत होती है, तो आम नागरिक कचहरी के दरवाजे पर दस्तक देता है. न सिर्फ़ व्यापमं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में जो घोटाले हैं, उनकी ठीक से जांच नहीं हो पाएगी. दूसरी बात यह कि व्यापमं बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक-प्राइवेट स्कैम की एक मिसाल है.

अहिल्याबाई विश्वविद्यालय या बिहार में जो हुआ, वह अपनी जगह निंदनीय है, निंदा करनी चाहिए. लेकिन, व्यापमं में जो हुआ, पब्लिक-प्राइवेट शिक्षा के बाज़ारीकरण का जो सिलसिला हिंदुस्तान में चला, उसके लिए साजिश रचाई गई सियासतदां, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के साथ मिलकर. यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि कहीं न कहीं इसमें ज्यूडिशियरी या लीगल लोग भी शामिल हैं, कम से कम उनका हाथ कहीं न कहीं नज़र आता है. इस देश में थोक के भाव स्पेक्ट्रम भी बेचा जाता है, कोयला भी बेचा गया, शिक्षा भी बेची गई और मेडिकल शिक्षा भी. अगर इस देश में पिछले 60-65 सालों से तालीम की इतनी किल्लत है, शिक्षा का इतना अभाव है, तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है, उसे वहां अच्छी से अच्छी सुविधाएं जुटाने में खर्च नहीं किया जा रहा है. क्यों नहीं किया जा रहा है? सियासतदां की वरीयता कहीं और है.

सरकारी तिजोरी खाली है, तो उसकी वजह यह भी है कि बहुत सारी चीजों, जिनसे सरकारी रेवेन्यू (पैसा) बनाया जा सकता था, को या तो मुफ्त या फिर बहुत कम दामों में उद्योगपतियों को बेचा गया. अगर हम व्यापमं की बात करें, तो एक पूरा ढांचा ही सामने नज़र आता है. व्यापमं बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, एक्जामिनेशंस और कई चीजें. लेकिन, यहां ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाया जा रहा है, जो एकदम काबिल नहीं हैं और ये लोग आगे जाकर लोगों की हत्या करेंगे. लेकिन, ऐसा सिर्फ़ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है. आपको याद होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो स्कैम निकला और केतन देसाई के ख़िलाफ़ जिस तरह कोर्ट ने कार्रवाई चलाने की बात की, उस पर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा. लेकिन क्या कहीं मेडिकल काउंसिल में पारदर्शिता है, क्या हिंदुस्तान में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम सही सलामत है? मुझे यकीन नहीं आता. और, इसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं, सड़े-गले सिस्टम को बचाने के लिए, करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए, करप्ट लोगों को बचाने के लिए.

व्यापमं स्कैम से पहले मीडिया में मोदीगेट खूब चला. मोदीगेट और व्यापमं में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज यह है कि नेता और क्रिकेट का मिश्रण, नेता और शिक्षा का मिश्रण. सियासतदां का इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं घोटाले की जड़ बन चुका है. आने वाले दिनों में अगर हिंदुस्तान इन चीजों से अपने आपको मुक्त कराना चाहता है, तो हिंदुस्तान के जो तमाम नेता हैं, उनसे हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई, आप सियासत तक अपना काम सीमित रखें, क्रिकेट में मत जाइए, शिक्षा में मत जाइए, स्वास्थ्य में मत जाइए. जो भी नुक़सान आपको करना है, एक क्षेत्र में करें, उसी दायरे में रहिए. चौथी बात यह कि हिंदुस्तान में इंवेस्टिगेशन करेगा कौन? मेरे ज़ेहन में यह सवाल उठा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर कोई बात छिपानी हो, तो आप कमीशन या कमेटी का गठन कर दें, उसे स्थापित कर दें. और, हमारे देश में कोई ऐसी खास जगह है, जहां से जजेज को चुन-चुन कर निकाला जाता है. कभी नानावती के नाम से, कभी रंगनाथ मिश्र के नाम से या लिब्रहान के नाम से, जो 10-12 या 15-20 साल लगाएंगे, लेकिन सच आपके सामने कभी पेश नहीं करेंगे. अगर हिंदुस्तान इन घोटालों का ख़ात्मा करना चाहता है, तो कम से कम यह जो खास जगह है, जहां से जजेज का चयन होता है, वह जगह प्लीज हम बंद कर दें. रही सीबीआई की बात, तो मैं भी उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सीबीआई इस जांच (व्यापमं) को सही-सलामत, ठीक तरीके से चलाए, लेकिन सीबीआई की हालत क्या है, वह भी सभी लोग जानते हैं.

हम रहस्यमय स्थितियों में हुई मौतों की बात कर रहे हैं. गुजरात में एक महिला कौशर बी का कत्ल हुआ, उनके शौहर सोहराबुद्दीन का कत्ल हुआ, उनके दोस्त तुलसीराम प्रजापति का कत्ल हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन तीनों कत्ल की जांच ठीक तरीके से सीबीआई करे. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई, चार्जशीट वगैरह दाखिल हुई, लेकिन पिछले साल दिसंबर में एक प्रमुख आरोपी को मुक़दमे से पहले ही केस से डिस्चार्ज कर दिया गया. चलिए यह सब होता है, लेकिन हिंदुस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री या क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तफ्तीश की, केस फाइल किया और जिसके बारे में हम लोग सही कहा करते थे कि यह पिंजरे के अंदर बंद तोता है, तो उस तोते ने आज तक अपील नहीं की और अमित शाह के साथ-साथ सात अन्य लोग भी डिस्चार्ज हो गए. वह केस कहां जाएगा, किस मुकाम तक पहुंचेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि वह इंसाफ की दिशा में नहीं जा रहा है.

एक और मिसाल. रोहिणी सालियान नामक एक सरकारी वकील हैं. उन्होंने अख़बारों में, टेलीविजन में बयान दिया है कि उन पर दबाव पड़ रहा है कि वह कुछ लोगों के ख़िलाफ़, जिन पर दहशतगर्दी का इल्जाम है, मुक़दमा सही तरीके से न चलाएं. उन्होंने न सिर्फ़ आरोप लगाया है, बल्कि हाल में उन्होंने कहा कि वह वरिष्ठ वकील हैं, वह ऐसे आरोप यूं ही नहीं लगातीं, उनके पास सुबूत भी हैं. मैं इंतजार कर रहा हूं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट सुओ-मोटो एक्शन ले कि एक वरिष्ठ वकील सरकार पर ऐसा गंभीर आरोप लगा रही है, इसे इंवेस्टिगेट किया जाए. अगर सुप्रीम कोर्ट यह तय करे कि सीबीआई वाकई में सरकार के दबाव में काम करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट यह तय करे कि व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई उसकी देखरेख या नियंत्रण में करे और सिविल सोसायटी, मीडिया का दबाव बना रहे, तो हो सकता है कि तमाम बाधाओं के बावजूद जांच अपने सही अंजाम तक पहुंचे. सुबूत तो पहले ही नष्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यह समझ ले कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता की उम्मीद उससे जुड़ी है, तो हो सकता है कि तमाम जो लोग इस घोटाले में शामिल रहे हैं, उन्हें अपने किए की सजा मिले. ■

-लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

feedback@chauthiduniya.com

व्यापमं की कहानी, व्हिसिल ब्लोअर्स की ज़ुबानी

सुरक्षाकर्मी जान से मारने की धमकी देते थे : आशीष चतुर्वेदी P-2

गोली इधर से जाएगी, उधर से निकल जाएगी : प्रशांत पांडेय P-3

दस साल में पूरी शिक्षा बिक गई: अजय दुबे P-4

शिवराज दूध के धुले नहीं हैं : डॉ. आनंद राय P-4

सुरक्षाकर्मी जान से मारने की धमकी देते थे

आशीष चतुर्वेदी

व्यापमं न केवल शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित भ्रष्टाचार है, बल्कि यह आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं पर कब्जा करने का भ्रष्टाचार है, युवाओं के रोज़गार के साथ किया जाने वाला भ्रष्टाचार है, जन-स्वास्थ्य के साथ किया जाने वाला भ्रष्टाचार है. इस भ्रष्टाचार के साथ मेरी लड़ाई की शुरुआत तब हुई, जब मैं अपनी माता जी के कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल जाता था. यह 2009 की बात है. इलाज के लिए कई सारे डॉक्टरों से मिलना-जुलना, संपर्क करना पड़ता था. कुछ डॉक्टरों का व्यवहार और काम देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे मरीज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मरीज के लिए उनके दिल में कोई भावना है. कई डॉक्टर ऐसे भी थे, जो वास्तव में एक आम आदमी, पीड़ित आदमी की मदद करना चाहते थे. दोनों पक्षों से जब मेरा आमना-सामना हुआ, सारी चीजें सामने आईं. जो डॉक्टर ग़रीब-परेशान आदमी की मदद करना चाहते थे, वे स्वयं जाकर उसकी मदद कर देते थे. ऐसे ही लोगों ने बताया कि मेडिकल प्रोफेशन में इस असमानता का एक कारण यह है कि कई लोग ऐसे हैं, जो पैसे के दम पर इस पेशे में आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि उनका एक अलग रास्ता था. मुझे लगा कि पता करना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा प्रोफेशन है, जिसमें उस आदमी को आना चाहिए, जिसके अंदर सेवा का भाव हो, क्योंकि मरीज पूरी तरह से डॉक्टर पर निर्भर होता है.

ये सारी चीजें देखते हुए आगे चलता गया. 2010 के दौरान बिजेंद्र रघुवंशी नामक एक शख्स मेरे संपर्क में आया, जिसने 2009 बैच में गजराराजे मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में फर्जी तरीके से एडमीशन लिया था. जब उससे बात हुई, तो उसने बताया कि शुरुआती तौर पर मेडिकल की पढ़ाई (पीएमटी) के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसके बाद टॉप रैंक आती है. कॉलेज में उसकी जो एक्टिविटी थी, उससे लगता नहीं था कि उसने इतनी मेहनत की होगी. परीक्षा पास करने के लिए वह ग्वालियर विश्वविद्यालय में पैसे दिया करता था. 2009 के पीएमटी में रैंक निकाल कर आया. 2010 आते-आते 18 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि वह 50 हज़ार रुपये प्रति विषय पास होने के लिए दे रहा है, नंबर बढ़ाने के लिए दे रहा है. 18 महीने में उसकी परफॉर्मेंस इतनी खराब कैसे हो गई? वे सारी चीजें कहीं न कहीं अविश्वसनीय लगती थीं. यह सब देखते हुए कुछ शिकायतें की गईं. उसके बाद 2011 में एक कमेटी बनी, जिसमें 2009 बैच के 114 लोग सस्पेंड किए गए, जिनमें उसका (बिजेंद्र रघुवंशी) भी नाम शामिल था.

उसके बाद उसने मुझसे संपर्क किया. मुझे तो पता था कि अख़बारों में उसका नाम छप चुका है, लेकिन जब मेरी उससे बात हुई, तो मैंने यह जाहिर नहीं किया. उसने कहा, पता है आशीष भाई, पहली बार पेपर में नाम आया है. मैंने पूछा कि ऐसा क्या कर लेते हो अकेले-अकेले और बताते भी नहीं हो, पेपर में नाम छपवा रहे हो? इसके बाद उसने कहा, रुको तो, सुनो तो. मैंने कहा, सुनें क्या, अकेले-अकेले ऐसा काम कर रहे हो. उसने बताया कि पेपर में नाम छपा है, सस्पेंड कर दिया है, कई सारे लोग हैं. फिर उसने बैचमेट्स के नाम भी बताए. मैंने कहा, ठीक है, परेशान क्यों होते हो? उसने कहा, मेरा भी नाम है. मैंने कहा, ऐसा कैसे हो गया? टॉप रैंक के पढ़ने वाले लड़के हो तुम. सरकार पर केस करते हैं, मानहानि का भी केस करते हैं. इसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं. उसने कहा, मेरी बात सुन लो, मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, सुनाओ, क्योंकि मुझे सच्चाई पता करनी थी. उसका अलग इरादा था कि आशीष का यहां के लड़कों से संपर्क है, नए लड़के लाकर देगा. बेरोज़गार है, मां भी बीमार है, पैसे के लालच में आएगा. मैंने भी उसकी हां में हां मिला दी और कहा कि बिल्कुल मदद करूंगा.

उसने बताया कि जब वह पीएमटी की तैयारी कर रहा था, तो उसके पिताजी के पास एक ऑफर आया कि तुम्हारे लड़के को तुरंत डॉक्टर बना सकते हैं. उसने कहा कि जिस दिन उसका पेपर दिल्ली में हो रहा था, उस वक्त वह भोपाल के डीबी मॉल में फिल्म देख रहा था. सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, खुद के कानों पर विश्वास नहीं हुआ. कोई आदमी मध्य प्रदेश में फिल्म देखते हुए डॉक्टर बन सकता है! मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की हालत इतनी खराब है. मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा, ये सारी चीजें हो जाती हैं. मैंने पूछा, इसमें क्या मदद चाहिए. उसने कहा, और लोगों को हम निकालेंगे, बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ज़्यादा लोग बाहर होंगे. बहुमत की बात वहां आई, क्योंकि वह पहले से पॉलिटिकल फैमिली संबंधित था. उसने कहा कि ज़्यादा लोग मेरे साथ होंगे, अभी 36 लोग बाहर निकाले हैं. ज़्यादा लोग होंगे, तो मुझे फिर से अंदर कर लेंगे.

मैंने कहा, ठीक है, करते हैं कैसे भी. हम लड़के लेकर आएंगे. 2011 के पीएमटी में वह मुझे भी अपने साथ ले गया. पीएमटी का पेपर मेरे सामने आया. फिर से वही सारी चीजें! मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. मेडिकल का पेपर होता है, पुलिस लगी होती है, सारा सिस्टम लगा होता है कि पेपर हम कराने वाले हैं. सारा सिस्टम इस बात को लेकर सीना ठोंकता है, दावा करता है कि पेपर पूरी तरह से फेयर होगा. लेकिन, उसके बाद भी ये सारी चीजें होती रहती हैं. पेपर आउट होता है. जिन्हें पेपर नहीं मिलता, उनकी अंदर से सेटिंग करा लेते हैं, पेयरिंग करा लेते हैं, ओएमआर सीट खाली छोड़ देते हैं. इसके बाद अगस्त 2011 में मुझे काउंसलिंग में जाने का मौक़ा मिला, तब तक निजी मेडिकल कॉलेजों का घोटाला मेरे सामने नहीं आया था. निजी मेडिकल कॉलेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या तकनीक थी, किसी को नहीं पता था. जब मैं काउंसलिंग में गया, तो वहां देखा कि जूनियर लड़के, जो उसके साथ सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वे वहां थे. ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम खराब है. वे सारे लोग मिलकर जो पहले से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे पेपर दिलाकर निजी कॉलेजों की सीटें ब्लॉक करा लेते थे. वे सीटें ऐसे उम्मीदवारों के लिए रहती हैं, जिन्हें किसी सरकारी कॉलेज में सीट नहीं मिल पाती. वे सब सरकारी कोटे की सीटें हैं, जिनके एवज में सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों को टैक्स सब्सिडी देती है. बिजली में सब्सिडी देती है. ये सारी चीजें देखीं, तो निजी मेडिकल कॉलेजों का घोटाला सामने आया.

2011 में यह सारी सच्चाई मेरे सामने आई, तो इसकी शिकायत की गई. उस दौरान शिकायत करते-करते अधिकारियों को बताते हुए मैं मंत्रालय पहुंचा, तो मंत्रालय में सचिव मुझसे कहते हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली है, तुम भी नशा लो, तुम्हें भी मजा आएगा. जब मैंने उनसे कहा, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा मत कहिए, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें कुछ मिला नहीं होगा. जब तुम्हें भी कुछ मिलने लगेगा, तो तुम्हें भी मजा आने लगेगा. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां सुनने वाला कोई है नहीं. जिसे बोलो, वह कहता है कि तुम भी मजे लो. जबरदस्ती नशा-मजा देने वाले लोग हैं. उन्होंने पूरी नस्ल खराब कर दी. इसके बाद मैं मुख्यमंत्री सचिवालय गया, यह बात है अप्रैल 2013 की. मुख्यमंत्री सचिवालय में शिकायत की. पूरे चार दिनों के प्रयास के बाद 15 लोगों के ख़िलाफ़ एफआरआई दर्ज की गई. उसके बाद उन्होंने सीना ठोका कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली इतने लोगों के ख़िलाफ़. इसके बाद जब मैं ग्वालियर गया, तो बताया गया कि मामला फर्जी भर्ती का है. मैंने कहा, ठीक है, एफआईआर दर्ज कर ली, अब आगे जांच-पड़ताल कीजिए, और भी लोग पकड़े जाएंगे. लगातार पूरा मामला पेंडिंग बना रहा. मामले को लगातार दबाया गया. पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले में रुचि नहीं थी, क्योंकि थाने का जो मामला होता है, उसमें कुछ मिलना होता है. जब सीधे पैसा आ रहा है, तो क्यों वे इस मामले में क्यों उलझें. मामला लगातार पेंडिंग बना रहा.

2013 में पेपर आउट हुआ, तो उसकी सूचना दी गई. उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते आ रहे हैं कि वह व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर हैं. मेरे पास उनके ख़िलाफ़ पर्याप्त और पुख्ता प्रमाण हैं, 2011 में उन्हें (शिवराज सिंह) प्रमाणित तौर पर सिस्टम से जानकारी दी गई थी कि उनकी सरकार में घोटाला चल रहा है, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, गड़बड़ियां चल रही हैं. गड़बड़ियों की जो जांच चल रही है, उसमें भी घोटाला चल रहा है. दूसरी जानकारी भी उन्हें दी गई कि सरकार घोटाले की जांच तो करा रही है, लेकिन जांच के नाम पर घोटाला हो रहा है. उसके बाद भी शिवराज कहते हैं कि वह व्हिसिल ब्लोअर हैं. 2013 में ही उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वह व्हिसिल ब्लोअर हैं? ऐसा उन्हें 2011 में क्यों नहीं लगा? 2012 में क्यों नहीं लगा? लगातार मध्य प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर धोखा देना आख़िर किस लिहाज से जायज है? यह धोखेबाजी-जालसाजी जो अब तक करते आए हैं, इसे आप कब तक चलाएंगे? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिल्कुल शर्म नहीं आती, वह जनता को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं.

2014 में कुछ एफआईआर पुलिस ने दर्ज कीं. यह व्यापमं मामले का टर्निंग प्वाइंट था. एक एफआईआर 16 जुलाई, 2014 को शिवराज चौहान के क़रीबी डॉ. गुलाब सिंह किरार के ख़िलाफ़ मेरे द्वारा दर्ज कराई गई. उसके बाद मेरी स्थिति बद से बदतर होती गई, क्योंकि एफआईआर दर्ज करा दी गई, मैं व्हिसिल ब्लोअर था. ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा दबाव बनाया गया कि सिस्टम के दो खेमे हो गए. एक ओर जांच एजेंसी और दूसरी ओर पुलिस. जांच एजेंसी चाहती थी कि जांच हो, पुलिस चाहती थी कि आशीष ही न हो. जांच एजेंसी का कहना था कि जांच आगे बढ़े, पुलिस का कहना था कि हमने ठेका ले लिया कि तुम ही न रहो. इस तरीके का माहौल था. सुरक्षाकर्मी भी मारने की धमकी देते थे. सुरक्षाकर्मी खुलेआम बोलते थे कि मैं किसी दिन उनकी गोली से मरूंगा. नेताओं के रिश्तेदार मेरी सुरक्षा में लगा दिए गए. मैंने ये सारी बातें पुलिस अधिकारियों को बताईं. यह पता करना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि कौन पुलिसकर्मी किससे जुड़ा है. लेकिन, मुझे उन्हें बताना पड़ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यह फलां उसका रिश्तेदार है, यह रोज़ उन्हें ख़बर देता है कि मैं कहां जाता हूं, कैसे जाता हूं. आपने मेरे लिए ख़बरी रखा है या सुरक्षाकर्मी? यह सारी स्थिति होते-होते अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, तब सीबीआई को जांच दी गई. जब तक व्यापमं और डीमेट, दोनों मामलों की जांच सीबीआई से नहीं होगी, तब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक बात कहते हैं कि वह आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं. मुझे बचपन की, स्कूल के दिनों की एक बात याद आ जाती है. एक दिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जन-प्रतिनिधि क्या होता है. बताया गया, जन-प्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि. मैंने कहा, जनता का प्रतिनिधि मतलब? उत्तर मिला, तुम्हारा प्रतिनिधि, तुम्हारे जैसा, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला. आज मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रतिनिधि मानने से इंकार करता हूं, खारिज करता हूं. न मैं चोर हूं, न मैं धोखेबाज हूं, न मैं भ्रष्ट हूं. मेरा प्रतिनिधि मेरे जैसा होगा. शिवराज सिंह चौहान जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 21
दिल्ली, 27 जुलाई –02 अगस्त 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिलीप चेरियन

बाबुओं का पलायन

इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार में बाबुओं को पहले से ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उन पर काम का बोझ भी बढ़ गया है. अगर मोदी सरकार के अच्छे दिनों का किसी को खुशनुमा एहसास हुआ है, तो वे हैं दिल्ली के नौकरशाह. मोदी सरकार में सप्ताह के अंत में भी इन बाबुओं को घंटों काम करना पड़ता है. यहां तक कि वे शनिवार को भी काम करते नज़र आ जाएंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि पीएमओ को उनके कामों को लेकर कोई शिकायत हो. वजह, पीएमओ इन बाबुओं के कामों पर नज़र रखे हुए है. यह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों को अधिकार सौंपकर शक्तिशाली बना दिया है और वे मंत्रियों के बजाय इन बाबुओं से प्रत्यक्ष रूप से काम की प्रगति के बारे में बातें करना पसंद करते हैं. लेकिन, बाबुओं की परेशानी अब शुरू होने वाली है. सूत्रों के अनुसार, जबसे मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला है, बहुत सारे बाबू दिल्ली छोड़कर चले गए हैं. मई 2014 के बाद से लगभग 56 आईएएस अधिकारी समय से पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति छोड़कर अपने मूल कैडर चले गए हैं. कुछ अधिकारी मुख्य सचिव बनने चले गए हैं. कई अधिकारी नई कार्य-संस्कृति या शासन के कथित गुजरात मॉडल से बचने के लिए चले गए हैं. बाबुओं का इस तरह से पलायन मोदी सरकार के लिए चुनौती बन गया है. ■

सीसीएस अधिकारियों पर मेहरबानी

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों से केंद्र सरकार के खाली पद भरे जा रहे हैं. उक्त अधिकारी अब अपनी मान्यता और बेहतर पदोन्नति नीतियों पर जोर दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह एक गंभीर संकेत है, क्योंकि मोदी सरकार ने हाल में केंद्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक स्तर के 27 अधिकारियों को ऊपर उठाया है. सरकार की यह नीति सीएसएस के बाबुओं को यह निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है कि वे भिन्न सरकार से खुद के लिए बेहतर समझौता कर सकें. सूत्रों के अनुसार, सीएसएस अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह से मिलकर अपने लिए समयबद्ध पदोन्नति की मांग की, जो उनके करियर संबंधी ठहराव से जुड़ी है. दिल्ली में सीसीएस अधिकारियों की संख्या लगभग 12,000 है, इसलिए उनकी शिकायतों को सरकार लंबे समय तक नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती. ■

आईएफएस अधिकारी नाराज़

वर्षों की बहस के बाद सिविल सर्विस में लेटरल एंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय ने अंतत: योजना बनाई है कि वह विदेश मामलों के अकादमिक-विशेषज्ञों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त करेगा, ताकि वे सरकार की नीतियों एवं अनुसंधानों के बारे में जनता को बताएं. सर्वेक्षणकर्ताओं का कहना है कि यह क़दम बहुत ही महत्वपूर्ण है. हालांकि, आईएफएस लॉबी ने सरकार के इस फ़ैसले का विरोध किया है. सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह आईएफएस कैडर की क्षमता वर्तमान से दोगुनी करेगी, लेकिन विस्तार की योजना बहुत धीमी गति से चल रही है. यह सरकार के अन्य क़दमों की तरह एक नया क़दम है, जिसे भारतीय कूटनीति को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, संस्कृत के लिए 1996 बैच एवं ओडिसा कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद पधी को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करने जैसे क़दम को लोग बेतुका समझ रहे हैं. मंत्रालय सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को मिलाकर एक उम्दा टीम तैयार करना चाहता है, जिससे उसके प्रस्तावों का लोहा माना जाए. अन्य मंत्रालयों में लेटरल एंट्री की अवधारणा लागू करने के बाद अन्य सेवाओं में भी यही किया जा सकता है. ■

dilipcherian@gmail..com

मुझे एक अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों को यह समझाया गया कि जिस डेटा के लिए आप प्रशांत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वह डेटा कहीं और से निकल गया, तो आपके पास एक और समस्या बढ़ जाएगी. मुझे याद है कि भोपाल के पुलिस अधिकारी श्रीनिवास वर्मा ने कहा था कि प्रशांत, ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे. चालीस एफआईआर तो मैं रजिस्टर करूंगा. उन्होंने यह साफ़ कर दिया था कि किसी भी चीज के बारे में अगर तुमने जुबान खोली, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी. अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं डिप्रेशन में भी गया और मन में यह मान लिया था कि पूरा परिवार परेशान हो रहा है. वही आईएएस अधिकारी, जो जनसंपर्क अधिकारी भी थे राज्य सरकार के, उनके बारे में कुछ पत्रकारों ने बताया कि हमें प्रेस नोट के साथ एक लिफाफा भी दिया गया.

गोली इधर से जाएगी, उधर से निकल जाएगी

अभी व्यापमं से संबंधित जितनी भी चीजें लोगों के सामने हैं, वे बीस प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हैं. यह बात दावे के साथ बोल रहा हूं. मैं सिर्फ़ उतनी ही बातें बोलता हूं, जितनी पर मुझे मशीन के कहने पर यकीन होता है. मशीन झूठ नहीं बोलती, हर फाइल अपनी सच्चाई खुद बयां करती है. इस तरह की कहानियां चल रही हैं कि जो एक्सल शीट है, उसे वेरीफाई कराओ. मैं पहले दिन से जानता हूं कि वह सही है. मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. जिस हार्डडिस्क से इमेज क्रिएट हुई थी, मुझे शक है कि वह अब एग्जिस्सटेंस में नहीं है, क्योंकि जब मैंने चार्जशीट्स देखीं, तो उनमें हार्डडिस्क का सीरियल नंबर अलग था. मुझे नहीं मालूम कि यह केस कैसे और किस दिशा में जाएगा, क्योंकि पूरा टेक्निकल केस है. यह उन सुबूतों पर आधारित है, जो हार्डडिस्क से बरामद हुए थे, वे अब एग्जिस्ट नहीं करते.

प्रशांत पांडेय

सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक एक्सल शीट के बारे में जो बात बार-बार सामने आ रही है, उस डॉक्युमेंट या शीट से मेरा कोई कन्सर्न डायरेक्टली नहीं था. दरअसल, पुलिस के एक प्रतिनिधि मेरे पास एक केबल लेकर आए, जिसे वह कनेक्ट नहीं कर पाए थे. उन्होंने मुझसे कहा कि आप कनेक्ट करके बताइए. इनकम टैक्स में कई बार ऐसा होता था कि सर्चेज के दौरान सारी चीजें सेट करने का समय नहीं मिलता है, इसलिए मैंने अपने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा था. जिस पार्टी के यहां सीजर होता था, वहां इस एप्लीकेशन की वजह से उस पार्टी के कंप्यूटर की हार्डडिस्क अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते ही उसमें हार्डडिस्क की एक इमेज बन जाती थी. मेरे पास उस समय वही लैपटॉप उपलब्ध था. मैंने उसी पर कनेक्ट किया उस केबल को, उसकी इमेज मेरे कंप्यूटर में बन गई. मैंने केबल चेक करके बता दिया और कहा कि अब इसे ले जाइए. मैं उसे निकालने लगा. उन्होंने कहा कि यूएसबी या कोई भी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस को लगाया जाता है, तो सेफ रिमूवल का ऑप्शन आता है, आप सब इससे परिचित होंगे, क्योंकि सभी इससे मोबाइल कनेक्ट करते हैं. मैं उस ऑप्शन पर क्लिक किए बगैर उसे निकालने लगा, तो उन्होंने कहा कि बिना सेफ रिमूवल क्लिक किए इसे मत निकालिए. मैंने उन्हें बताया कि देखिए, एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा है, आप इसे बिना सेफ रिमूवल के ही निकाल सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि वह कोई रिस्क नहीं ले सकते. मैंने कहा कि इसमें समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी एक शादी में जाना है. वह इसे थोड़ी देर बाद ले लेंगे. तक़रीबन डेढ़ घंटे बाद वह हार्डडिस्क मुझसे ले गए. मुझे उसके तक़रीबन डेढ़ महीने तक यह सब कुछ नहीं पता था. न मैंने उस इमेज को टच किया, न उसे देखा. बहुत बाद में जब इनकम टैक्स का एक असाइनमेंट आया, तो मैंने उसे देखा. हार्डडिस्क ज़्यादा भरी हुई थी. इसका मतलब कि यह सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ था.

इसके क़रीब दो महीने बाद एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी ने मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा कि प्रशांत, क़रीब डेढ़ साल पहले हमने एक सर्च कंडक्ट की थी इनकम टैक्स की, जिसे वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम टैक्स सर्च कहा जाता है. दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा, जो माइनिंग बैरन हैं, उनके यहां. उस सर्च के दौरान बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीजें प्री सर्च एनालिसिस में निकलीं और पोस्ट सर्च एनालिसिस में भी निकलीं. अब चूंकि इनकम टैक्स को मतलब होता है सिर्फ़ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन से, इसलिए बाकी डेटा मैंने डंप कर दिया था. उस अधिकारी ने कहा कि उनके एक मित्र मध्य प्रदेश एसटीएफ में हैं और स्कैम से संबंधित साक्ष्य उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि ठीक है सर, मैं मिल लेता हूं उनसे जाकर. जब मैं उनके उक्त मित्र से मिला, तो उन्होंने खुद बताया कि हमने जबलपुर हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है. कांग्रेस की किसी पिटीशन के जवाब में उन्होंने यह एफिडेविट फाइल किया था. उसमें यह बात थी कि हमारे पास सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा के ख़िलाफ़ कोई सुबूत नहीं हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार करें.

मुझे लगा कि वह एक ईमानदार आदमी हैं. उनका खुद का कोई परिवार भी नहीं है. अगर वह सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए. मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, जिसमें बहुत सारा डेटा था. एक छोटी-सी एक्सल शीट तो प्वाइंट वन परसेंट भी नहीं होगी उसकी. जो इंफॉर्मेशन मैंने दी, उसके आधार पर उन्हें यह तो समझ में आ गया कि कौन-कौन इसमें मिला हुआ है. जो इंफॉर्मेशन मैंने डंप कर दी थी एक साल पहले, वह यहां के लिए बहुत यूजफुल थी, क्योंकि उसमें रोल नंबर थे, एडमिशन, टेक्स्ट मैसेजेस थे, उनके मोबाइल का पूरा डेटा था, कम्युनिकेशन और कॉल रिकॉर्ड का डेटा था. कुल मिलाकर यह एक बड़ा सुबूत था. और मैंने उस समय तक उन्हें सिर्फ़ 40 प्रतिशत डेटा दिया होगा. मैं सिर्फ़ यह देखना चाहता था कि वह उस पर एक्शन क्या लेते हैं. मैंने पाया कि उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा और सुधीर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. डॉ. विनोद भंडारी की गिरफ्तारी की बात आई, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, कई क़दम उठाए. मुझे लगा कि वह सही दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं.

लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के बाद मुझे लगा कि अभी जो और सुबूत मेरे पास हैं, उनके हिसाब से मामले में और भी लोग मिले हुए हैं. मैंने कुछ महीनों तक इंतजार किया और पाया कि शायद कुछ सुबूत उस अधिकारी ने मिस कर दिए हैं. मैंने उनसे पूछा कि सर, आप इसे क्यों नहीं एडमिट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रशांत, सोर्स निश्चित नहीं है और अदालत इसके बारे में पूछेगी. मैंने कहा कि सोर्स आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से ले लीजिए, उसके पास पूरा डेटा है. उन्होंने कहा कि कोशिश करके देखते हैं. उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को खत लिखे, जिनके जवाब में मंत्रालय ने मना कर दिया कि हम वह डेटा दे पाने में सक्षम नहीं हैं. फिर मैंने दिल्ली में एक आदमी से बात की. मैंने उस अधिकारी से कहा कि सर, आप एक खाली हार्डडिस्क भेजिए और कहिए कि अधिकतम आप जो भेज सकते हैं, वह भेज दीजिए. नो मैटर कि वह काम का है या नहीं. उन्होंने कहा कि इससे क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा कि आप मंगाइए तो सही, हम आधिकारिक सूत्र पा जाएंगे. उन्होंने हार्डडिस्क भेजी, जो ऑन रिकॉर्ड आई है.

हो सकता है कि यह प्रोसेस ग़लत हो या अनफेयर बाई एनी मीन्स, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तथ्य सही हैं और सुबूत भी हैं, तो एक ग़लत आदमी को पकड़वाने के लिए इस तरह के छोटे-मोटे एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंफॉरमेशन करेक्ट थी, उसमें एक भी झूठ या एडिटेड डॉक्युमेंट नहीं था. मैंने उस हार्डडिस्क में जो एडिट डेटा आया था, उसमें 40 प्रतिशत में दस प्रतिशत और जोड़कर क्लब किया और उनसे कहा कि सर, अब तो यह ऑफिशियल है. अब इसे ऑन रिकॉर्ड रख सकते हैं. कौन पूछेगा कि आपके पास कहां से आया? जब मैंने पहली चार्जशीट देखी, तो मुझे आश्चर्य हुआ. उसमें सत्तर प्रतिशत चीजें नहीं थीं. हालांकि, मुझे बहुत विश्वास था कि शायद उनका कोई और तरीका होगा, उसे वह किसी दूसरे रास्ते से पूरा करेंगे. इसी दौरान कांग्रेस के एक नेता ने कुछ जानकारियां रिलीज कीं, जिनका शक मुझ पर आया और पूरा सेनेरियो हुआ. उसी समय एक ग़लती मुझसे यह हुई कि एसपी इंटेलिजेंस भोपाल मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि प्रशांत, मुझे यह पता करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि इंफॉरमेशन किसने लीक की.

उन्होंने कहा कि सारे लोगों को शक है कि तुमने यह डेटा लीक किया है. पहले मैंने क्लीयर करना चाहा कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है. आप मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. इसके बावजूद मैंने उन्हें अच्छी तरह कनविंस किया. मैंने उन्हें वे डॉक्युमेट्स दिखाए, जो ओरिजनल थे. तब तक मैंने उस इमेज को भी रिकवर कर लिया था. ओरिजनल शीट भी दिखाई मैंने उन्हें. वह आश्चर्यचकित हुए और कनविंस होकर चले गए. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई मेरे ऊपर. उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी मुझे जमानत मिल पाएगी. सौभाग्य से एक एसटीएफ अधिकारी कोर्ट में थे और उन्होंने स्वीकार किया कि मैं उनके साथ काम कर रहा था. उनके यह कहने के बाद ही मुझे जमानत मिली. जमानत के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, तो वह भी मेरे घर पहुंच गए. मैंने सुप्रीम कोर्ट में उनके वाट्सअप के कम्युनिकेशन भी लगाए हैं, जिनमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे. कुछ आईएएस अधिकारियों के शब्द थे, गोली इधर से जाएगी और उधर से निकल जाएगी. जितना दिमाग में है न, सब चला जाएगा.

मुझे एक अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों को यह समझाया गया कि जिस डेटा के लिए आप प्रशांत को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वह डेटा कहीं और से निकल गया, तो आपके पास एक और समस्या बढ़ जाएगी. मुझे याद है कि भोपाल के पुलिस अधिकारी श्रीनिवास वर्मा ने कहा था कि प्रशांत, ज़िंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाओगे. चालीस एफआईआर तो मैं रजिस्टर करूंगा. उन्होंने यह साफ़ कर दिया था कि किसी भी चीज के बारे में अगर तुमने जुबान खोली, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी. अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं डिप्रेशन में चला गया और मन में यह मान लिया था कि पूरा परिवार परेशान हो रहा है. वही आईएएस अधिकारी, जो जनसंपर्क अधिकारी भी थे राज्य सरकार के, उनके बारे में कुछ पत्रकारों ने बताया कि हमें प्रेस नोट के साथ एक लिफाफा भी दिया गया. मेरी सोशल इमेज खराब करने की कोशिश की गई. मेरा दावा है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि प्रशांत ने कभी किसी इंफॉरमेशन का मिस यूज किया. मैंने पचासों मामलों में बहुत-सी एजेंसियों के साथ काम किया है, लेकिन आज तक किसी का कोई डेटा लीक नहीं किया.

यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा इतनी मदद करने के बावजूद मैंने कभी कोई डेटा उन्हें नहीं दिया. मैं उस डेटा को लेकर बहुत दबाव महसूस करता था. मैंने कपिल सिब्बल से कहा कि सर, मैं यह डेटा कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि कोर्ट ही सही जगह है. फाइनली वह डेटा मैंने कोर्ट में जमा किया. उसमें से कुछ इंफॉरमेशन लीक हो गई. आनंद को अच्छी तरह जानता हूं, मैंने ही उनका कॉल और मेल का रिकॉर्ड निकाल कर एसटीएफ के अधिकारियों को दिया. उन्हें लगता था कि यह लड़का बहुत परेशान कर रहा है, हर बात में कुछ न कुछ लेकर आ जाता है. वे चाहते थे कि कोई ऐसा प्वाइंट मिल जाए कि इसके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर हो जाए. उस दौरान दिग्विजय सिंह ने मेरा सपोर्ट किया और यह सब कुछ बिना किसी एग्रीमेंट के हुआ. उन्होंने कहा कि प्रशांत, तुम जो कुछ कर रहे हो, अगर वह सही है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं. उसके बाद विवेक तनखा सर को यही लगा. मैं निर्णय ले चुका था कि किसी राजनीतिक पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रखना है. खुशकिस्मती से एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात विवेक सर से हुई. उन्होंने मुझे अपने होटल में बुलाया और हम लोग क़रीब पांच घंटे तक चर्चा करते रहे. फिर मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं. उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह से संपर्क साधा.

अभी व्यापमं से संबंधित जितनी भी चीजें लोगों के सामने हैं, वे बीस प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हैं. यह बात मैं दावे के साथ बोल रहा हूं. मैं सिर्फ़ उतनी ही बातें बोलता हूं, जितनी पर मुझे मशीन के कहने पर यकीन होता है. मशीन झूठ नहीं बोलती, हर फाइल अपनी सच्चाई खुद बयां करती है. इस तरह की कहानियां चल रही हैं कि जो एक्सल शीट है, उसे वेरीफाई कराओ. मैं पहले दिन से जानता हूं कि वह सही है. मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. जिस हार्डडिस्क से इमेज क्रिएट हुई थी, मुझे शक है कि वह अब एग्जिस्सटेंस में नहीं है, क्योंकि जब मैंने चार्जशीट्स देखीं, तो उनमें हार्डडिस्क का सीरियल नंबर अलग था. मुझे नहीं मालूम कि यह केस कैसे और किस दिशा में जाएगा, क्योंकि पूरा टेक्निकल केस है. यह उन सुबूतों पर आधारित है, जो हार्डडिस्क से बरामद हुए थे, वे अब एग्जिस्ट नहीं करते. एकाध आदमी पर भी आरोप सिद्ध हो जाए और सजा मिल जाए, तो बड़ी बात है. इसलिए सीबीई जांच की डिमांड थी.

जो दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे उन लोगों के रिकॉर्ड्स, मेल्स, जो दूसरी जगह अटेस्टेड डेटा इमेजेस होती हैं, वहां से रिकवर करके कोई एजेंसी उन्हें प्रोड्यूस करे और सही तरह से प्रेजेंट करें, तो संभव है कि एक्चुअल लोग जो इन्वॉल्व हैं, उन सबको सजा हो पाए. लेकिन, इसमें बहुत समय लगेगा. मेरा मानना है कि सीबीआई अगर ठीक से काम करे, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है. पर मुझे वह सब डेटा सीबीआई को सौंपने में हर्ष होगा, जो मेरे पास है. सीबीआई उसकी जांच कर ले, उसका जो भी पैमाना हो, तरीका हो, उसकी सत्यता जांच ले और उसे प्रॉसेस करे. कम से कम जो लोग इसमें शामिल हैं, जो परदे के पीछे हैं, उन सभी के नाम सामने आएं. टीएस तुलसी सर का सुबूतों को लेकर एक प्वाइंट है. वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने समझा कि मैं क्या कहना चाह रहा था. विवेक सर ने मुझे मैसेज भेजा कि प्रशांत, यह प्वाइंट बिल्कुल सही है कि जो इनकी कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं, वे सारी जेल जाने लायक हैं और इसके लिए हमारे पास पुख्ता सुबूत हैं.

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस हैं कि जब कभी किसी डिजिटल एविडेंस को आप उठाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यह किसी हार्डवेयर को सीज करने जैसा नहीं है. यह सॉफ्टवेयर डेटा है, जिसे आप नहीं देख सकते, जिसे आप फिजिकली छूकर महसूस नहीं कर सकते. उस चीज को सीज किया जाता है. उसका एक तरीका है. सीज करने के दौरान उसकी हैश वैल्यू क्रिएट की जाती है, ताकि उन दस्तावेज़ों के साथ टेंपरिंग (छेड़छाड़) की सारी आशंकाएं ख़त्म हो जाएं. हैश वैल्यू क्रिएट करने के बाद एक डिजिटल डेटा के साथ छेड़छाड़ का कोई विकल्प बाकी नहीं बचता. लेकिन इन लोगों ने, हैश वैल्यू तो दूर की बात, हार्डडिस्क का सीरियल नंबर तक बदल रखा है. इस वजह से आगे बढ़ने में हमारे सामने बहुत-सी मुश्किलें पेश आएंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

दस साल में पूरी शिक्षा बिक गई

अजय दुबे

साल 2008-09 से सूचना के अधिकार के तहत कई लोग हमसे मिलते थे कि भाई, परीक्षा में हमारा चयन नहीं हुआ, आंसर सीट के लिए आरटीआई लगानी है. गाहे-बगाहे हम लोग व्यापमं के दरवाजे तक जाते थे और उसका भवन देखते थे. भवन में बड़ी-बड़ी गाड़ियां आती थीं और जिस तरह का माहौल देखने को मिलता था, वह समझ से परे था, लेकिन तो भी हमने कहा कि व्यापमं में आना-जाना चलता होगा. सूचना के अधिकार के संबंध में हम लोगों की मदद करते थे कि कैसे वे आरटीआई फाइल करें और आरटीआई के माध्यम से मिले डॉक्युमेंट्स से वे कोर्ट भी जाते थे. मैं यहां व्यापमं स्पेशिफिक यानी इस संस्था पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि व्यापमं को हम लोग बहुत गंभीरता से वॉच कर रहे थे कि इसमें आख़िर ऐसा है क्या कि यह पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में एक नेटवर्क स्थापित करके काम कर रही है. व्यापमं का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका जो हेड होता है, वह चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है. लेकिन इस घोटाले में जो पकड़ा गया है, जिसका पूरा दिमाग है, वह क्लास थ्री का कर्मचारी है. रॉबिन हुड कहलाता था नितिन महिंद्रा. क्यों? व्यापमं में जो खर्चे होते थे, उनकी ऑडिट हमने देखी. 2005-06 के दौरान वहां पर तिजोरी में सत्तर लाख रुपये पड़े रहते थे. लोकल फंड ऑडिटर ने कहा स्ट्रांग रूम में इतना पैसा क्यों रहता है? वहां के एकाउंट में यह डिटेल स्टेटस कभी रहता ही नहीं था कि व्यापमं में कितनी ओएमआर सीट छपकर आई हैं और कहां जा रही हैं? ओएमआर सीट, जो एप्लिकेंट्स के पास परीक्षा केंद्र में जाती है, उसका डेटा होना चाहिए. ओएमआर सीट का जो ऑर्डर लेता था, वह वहां का एक बड़ा नेता है. 2003 में जैसे ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, हिंदी के जो अच्छे शब्द थे जैसे राष्ट्रवाद, अखंड भारत एवं शिक्षा आदि का इस्तेमाल शुरू हुआ. इस अपराध में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो वर्तमान सत्ताधारी नेता के शिक्षा समूह के अध्यक्ष थे. तो ऐसे लोग लगे थे राष्ट्र निर्माण में!

बाहर की ताकतों से, दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक हमारे नकली पुलिसकर्मी, नकली डॉक्टर, नकली टीचर हैं. मतलब जो सही हैं, उनका भी नुक़सान हो गया. जो ग़लत हैं, वे तीस साल तक हैं. वे तीस साल तक इस देश की कितनी नस्लों को बर्बाद करेंगे, मुझे नहीं पता. बोर्ड मैनेजमेंट व्यापमं का एक बहुत बड़ा बोर्ड है. उसमें कई विभागों के सचिव हैं. उन्होंने निर्णय लिया कि हम सेंट्रल ऑब्जर्वर्स रखेंगे, जैसा कि लोकसभा चुनाव में होता है. ऑब्जर्वर रखे गए. रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सबको रखा गया. 2010 से उन्हें बहुत बड़ा पेमेंट भी होता था. ये लोग बाकायदा प्रश्नपत्र सेलेक्ट होने से लेकर आंसर सीट कलेक्शन होने तक, ओएमआर सीट तक ऑब्जर्वेशन करते थे. सीसीटीवी फुटेज थे. स्ट्रांग रूम में भी ऑब्जर्वेशन होता था. लेकिन, उसके बाद फिर वही बात हुई. क्लास थ्री के अधिकारी ने सब गोले लगा दिए, पास-फेल करा दिया.

व्हिसिल ब्लोअर आज मुख्यमंत्री हैं. कैसे व्हिसिल ब्लोअर? आपको पता नहीं था कि दस साल में पूरी शिक्षा बिक गई, नौकरी बिक गई? अपर स्कूल बोर्ड का घोटाला, व्यापमं घोटाला, पीएसी घोटाला, संस्कृत घोटाला. संस्कृत बोर्ड में दस-दस हज़ार रुपये में मार्कशीट बांटी गईं. सीनियर लीडर मिले प्रधानमंत्री जी से, जो पेनड्राइव और सब दिया. हमने आरटीआई में पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? वहां से जवाब आया, जो आपके आरटीआई प्रश्न हैं, उनसे प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सोर्सेस हैं, वे डायवर्ट हो जाएंगे और उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया. मध्य प्रदेश में जो व्यापमं की जांच एसआईटी से कराई गई या उसे हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया, यह सब जनहित याचिकाओं का आउटकम था. जबलपुर में हम केवल सरकार के ही विक्टिम नहीं हैं, जबलपुर में न्यायपालिका ने भी अच्छे से हमारी सुनवाई नहीं की. आगे जनहित याचिका की सुनवाई चल रही थी, पीछे हाईकोर्ट से एक लेटर जाता है सरकार को कि एक ऐसा क़ानून बनाओ कि जनहित याचिकाओं को

कंट्रोलर और डायरेक्टर पद एक ही व्यक्ति देखता था पंकज त्रिवेदी. उसे रैना चौधरी जी के समय आईएएस बनाने की बात चली. यह सब कैसे हुआ? इतना सफल व्यक्ति, जिसे शिवराज जी आईएएस बनाना चाह रहे थे, उसके रहते यह सब कैसे हुआ? यह सब चीजें एसआईटी को दी गईं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की लिस्ट दी गई. सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को जो नियुक्ति-पत्र मिलता था, उसमें एक लाइन लिखी थी कि आप जो परीक्षा है, उसे सफल होने का प्रमाण-पत्र देंगे. इतने सफल प्रमाण-पत्र दिए कि 13 परीक्षाओं में 55 एफआईआर हो गईं.

कंट्रोल कर लो. अरे, आप जनता और सरकार दोनों के बीच में हो और आप कैसे यह सलाह दे रहे हो सरकार को? उस बिल का नाम रखा, मध्य प्रदेश: तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक-2015. हमने उसे जलाया, हम पर पचास हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ.

बीती नौ जुलाई मध्य प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए बहुत बड़ा उजाला लेकर आई. सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, उसके दो दिन पहले तनखा साहब ने चीफ जस्टिस को व्यापमं पर बात बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दो दिन बाद सुन लेते हैं. उसी समय सीएम, जो व्हिसिल ब्लोअर थे, एक दिन पहले कह रहे थे कि सीबीआई इन्क्वायरी डिक्लेयर करना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, बिल्कुल नहीं करेंगे. दो दिन पहले जो मना कर रहे थे, वह दो दिन बाद इस मुद्दे पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की प्रोसिडिंग पता चली, कहते हैं कि सीबीआई जांच कराएंगे. क्या मज़ाक था? कल तक उल्लंघन था, आज सही हो गया.

स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम के हेड हैं जस्टिस चंद्रेश भूषण. वह हाईकोर्ट की तरफ़ से मॉनीटरिंग कर रहे थे. 2006 में डीमेट घोटाले की जांच वह पहले ही कर चुके हैं. 2006 में ऐसी जांच की कि आज तक घोटाला ही चल रहा है. 2006

में अच्छी जांच करने के फलस्वरूप जस्टिस चंद्रेश भूषण को 2008 में मध्य प्रदेश का उप-लोकायुक्त बनाया गया. फिर 2014 में उन्हें व्यापमं की मॉनीटरिंग दे दी गई. इतना अच्छा-अच्छा काम करते हैं, तो हमने कहा कि चलो पता किया जाए. पता चला कि वह सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें फैमिली पेंशन दी जाए. हाईकोर्ट के जज को फैमिली पेंशन मिलती है. वह चाहते हैं कि उप-लोकायुक्त की पेंशन भी उन्हें फैमिली पेंशन के तौर पर मिले. फिर कुछ पैसे की बात थी. हमने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति सरकार से ये सब चीजें मांग रहा है, वही सरकार के साथ बैठक कर रहा है, वही लोकायुक्त के साथ बैठक करा रहा है और वही मॉनीटरिंग भी कर रहा है. यह कैसी फेयर मॉनीटरिंग है? हाईकोर्ट ने कहा था कि मॉनीटरिंग में फेयरनेस होना चाहिए. कैसी फेयर मॉनीटरिंग? सरकार के साथ लेन-देन चल रहा है और व्यापमं की मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं!

कंट्रोलर और डायरेक्टर पद एक ही व्यक्ति देखता था पंकज त्रिवेदी. उसे रैना चौधरी जी के समय आईएएस बनाने की बात चली. यह सब कैसे हुआ? इतना सफल व्यक्ति, जिसे शिवराज जी आईएएस बनाना चाह रहे थे, उसके रहते यह सब कैसे हुआ? यह सब चीजें एसआईटी को दी गईं, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की लिस्ट दी गई. सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को जो नियुक्ति-पत्र मिलता था, उसमें एक लाइन लिखी थी कि आप जो परीक्षा है, उसे सफल होने का प्रमाण-पत्र देंगे. इतने सफल प्रमाण-पत्र दिए कि 13 परीक्षाओं में 55 एफआईआर हो गईं. फिर भी जवाबदेही तय नहीं हुई. लोकतंत्र जवाबदेही से ही चलता है. सूचना के अधिकार से बहुतों की आंसर सीट पर जो लड़ाई चलती रही, उससे इतने रहस्य खुलते गए कि यह पता चला कि इन अपराधियों को बैंकों ने भी ब्लैकमेल कर लिया. व्यापमं में एक बड़ा अजीबोग़रीब अपराध होता था. 2007 में ऑनलाइन सबमिशन हुआ फॉर्म का. उसके पहले बैंकों से फॉर्म बिकते थे. व्यापमं में अपराध इस तरह होता था कि जो फॉर्म बेचे गए, उनके पैसे व्यापमं को नहीं मिलते थे. जो बच्चे अपीयर हुए, उसकी फीस व्यापमं को दी जाती थी. बैंकों ने आज भी सात करोड़ रुपये व्यापमं के दबा रखे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि व्यापमं के लोगों का जो रैकेट है इतना बड़ा, वह खुद इंट्रेस्टेड नहीं है कि पैसे वापस लिए जाएं.

रॉबिन हुड साहब पूरे व्यापमं के कर्मचारियों की शादी कराते थे. यह पूरा नेटवर्क कैसे पूरा हो सकता था चेयरमैन के बिना? इसके अलावा जो सबसे गंभीर बात देखने में आई, वह यह कि बिट्स पिलानी ने 2005 से ऑनलाइन एक्जाम कराना शुरू कर दिया था. उस समय एमके रॉय साहब चेयरमैन थे. उन्होंने कहा कि जाकर स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम लोग भी शुरू करते हैं. व्यापमं का ऑनलाइन एक्जाम कराने के लिए सीएम सचिवालय को लेटर भेजे गए. उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई. 2010 में रैना चौधरी ने सीएम को फिर लेटर लिखा. यदि उस वक्त ऑनलाइन इक्जाम कराने का निर्णय ले लिया जाता तो प्रदेश में मुन्नाभाई बनने का सिलसिला रुक सकता था. अब निवेश कहां से होगा मध्य प्रदेश में? क्या इन्हीं 47 अकाल मौतों से प्रभावित होकर कोई निवेश करने आएगा? यही हम लोगों का दर्द था. मैं मध्य प्रदेश फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं कि उसने उजाले की किरण दिखाई है. इससे मध्य प्रदेश की अच्छी छवि दिल्ली और बाहर बनेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

शिवराज दूध के धुले नहीं हैं

डॉ. आनंद राय

पीएमटी में मेरा चयन चार प्रयासों में हुआ. मैं शुरू से मेरिटोरियस रहा. पांचवीं, आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं में मेरिट में आया. मुझे लगा कि ऐसा क्या है कि मैं पीएमटी फेस नहीं कर पा रहा हूं? पीएमटी में मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बाद में पता चला कि 2005 में एमडी एमएस एंट्रेंस में जो टॉप 10 थे, वे दस के दस फर्जी थे. मैंने एसटीएफ से शिकायत की, आज तक उनमें से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ. 2009 में जब मुझे जानकारी हुई कि पीएमटी का पेपर आउट होने वाला है, तो मैंने उसकी जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को दी. केस दर्ज हुआ, लेकिन उसमें लिखा गया कि एक गेस पेपर पकड़ा गया है. ऐसा करके उस केस को डायल्यूट कर दिया गया. मैंने हिम्मत नहीं हारी और 15 जुलाई, 2009 को मैंने फिर से शिकायत की कि किस तरह यूपी, बिहार एवं राजस्थान के लोग आते हैं और धांधली के ज़रिये सेलेक्ट होते हैं. 2010 में कई आरटीआई लगाई कि जो कमेटी गठित की गई है मेरी शिकायत के आधार पर, उसने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया? पता चला कि शिवराज सरकार ने उसमें न तो कोई रुचि ली और न उसका कोई रुचि लेने का इरादा था, क्योंकि वह पहले ही भांप चुकी थी कि इसके माध्यम से कोई बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है.

हमने कुछ ईमानदार विधायकों से संपर्क किया, उनमें कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल, पारस सकलेचा प्रमुख थे. उनके माध्यम से हमने क़रीब 12 सवाल विधानसभा में लगाए और पता करने की कोशिश की कि जो कमेटी बनी थी, उसने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया. शिवराज सिंह चौहान तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे और क़रीब नौ महीने बाद उन्होंने यह माना कि 2009 बैच में 114 अभ्यर्थी ग़लत तरीके से सेलेक्ट हुए हैं. हम लोग बराबर पूछते रहे कि आपने उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? मार्च 2013 में उन्होंने बताया कि ऐसे कुल मिलाकर 300 मामले थे और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर की अनुशंसा की गई. आप यह देखिए कि एक अभ्यर्थी जो 2009 में ग़लत तरीका अपना कर सेलेक्ट हुआ, वह मुन्ना भाई फाइनल तक पहुंच गया और तब तक उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.

साल 2013 में दोबारा हमें जानकारी हुई कि कुछ सॉल्वर्स होटलों में रुके हुए हैं. इंदौर पुलिस को हमने यह जानकारी दी. हमारी जानकारी पर इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसका श्रेय शिवराज सिंह ले रहे हैं कि उसके व्हिसिल ब्लोअर वह हैं. चार-पांच दिनों तक मीडिया में बहुत कवरेज हुआ. जब जगदीश सागर का नाम सामने आया, तो 13 जुलाई को मेरे पास उनका फोन आया कि तुम्हारे कारण बहुत मीडिया कवरेज हो रहा है, इसे बंद कर दो, नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे. क़रीब आधा घंटे तक मैं सोचता रहा कि इसका नंबर पुलिस को दूं या न दूं. पुलिस पर मुझे विश्वास

नहीं था. जिस तरह से इतने दिनों से हम लगे थे, हमारा विश्वास उठ गया था, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी कि चलो, यह नंबर पुलिस को दिया जाए और उसकी टॉवर लोकेशन से वह अरेस्ट हुआ. और, उसी के बाद से नितिन महिंद्रा, एक्सल शीट और सारी चीजें आती गईं.

हम देखते रहे कि किस तरह से रसूखदारों को बचाया जा रहा है. हम हाईकोर्ट गए और हमने मांग की कि यह परीक्षा फिर से कराई जाए. अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि एक भी अभ्यर्थी ग़लत तरीके से सेलेक्ट होता है, तो उस परीक्षा की प्रामाणिकता (सैंक्टिटी) पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है. एक क्या, यहां पहले दिन से पता था कि क़रीब 350 लोग फर्जी हैं. उसके बावजूद सुशासन का दावा करने वाले शिवराज सिंह ने परीक्षा फिर से कराने के लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया, जबकि सात से ज़्यादा पीआईएल हम लोगों ने दायर कराई थीं और मांग की थी कि जांच एसटीएफ से कराई जाए या फिर सीबीआई जांच कराई जाए. उसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि ठीक है, हम एसटीएफ से जांच कराने के लिए तैयार हैं, न कि कोई स्वत: प्रेरणा से एसटीएफ जांच के ऑर्डर उन्होंने किए.

उसके बाद जिस तरीके से बड़े-बड़े लोगों के नाम सामने आते गए और हम देखते गए कि किस तरह से अभ्यर्थियों को तो जेल में ठूंस दिया गया, जो उस पिरामिड में सबसे नीचे थे. लेकिन, बड़े लोग बचे रहे. हम हाईकोर्ट गए. निजी मेडिकल कॉलेजों के मालिक पूरे घोटाले के हिस्से थे, उन्हें पूरी तरह से बख्श दिया गया. सिर्फ़ एक कॉलेज के मालिक को बलि का बकरा बना दिया गया. मैंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. मेरी याचिका के बाद एएफआरसी को नोटिस जारी हुए और एएफआरसी ने मेरी एक सिंगल कंप्लेंट पर निजी मेडिकल कॉलेजों पर 13.5 करोड़ रुपये का अर्थदंड (फाइन) लगाया. उसके बाद भी आज तक उन निजी कॉलेजों के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर शिवराज सरकार ने दर्ज नहीं कराई. कहीं न कहीं सुरक्षा का ख़तरा था, इसलिए सुरक्षा के लिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस के पास गया. मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा, तुम्हें किस बात का ख़तरा? तुमने व्यापमं के लिए क्या किया? जितनी जानकारी मैंने पुलिस को दी, वह सब उसने नकार दी.

हर जगह जब भी कोई व्हिसिल ब्लोअर जानकारी देता है, तो उसके साथ यही होता है. अंग्रेजों के समय का एक शब्द चल रहा है, मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि उस शब्द को शब्दावली से निकलवाइए, जिसे मुखबिर कहते हैं. मुखबिर एक बहुत निगेटिव वर्ड है. जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, तो हर जगह लिखा था कि मुखबिर की सूचना पर. सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा. हाईकोर्ट ने मुझे सुरक्षा दी. फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, इसलिए कि सीबीआई जांच हो. हमें लग रहा था कि उनका जो दायरा है, उस लिहाज से वे पुलिस के नेटवर्क से बाहर हैं, वे बहुत ताकतवर लोग हैं, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हैं और यह बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रक्सौल विधानसभा क्षेत्र

पहले सवालों से वार, फिर वोटों की बौछार

सुरेश यादव

रामबाबू यादव

प्रमोद सिन्हा

प्रमोद राय

कपिलदेव प्रसाद

अब्दुल हाफिज अंसारी

रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता राजनीतिक दृष्टि से उदासीन रही है. यहां जो भी राजनीतिक धारा बन जाती है, लम्बे समय तक चलती रहती है. यही कारण है कि 1977 से 1990 तक कांग्रेस के सगीर अहमद रक्सौल के विधायक रहे. 1990 से 2000 तक जनता दल के राजनन्दन राय ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 2000 के चुनाव में भाजपा के डॉ अजय कुमार सिंह जीते. तब से श्री सिंह रक्सौल के विधायक हैं. क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से आम लोग परेशान हैं.

राकेश कुमार/अनुज

भारत-नेपाल का सीमाई शहर रक्सौल कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है. रक्सौल को गेटवे ऑफ नेपाल भी कहा जाता है. भारत-नेपाल की खुली सीमा के कारण रक्सौल तस्करी और मानव व्यापार के लिए बदनाम रहा है. सीमाई शहर रक्सौल की जमीन मूल्यवान है. यहां जमीन का मूल्यांकन कट्ठा और बीघा में नहीं, बल्कि फीट में होता है. नेपाली नागरिकों सहित विदेशी पर्यटकों का यहां आना-जाना रहता है, लेकिन इस महत्वपूर्ण शहर की पहचान है जाम, गंदगी, जल जमाव, टूटी सड़कें, अतिक्रमण जैसी समस्याओं से. 2008 में रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन के बाद आकार बदल गया. आदापुर प्रखण्ड के 16 पंचायत और रक्सौल प्रखण्ड के 13 पंचायतों को मिलाकर 29 पंचायतों का रक्सौल विधानसभा क्षेत्र बना. रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 4,64,296 है. वोटरों की संख्या 2,51,560 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,37,015 तथा महिला वोटरों की संख्या 1,14,535 है.

रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता राजनीतिक दृष्टि से उदासीन रही है. यहां जो भी राजनीतिक धारा बन जाती है, लम्बे समय तक चलती रहती है. यही कारण है कि 1977 से 1990 तक कांग्रेस के सगीर अहमद रक्सौल के विधायक रहे. 1990 से 2000 तक जनता दल के राजनन्दन राय ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 2000 के चुनाव में भाजपा के डॉ अजय कुमार सिंह जीते. तब से श्री सिंह रक्सौल के विधायक हैं. क्षेत्र की वर्तमान स्थिति से आम लोग परेशान हैं. यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के दावेदारों के साथ 2015 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की भीड़ होने की संभावना जतायी जा रही है. भाजपा के वर्तमान विधायक अजय कुमार सिंह 15 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. सिटिंग-गेटिंग के तहत इनको भाजपा का टिकट मिलना तय बताया जा रहा है, जबकि महागठबंधन के घटक दल जदयू, राजद, कांग्रेस के कई दावेदार चुनावी समर में उतरने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं. वहीं नरकटिया के जदयू विधायक श्याम बिहारी प्रसाद के चुनाव क्षेत्र बदलने की भी चर्चा जोरों पर है. राजनीतिक धुरंधरों की मानें तो श्याम बिहारी प्रसाद को रक्सौल से चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके पीछे कारण यह है कि यहां जदयू के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है और जो चेहरे हैं भी तो उनका स्थानीय लोगों में मजबूत पकड़ नहीं बताई जाती है. वहीं लम्बे समय से श्याम बिहारी प्रसाद आदापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 का चुनाव आदापुर से जीते. वहीं 2010 के चुनाव में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की. जानकारों की मानें तो क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता में कमी आई है. 2008 में नये परिसिमन के बाद 13 आदापुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और इसका नाम 12 नरकटिया विधानसभा पड़ा. इधर दो सत्र जिला जदयू के अध्यक्ष रहे प्रमोद कुमार सिन्हा भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों की मानें तो क्षेत्र में चुनावी तैयारी करने के लिए ही इन्हें जिलाध्यक्ष के पद से विगत माह हटाकर इनके स्थान पर प्रो. दिनेश चन्द्र प्रसाद को जिलाध्यक्ष का भार सौंपा गया है. हालांकि जिलाध्यक्ष रहते हुए भी श्री सिन्हा का ज्यादा समय रक्सौल में ही बीतता था, जिसके कारण जदयू कार्यकर्ताओं ने नाराजगी के स्वर भी उठाए. श्री सिन्हा पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी में हैं. आर्थिक रूप से मजबूत हैं.

कपिलदेव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल भी चुनावी समर में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं. वर्तमान में श्री प्रसाद भेलाही पंचायत के मुखिया हैं. वे दूसरी बार मुखिया चुने गये हैं. श्री प्रसाद को चुनाव लड़ने का तर्जुबा भी है. 2005 फरवरी के चुनाव में श्री प्रसाद चुनाव लड़ थे. तब इन्होंने लोजपा के टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला और वे निर्दलीय चुनाव लड़े. कपिलदेव प्रसाद जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं. श्री प्रसाद को वैश्य मतों के साथ अन्य जातियों में मजबूत पकड़ का भरोसा है, जो इनकी चुनावी बैतरणी पार करा सकती है.महागठबंधन के घटक दल राजद से भी कई उम्मीदवार आसन्न विधानसभा चुनाव में जोर आजमाना चाहते हैं. इनमें से राजद के जिला उपाध्यक्ष सुरेश यादव एक हैं. श्री यादव रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और दूसरी बार रामगढ़वा कौडियार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चुने गये हैं. श्री यादव का मानना है कि रक्सौल सीट राजद का है. वे आश्वस्त हैं कि राजद से इन्हीं को टिकट मिलेगा. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें चुनावी तैयारी करने को कहा है. बकौल सुरेश यादव इस बार जनता परिवर्तन चाहती है. क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है. रक्सौल में एक भी खेल मैदान नहीं है. मिशनरी अस्पताल डंकन के अतिरिक्त कोई सरकारी अस्पताल भी नहीं है. रक्सौल में जाम की विकराल समस्या है. यहां भाजपा के ही सांसद डॉ संजय जायसवाल और विधायक अजय सिंह लम्बे समय से हैं, लेकिन एक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करा सके. फ्लाईओवर बन जाने से जाम की समस्या का निदान हो जाता. श्री यादव के अनुसार पूरा यादव समाज उनके साथ है. माई समीकरण का मुसलमान वोट के साथ सभी वर्गों में उनकी पहचान के बदौलत जीत सुनिश्चित है. पैक्स चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीते श्री यादव का दावा है कि वे विधानसभा चुनाव भी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे. वहीं राजद के टिकट के दावेदार पूर्व विधायक स्व. राजनन्दन राय के पुत्र प्रमोद राय भी हैं. राजनन्दन राय 1990 और 1995 में राजद के टिकट पर विधायक चुने गये थे, लेकिन 2000 के चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रहे. फरवरी 2005 में राजद से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे. अक्टूबर 2005 और 2010 में लोजपा से चुनाव लड़े, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा. प्रमोद राय को अपने पिता द्वारा किये गये विकास कार्यों पर भरोसा है. शिक्षित बेरोजगारों के लिए बनाया गया नन्दन मार्केट, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर आदि इन्हीं के कार्यकाल में बना था. प्रमोद राय के अनुसार पिता से ही इन्होंने राजनीति सीखी है. वे भी पिता राजनन्दन राय की तरह ही सकारात्मक राजनीति करते हैं. यही कारण है कि यादव समाज इन्हें अपना नेता मानता है. यादव मत के साथ वैश्य मत को भी प्रमोद अपना मानते हैं. इनका कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए इनके पिता ने कई कार्य किये, इसके कारण वैश्य समाज इनके साथ है. वहीं राजद का परंपरागत मुसलमान वोट भी इन्हें मिलेगा.महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी से भी दावेदारों की संख्या कम नहीं है. दो बार चुनावी जंग में अपना दम-खम दिखा चुके अब्दुल हफीज अंसारी कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं. श्री अंसारी आदापुर विधानसभा क्षेत्र से 2000 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारी पर चुनाव लड़े थे, जिसमें तीसरे स्थान पर रहे थे. पुन: 2005 के विधानसभा चुनाव में आदापुर से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लोजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, इसमें भी हार का सामना करना पड़ा. 2010 के चुनाव के समय परिसीमन के बाद आदापुर नरकटिया बन गया. बकौल श्री अंसारी आदापुर के 16 पंचायतों में इनकी मजबुत पकड़ है. चुनाव में नगरपालिका क्षेत्र ही बढ़त लेकर कोई विजयी होता है. नप क्षेत्र में किए गये कार्यों के कारण मुझे सबसे ज्यादा सहयोग मिलेगा. वहीं क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है. इनमें भी अंसारी सबसे ज्यादा हैं. महागठबंधन से अगर टिकट नहीं मिला तो जनता के फैसले के अनुसार निर्णय लिया जायेगा. श्री अंसारी को विरासत में राजनीति मिली है. इनके पिता मुखिया और भाई आदापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं. कांग्रेस के अन्य दावेदार हैं रामबाबू प्रसाद यादव. स्वयं को यादवों का एकछत्र नेता मानने वाले रामबाबू यादव 2010 के चुनाव में रक्सौल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे. तब वे तीसरे स्थान पर रहे थे. 2005 का चुनाव उन्होंने आदापुर से लड़ा था. राजद के प्रत्याशी के रूप में वे दूसरे स्थान पर रहे. श्री यादव के अनुसार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किये गये कार्यों का पुरस्कार जनता अवश्य देगी, जिसमें डंकन की तानाशाही रवैये को समाप्त कराने के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है. टिकट नहीं मिलने की स्थिति में रामबाबू निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं. वामपंथी कॉमरेड श्याम बिहारी तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं. भाकपा नेता श्याम बिहारी पहली बार चुनावी मैदान में जोर आजमायेंगे. इधर, रालोसपा के नरेश कुशवाहा संगठन को संगठित कर चुनावी धरती तलाश रहे हैं.

बहरहाल, राजनीतिक धुरंधरों की मानें तो इस बार चुनाव दिलचस्प होगा. समस्याओं से जूझ रहे लोगों की उदासीनता कम हो रही है. वोट मांगने के लिए आये नेताओं से जवाब तलब करेगी. पिछले लोकसभा चुनाव में पुरंदरा पंचायत के बाडी टोला के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया था. नेताओं से ग्रामीण फिर पुछेगी, क्या हुआ तेरा वादा.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध में विधान परिषद का चुनाव

कहीं भाजपा तो कहीं जदयू ने दी मात

सुनील सौरभ

मगध में विधान परिषद निकाय चुनाव में तीन सीटों में से दो पर जदयू तथा एक पर भाजपा ने जीत हासिल की. 2009 के चुनाव में तीनों सीटों गया-जहानाबाद, अरवल, नवादा तथा औरंगाबाद पर जदयू का कब्जा था. इस हिसाब से मगध में भाजपा ने औरंगाबाद सीट जदयू से छिनी. यहां भाजपा के प्रत्याशी राजन सिंह ने जदयू के प्रत्याशी रंजन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को 368 मतों से हराया. लेकिन गया-जहानाबाद, अरवल और नवादा सीट पर जदयू का कब्जा बरकरार रहा. नवादा से तो जदयू के सलमान रागिव लगातार तीसरी बार विधान पार्षद बने, जबकि गया-जहानाबाद, अरवल क्षेत्र से जदयू की मनोरमा देवी भाजपा प्रत्याशी अनुज सिंह को हराकर दूसरी बार विधान पार्षद बनीं.

2009 में अनुज सिंह जदयू प्रत्याशी के रूप में राजद प्रत्याशी मनोरमा देवी को हरा कर विधान पार्षद बने थे, लेकिन इस बार दोनों ने पार्टी बदल ली. विधान परिषद चुनाव से पूर्व मनोरमा देवी ने जदयू का दामन थाम लिया तो अनुज सिंह ने जदयू छोड़ भाजपा का दामन थाम विधान परिषद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गये. मनोरमा देवी ने अनुज कुमार सिंह को 555 मतों से शिकस्त दी. अनुज सिंह ने हार का ठीकरा किसी नेता या दलीय कार्यकर्त्ता पर नहीं फोड़ते हुए कहा कि जहानाबाद, अरवल के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने इनका सहयोग नहीं किया, जिससे इनकी हार हुई. सच कहा जाये तो भाजपा में कुछ नेता आस लगाये बैठे थे कि निकाय क्षेत्र के विधान परिषद सीट से उन्हें पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐन वक्त पर जदयू छोड़ भाजपा में शामिल होकर अनुज सिंह भाजपा के प्रत्याशी हो गये. यह बात भाजपा के अनेक नेताओं-कार्यकर्ताओं को पच नहीं पाया. भाजपा के सहयोगी दलों के लोगों ने भी खुलकर सहयोग नहीं किया. एक तरह

से कहा जाये तो अनुज सिंह भाजपा के स्थानीय नेताओं के अंदरूनी राजनीति तथा भीतरघात के शिकार हुए. भाजपा के नेताओं ने आरोप को खारिज करते हुए बताया कि अनुज सिंह को अपने ही लोगों ने धोखा दिया. लोग कहते मिले कि अनुज सिंह के जदयू के विधान पार्षद रहते जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी उनके गया स्थित घर पर भोजन पर आये, तब से अनुज सिंह का व्यवहार भी अपने लोगों के बीच बदल गया. लोगों का कहना है कि कुछ चापलूसों से अनुज सिंह घिर गये, जिससे अच्छे लोग उनसे कट गये. नतीजा सामने है. विधान परिषद चुनाव में बड़ी राशि खर्च करने पर भी अनुज सिंह को हार का सामना करना पड़ा.

उसी प्रकार नवादा निकाय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पराजित प्रत्याशी श्रवण कुमार ने अपनी हार का ठीकरा नवादा के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा हिसुआ के भाजपा विधायक अनिल सिंह पर फोड़ा है. यहां से जदयू के सलमान रागिव लगातार तीसरी बार जीत हासिल किये. सलमान रागिव नवादा की विधायक पूर्णिमा यादव और गोबिन्दपुर के विधायक कौशल यादव के खास माने जाते रहे हैं. उनकी जीत में विधायक पति-पत्नी कौशल यादव व पूर्णिमा यादव का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है. बताया जाता है कि भाजपा के हिसुआ विधायक अनिल सिंह तथा सासंद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा जिला परिषद की अध्यक्ष के पति बिरेन्द्र चौहान को भाजपा से टिकट चाहते थे. भाजपा का टिकट नहीं मिल सका. फलत: वीरेन्द्र चौहान निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में आ गये. उन्हें नवादा के सांसद और हिसुआ के विधायक का समर्थन मिला. यह आरोप कादिरगंज क्षेत्र के पंचायत के मुखिया रह चुके और विधान परिषद चुनाव में नवादा से भाजपा के प्रत्याशी बने श्रवण कुमार ने लगाया है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी श्रवण कुमार को जदयू प्रत्याशी सलमान रागिव ने करीब सवा दो सौ मतों से हराया. निर्दलीय प्रत्याशी विरेन्द्र चौहान को भी करीब सवा दो सौ मत मिले. उसी बात से श्रवण कुमार का गुस्सा अपने सांसद और विधायक पर है. भजापा प्रत्याशी श्रवण कुमार जीती हुई सीट हार जाने का कारण भीतरघात होना बताते हैं.

विधान परिषद चुनाव में मगध में जदयू को एक सीट का नुकसान ही हुआ. 2009 के चुनाव में जदयू का मगध के तीनों सीटों पर कब्जा था. तब जदयू-भाजपा का गंठबंधन था, लेकिन इस बार समीकरण उलटा हो गया. भाजपा का गठबंधन लोजपा-रालोसपा से हो गया, जदयू से भाजपा टूट गया. वहीं दूसरी ओर जदयू का राजद से तालमेल हो गया. बदले समीकरण में जदयू ने औरंगाबाद सीट खो दी. भाजपा प्रत्याशी राजन सिंह 1782 तो जदयू प्रत्याशी रंजन सिंह उर्फ मुन्ना को 1414 मत मिले. इस प्रकार 368 मतों से हार हुई. कहा जाये तो मगध में विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन का प्रभाव कुछ कम हुआ. भाजपा कुछ हद तक मगध में एक सीट लेकर सफल रहा.■

feedback@chauthiduniya.com

अमिताभ और नूतन पर गाजियाबाद की महिला से बलात्कार का जो मुक़दमा दर्ज किया गया, वह छह महीने पुराना मामला है. अमिताभ ख़ुद उसकी गहराई से जांच की मांग करते रहे हैं. उक्त महिला ने पिछले साल 31 दिसंबर को ही यह शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब पुलिस ने इसे तथ्यहीन मानकर मुक़दमा दर्ज नहीं किया था. जब मुलायम की धमकी वाला मामला सामने आया, तो अमिताभ के ख़िलाफ़ वही पुराना केस दर्ज कर लिया गया. ठाकुर दंपत्ति जब दिल्ली में थे, तभी उक्त महिला द्वारा धारा164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवा दिया गया, ताकि ठाकुर दंपत्ति को गिरफ्तार किया जा सके.

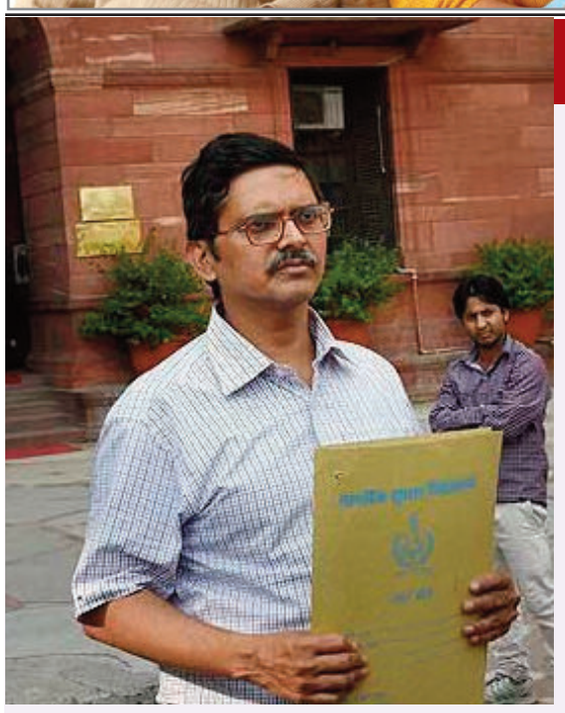

उत्तर प्रदेश

एक आईपीएस से भिड़ गई पूरी समाजवादी सरकार

मुलायम सिंह देश के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रकरण उनके कद और प्रतिष्ठा पर पैबंद की तरह चस्पा हो गया है. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा और सरकार के एक मुलाजिम के बीच की लड़ाई सड़क छाप हो गई है. निलंबित अमिताभ ठाकुर यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुलायम सिंह उन्हें समझा रहे थे, धमकी नहीं दे रहे थे. उन्होंने मुलायम की धमकी वाली रिकॉर्डिंग गृह मंत्रालय को सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने अपने और परिवार के जान-माल पर संकट की आशंका जताते हुए सुरक्षा भी मांगी है. मुलायम की धमकी को डांट बताने वाले अखिलेश मीडिया को यह बताने से कन्नी काट गए कि आख़िर अमिताभ ठाकुर की ग़लती क्या थी, जिस पर नेता जी नाराज़ होकर उन्हें डांटने लगे? आरटीआई एक्टिविज्म वह पहले से कर रहे थे, जनहित याचिकाएं वह पहले से दाखिल कर रहे थे, धरना-प्रदर्शन में वह पहले से शामिल होते रहे हैं और सरकार के ग़लत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वह विरोध पहले से दर्ज कराते रहे हैं, तो फिर सपा सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को दी गई धमकी को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी बुद्धिमानी से स्वीकारने और सहज बनाने की कोशिश की, लेकिन धमकी के तुरंत बाद ठाकुर पर बलात्कार का जो प्रतिशोधी मुक़दमा दर्ज कराया गया, उससे अखिलेश की राजनीति का दांव हल्का पड़ गया. मुलायम की कथित धमकी की कथित रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होने के बाद सपा नेता अनाप-शनाप बयान देने लगे, जिससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई. पार्टी ने पहले कहा कि धमकी वाला टेप फर्जी है, फिर अमिताभ ठाकुर एवं उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के ख़िलाफ़ बलात्कार का वह विवादास्पद मुक़दमा दर्ज करा दिया गया, जिस पर अदालत भी कह चुकी थी कि इसमें कोई क़ानूनी सूत्र नहीं है. वहीं लखनऊ पुलिस ने अमिताभ को धमकी की शिकायत पर मुलायम के ख़िलाफ़ मामला दर्ज नहीं किया.

दरअसल, कथित धमकी की कथित रिकॉर्डिंग की असलियत से सभी वाकिफ हैं, लिहाजा टेप तकनीकी जांच में जाए और समाजवादी पार्टी की भद हो, यह भांपते हुए अखिलेश ने बात संभालते हुए कहा कि नेताजी अभिभावक तुल्य हैं और ग़लती पर डांटने-समझाने का उन्हें हक़ है. काबीना मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी को डांटने का अधिकार है, इसे धमकी के रूप में नहीं लेना चाहिए. अखिलेश और शिवपाल के बयानों के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी का नैतिक दायित्व बनता है कि वह उक्त टेप को फर्जी बताने वाले अपने बयान पर सफाई दे, लेकिन ऐसा करने के बजाय पूरी पार्टी अमिताभ ठाकुर के ख़िलाफ़ गुस्सा उगलने में ऊर्जा लगा रही है. सपा सरकार ने आनन-फानन में अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर बता दिया कि वह बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. जबकि होना यह चाहिए था कि मुलायम सिंह खुद मीडिया के सामने आते और इस धमकी, झिड़की, डांट या हिदायत के बारे में सफाई देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

मुलायम सिंह देश के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रकरण उनके कद और प्रतिष्ठा पर पैबंद की तरह चस्पा हो गया है. उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सपा और सरकार के एक मुलाजिम के बीच की लड़ाई सड़क छाप हो गई है. निलंबित अमिताभ ठाकुर यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुलायम सिंह उन्हें समझा रहे थे, धमकी नहीं दे रहे थे. उन्होंने मुलायम की धमकी वाली रिकॉर्डिंग गृह मंत्रालय को सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की. उन्होंने अपने और परिवार के जान-माल पर संकट की आशंका जताते हुए सुरक्षा भी मांगी है. मुलायम की धमकी को डांट बताने वाले अखिलेश मीडिया को यह बताने से कन्नी काट गए कि आख़िर अमिताभ ठाकुर की ग़लती क्या थी, जिस पर नेता जी नाराज़ होकर उन्हें डांटने लगे? आरटीआई एक्टिविज्म वह पहले से कर रहे थे, जनहित याचिकाएं वह पहले से दाखिल कर रहे थे, धरना-प्रदर्शन में वह पहले से शामिल होते रहे हैं और सरकार के ग़लत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वह विरोध पहले से दर्ज कराते रहे हैं, तो फिर सपा सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मुलायम सिंह ने इस दरम्यान उन्हें क्यों नहीं डांटा?

अमिताभ एवं उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के प्रति सपा प्रमुख मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश की नाराज़गी प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ख़िलाफ़ चलाई गई मुहिम से गहराती गई. खनन मंत्री के भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे पहले प्रतापगढ़ के ओम शंकर द्विवेदी एवं उनके वकील अजय प्रताप सिंह राठौर ने की थी. लोकायुक्त से की गई इस शिकायत में कहा गया था कि प्रजापति ने जब विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था, तब उनकी संपत्ति 1.81 करोड़ रुपये की थी, लेकिन मंत्री बनने के बाद उनकी संपत्ति 942.57 करोड़ रुपये की हो गई. लोकायुक्त को 1,725 पृष्ठीय साक्ष्य भी सौंपा गया था. बाद में कई और संपत्तियों का ब्यौरा मिला. अब तक गायत्री की 1,350 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की रजिस्ट्री मिल चुकी है. जब हाईकोर्ट के निर्देश पर खनन मंत्री के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हो गया, तो सपा नेतृत्व बौखला गया.

बलात्कार का जो मुक़दमा मुलायम की धमकी के बाद अमिताभ पर दर्ज कराया गया, उसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों पर षड्यंत्र करने का मुक़दमा दर्ज किया गया था. जरीना ने ठाकुर पर दुष्कर्म करने और उनकी पत्नी नूतन पर उसमें सहयोग आरोप लगाया था. जवाब में नूतन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर गायत्री प्रजापति और जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों पर फर्जी फंसाने का आरोप लगाया और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज करने की मांग की. अदालत ने 20 जून को आरोपियों पर मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने अदालती आदेश की अनदेखी कर दी. इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई, तब जाकर मुक़दमा दर्ज हुआ.

अमिताभ और नूतन पर गाजियाबाद की महिला से बलात्कार का जो मुक़दमा दर्ज किया गया, वह छह महीने पुराना मामला है. अमिताभ खुद उसकी गहराई से जांच की मांग करते रहे हैं. उक्त महिला ने पिछले साल 31 दिसंबर को ही यह शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब पुलिस ने इसे तथ्यहीन मानकर मुक़दमा दर्ज नहीं किया था. जब मुलायम की धमकी वाला मामला सामने आया, तो अमिताभ के ख़िलाफ़ वही पुराना केस दर्ज कर लिया गया. ठाकुर दंपत्ति जब दिल्ली में थे, तभी उक्त महिला द्वारा धारा 164 में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवा दिया गया, ताकि ठाकुर दंपत्ति को गिरफ्तार किया जा सके. अमिताभ ने कहा कि यह और कुछ नहीं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक राजनीतिक साजिश और उत्पीड़न का प्रयास है.

मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ अमिताभ ठाकुर ने जैसे ही दिल्ली दरबार में गुहार लगाने के लिए कूच किया, प्रदेश सरकार ने उनका निलंबन आदेश टाइप कराना शुरू करा दिया. उधर गृह मंत्रालय से अमिताभ बाहर निकले और इधर उनके निलंबन आदेश पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी. निलंबन के लिए सरकार ने जो आरोप लगाए, वे अद्यतन नहीं हैं, पुराने हैं और सरकार के निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हैं. सरकार कहती है कि नागरिक सुरक्षा महकमे के महानिरीक्षक (आईजी) अमिताभ ठाकुर को स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासन विरोधी दृष्टिकोण, उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी, पद से जुड़े दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता और नियमों के उल्लंघन में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. सरकार खुद बताती है कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यह आदेश दिया था कि शासन की अनुमति के बिना कोई भी लोकसेवक जनहित याचिका दाखिल नहीं करेगा, जब तक संदर्भित प्रकरण में उसके व्यक्तिगत हित अंतर्निहित न हों. सरकार का कहना है कि अदालत की अवहेलना कर अमिताभ ठाकुर जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहे, बिना किसी अधिकार के शासन एवं विभिन्न शासकीय विभागों से जुड़े प्रकरणों की स्वयंभू जांच करते रहे और मीडिया के सामने शासन की नीतियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी करते रहे. आम लोगों का यह सवाल भी इस निलंबन आदेश के साथ चस्पा है कि इन आरोपों पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अनुशासनिक कार्रवाई करने के बजाय धमकी का सहारा क्यों लिया गया? प्रशासनिक मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा हस्तक्षेप क्यों किया? खनन मंत्री के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होने के पहले तक सरकार ठाकुर की गतिविधियों पर चुप्पी क्यों साधे रही?

केंद्र से अमिताभ ने क्या कहा

गृह सचिव को संबोधित शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि फोन पर मुलायम सिंह यादव द्वारा जसराना की घटना का जिक्र करते हुए धमकी देना और उनके श्वसुर से हुई मुलाकात का हवाला देना यह साबित करता है कि फोन पर मुलायम खुद थे, कोई अन्य नहीं. जसराना की घटना वर्ष 2006 में घटी थी, जब वह (अमिताभ) फिरोजाबाद के एसपी थे और मुलायम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री. मुलायम के समधी रामवीर सिंह जसराना के विधायक थे और एक सिफारिश से इंकार किए जाने से वह उनसे (अमिताभ) नाराज़ चल रहे थे. तत्कालीन मंत्री शिवपाल सिंह यादव के एक कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते समय उन पर स्कूल के अंदर कातिलाना हमला कराया गया. वहां तत्कालीन ज़िलाधिकारी संयुक्ता समाद्दार भी मौजूद थीं. घटना के बीच ही अमिताभ ने मुलायम सिंह को फोन कर स्थिति बताई, तो मुलायम ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन उन्हें एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया. इसके बावजूद उन्होंने एका थाने पर एफआईआर दर्ज कराई. कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ, लिहाजा बाद में रामवीर सिंह समेत सभी अभियुक्त बरी हो गए. अमिताभ ने गृह मंत्रालय को बताया कि जिस नंबर से फोन आया था, वह नंबर मुलायम सिंह के आवास का है. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच और मुलायम सिंह एवं गायत्री प्रजापति से अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की मांग की. अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी अपनी शिकायत भेजी है. हजरतगंज थाने में शिकायत पेश करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन औपचारिक रूप से तहरीर रिसीव करने के बाद अमिताभ ठाकुर को थाने से लौटा दिया गया.

घिरती जा रही है सपा सरकार

खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और काली कमाई के सिरमौर यादव सिंह को खुलेआम संरक्षण देने वाली सपा सरकार लगातार विभिन्न मामलों में शासनिक ग़ैर ज़िम्मेदारी बरतने और अराजकता को बढ़ावा देने के आरोपों में घिरती जा रही है. विधान परिषद में मनोनयन का मसला भी गंभीर विवादों में फंस गया. संदिग्ध आचरण के लोगों की सूची राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटा दी और पांच लोगों के मनोनयन का मसला लटका रह गया. सपा सरकार ने जिस संजय सेठ को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए चुना था, उसके ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा और अकूत काले धन का खुलासा सुर्ख़ियों में रहा. राज्य मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा के इशारे पर शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को मंत्री के गुंडों और पुलिस द्वारा दिनदहाड़े घर में घुसकर जलाकर मार डालने की घटना में सपा सरकार ने जिस तरह लीपापोती की, उसे आम लोगों ने देखा. राजधानी लखनऊ के क़रीब बाराबंकी के कोठी थाने में थाना प्रभारी साहेब सिंह यादव और एक अन्य दारोगा ने मिलकर एक पत्रकार की मां के साथ बलात्कार की कोशिश की. विरोध करने पर उसे थाने में जलाकर मार डालने की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया. शासन से लेकर प्रशासन तक अराजकता से भर गया है. किसी अधिकारी के ख़िलाफ़ ख़बर लिखने पर पत्रकारों को जान से मार डालने की खुलेआम धमकियां दी जाती हैं. पत्रकार अनूप गुप्ता ने वरिष्ठ नौकरशाह नवनीत सहगल के ख़िलाफ़ अपनी पत्रिका में ख़बर लिखी, तो उन पर न केवल मानहानि का मुक़दमा दर्ज हुआ, साथ ही आपराधिक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई. मामले की सुनवाई के समय भरी अदालत में वकील वेशधारी अराजकतत्वों ने अनूप पर हमला करने की कोशिश की और खुलेआम गालियां दीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

किस-किस से निपटेंगे मुलायम!

उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं, जिनकी साफ़गोई या बेबाकी से सरकार अक्सर संकट में आ जाती है. नया नाम वरिष्ठ आईएएस डॉ. सूर्य प्रताप सिंह का है. 1980 बैच के आईएएस सिंह 34 सालों के करियर में नौ साल विदेश में रहे. स्टडी लीव से वापस लौटने पर उन्हें औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव पद पर तैनाती दी गई. हाल में वह माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए थे. इस समय वह सार्वजनिक उद्यम विभाग में प्रमुख सचिव हैं. सिंह ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रहते हुए बोर्ड परीक्षा से पहले नकल माफियाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी. इस पर सरकार ने उनका तबादला लघु सिंचाई विभाग में कर दिया, जहां चेकडैम घोटाला उजागर करने के बाद उन्हें सार्वजनिक उद्यम विभाग भेज दिया गया. इसके बाद भी सिंह चुप नहीं बैठे हैं और सोशल साइट्स के अलावा अख़बारों में भी अपने बेबाक विचार व्यक्त करके सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. वह समूह-ग की भर्ती में भ्रष्टाचार और यादववाद, प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए किसानों को मुआवजा देने, पीसीएस-प्री का पर्चा लीक होने का मुद्दा उठाने के कारण भी सुर्ख़ियों में रहे. आईपीएस विभूति नारायण राय की बेबाकी मशहूर रही है. उनके एक्टिविस्ट स्वभाव ने उन्हें उपन्यासकार से लेकर वाइस चांसलर तक बनाया, लेकिन पुलिस अफसर के रूप में वह असफल रहे. मेरठ-मलियाना-हाशिमपुरा दंगे पर उनका उपन्यास-शहर में कर्फ्यू काफी चर्चित रहा और सरकार काफी विवादित. दंगे में पीएसी के शरीक होने पर उन्होंने आईपीएस रहते हुए आवाज़ उठाई थी. अब भी हाईकोर्ट के ताजा फ़ैसले पर राय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है. मेरठ दंगे के समय राय गाजियाबाद के एसएसपी थे. उन्होंने पीएसी के ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज कराई थी. वह क़रीब 28 सालों तक अदालत में चले इस मामले के साक्षी रहे हैं. माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के समर्थन में मुलायम के उतरने पर पीपीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह का विद्रोह लोगों को अब तक याद है. सेना के हथियारों की चोरी में मुख्तार के शामिल रहने के पुख्ता सुबूत शैलेंद्र सिंह ने इकट्ठा कर लिए थे और उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. मुलायम ने शैलेंद्र को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने यह ग़ैर वाजिब आदेश मानने से इंकार कर दिया. शैलेंद्र ने सरकार के ख़िलाफ़ खुला विद्रोह करते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. शैलेंद्र के इस क़दम से नाराज़ होकर सरकार ने देर रात उनके घर पुलिस भेजकर उन्हें अपमानित कराया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मायावती सरकार के ख़िलाफ़ खुला विद्रोह करने वाले आईएएस विजय शंकर पांडेय भी सुर्ख़ियों में रहे. 1979 बैच के आईएएस विजय शंकर पांडेय ने सरकार से अनुमति लिए बिना विदेश से काला धन वापस लाने और देश के सबसे बड़े टैक्स चोर हसन अली के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय की चल रही सुस्त जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां यह आदेश जारी हुआ कि ढीली जांच के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उनसे जुर्माना वसूला जाए. पांडेय पर मायावती इतनी नाराज़ हुईं कि आईएएस सर्विस रूल्स के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन पर विभागीय जांच बैठा दी गई, लेकिन जांच में सारे आरोप निराधार पाए गए. विडंबना यह कि मायावती सरकार जाने के बाद भी उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ. अखिलेश सरकार ने भी पांडेय पर जांच बैठा दी. जांच कमेटी में तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त (मौजूदा मुख्य सचिव) आलोक रंजन और अनिल कुमार गुप्ता थे. सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ विजय शंकर पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी अर्जी खारिज हो गई. पांडेय सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां से उन्हें न्याय मिला. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

दलाल युग में भारत

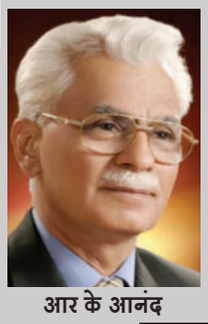

आर के आनंद

सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि नीरा राडिया कैसे भारत के तत्कालीन हालात में फिट बैठीं? वे कौन-सी ताकतें और राजनीतिक एवं आर्थिक बाध्यताएं रहीं, जिन्होंने इस महिला को जन्म दिया? इसका साधारण-सा जवाब यह है कि वह उस आधुनिक भारत की उपज हैं, जहां क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर में उद्योगपति सिर्फ़ उत्पाद या सेवा नहीं बेचते, बल्कि वे उन राजनीतिज्ञों को बहुत सारा पैसा वापस देने के लिए धन का निर्माण भी करते हैं, जिन्होंने उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने में मदद की हो. वैसे लोग, जो राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों एवं व्यवसायियों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, लॉबिस्ट कहलाते हैं. अमेरिका जैसे देश में ऐसे लोग तो बाकायदा आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड होते हैं और अपने क्लाइंट (ग्राहक) का नाम तक बताते हैं.

नीरा राडिया की तुलना शायद वॉशिंगटन के उस बड़े डिटा बेर्ड से की जा सकती है, जिसने 1970 के दशक में आईटीटी कंपनी के लिए लॉबिंग की थी. डिटा बेर्ड ने रिपब्लिकन पार्टी और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए काफी धन जुटाया था और बदले में आईटीटी कंपनी के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट से काम निकलवाया था. बाद में इन सबकी संघीय जांच हुई और निक्सन के ख़िलाफ़ वाटरगेट प्रकरण के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा. इसके लिए महान स्तंभकार जैक एंडरसन की खोजपरक रिपोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन भारत की नीरा राडिया के मामले में ऐसा नहीं हुआ. यहां पर देश के बड़े पत्रकारों, जिनका काम इस केस को सामने लाने का था, ने नीरा के साथ मिलकर साजिशें रचीं. इन पत्रकारों ने डीएमके के ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने के लिए लॉबिंग की, ताकि उनके ग्राहकों (क्लाइंट्स) को बदले में टेलीफोन स्पेक्ट्रम का आवंटन आसानी से हो सके. अंतत: इस वजह से भारतीय खजाने को करोड़ों करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसे लोगों के लिए अचानक भारत क्यों स्वर्ग बनता जा रहा था? इस विकास क्रम की गाथा की जड़ें, जिसमें नीरा की कहानी भी शामिल है, भारत में प्रभावशाली और छिपे हुए ऐसे लोगों के विकास से जुड़ी है, जो किसी भी काम को अपने हक़ में कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

फिक्सिंग की ललित कला

जी फाइल्स (शासन व्यवस्था पर भारत की एक विश्वसनीय मासिक पत्रिका) के हालिया अंक में लिखा है कि फिक्सर (बिचौलिए) अब भारतीय शासन व्यवस्था की धुंधली दुनिया के एक स्थायी हिस्से बन गए हैं. मैं उस लेख के कुछ हिस्सों का यहां उल्लेख करना चाहूंगा. पत्रिका के मुताबिक, बिचौलियों की इस स्थिति का भारतीय राज व्यवस्था में कहीं कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है, लेकिन राजकाज के मामले में यह संस्थागत रूप ले चुका है. एक बिचौलिए का जीवनकाल नियत है. जब बिचौलियों की ज़रूरत होती है, तब उनका कद बहुत बड़ा होता है. वे राजनीतिज्ञों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं. नौकरशाहों के मुक़ाबले ज़्यादा जानकार होते हैं. गपशप, संदेहास्पद वित्तीय एवं व्यक्तिगत जानकारी, चापलूसी, ब्लैकमेलिंग और अपने आकर्षण से वे ऐसे काम भी करा लेते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री, मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री तक संभव नहीं मानते.

जी फाइल्स के मुताबिक, असंभव को संभव बना देने की इस कला से उनकी ज़िंदगी चलती रहती है. कुछ बिना किसी शोर के नेपथ्य में चले जाते हैं. कुछ अपनी क्षणभंगुर ताकत से अंजान किसी राजनीतिक दल में जगह तलाशते हैं, संसद में नामित होने की कोशिश करते हैं या एक सफल व्यापार शुरू करने की कोशिश करते हैं. उन्हें द्रोही माना जाता है. उन्हें कभी भी असली भाईचारे वाली बिरादरी या राजनेताओं, नौकरशाहों एवं उद्योगपतियों जैसे कुलीन तंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिनके लिए कभी उन्होंने काम किया हो. शक्ति, आकर्षण, मोहकता, बुद्धिमत्ता, सुंदर महिलाओं का साथ होने के बाद भी जब एक बिचौलिए का समय ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म ही हो जाता है. फिर उसे कोई नहीं पूछता. काम निकलने के बाद उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है. ऐसे लोगों में, नीरा राडिया से पहले भी, राज्यसभा सांसद एवं उद्योगपति अमर सिंह का नाम सभी ने सुना होगा.

जी फाइल्स के मुताबिक, सिंह का एक विशेष आकर्षण था, बाकी के डीलर्स से अलग. वह एक बेहतर श्रोता हैं, अधिक शक्तिशाली हैं और डरपोक नहीं हैं. उन्होंने केके बिड़ला, शोभना भरतिया एवं उनके पति श्याम के लिए काम करते वक्त ही एक मददकर्ता (फैसिलिटेटर) का महत्व समझ लिया था. उन्हें मालूम हो गया था कि केके, जिनके परिवार ने शुरू से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था और उनकी मीडिया पसंद बेटी शोभना भरतिया खुद से अपने परिवार के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती. चाहे वह न्यूजप्रिंट खरीदने या गजरौला (उत्तर प्रदेश) में फैक्ट्री के लिए नौकरशाहों या मंत्री से काम निकलवाने की बात हो. अमर सिंह को पता था कि इस सबके लिए उन्हें एक बेहद ताकतवर बिचौलिया चाहिए, जो सरकार के हर स्तर पर उनके लिए काम कर सके.

अमर सिंह ने दरबार राजनीति बारीकी से सीखी. बिना शीर्ष नेतृत्व को खीज दिलाए, उन्होंने कुशलता से पार्टी के लिए फंड जुटाया. उदारवाद आने के बाद जब वह बिड़ला के काम के नहीं रहे, तब उन्होंने मंडल राजनीति चलाने वाली ठाकुर ब्रिगेड को पकड़ लिया. वह अमेठी के राजा संजय सिंह और फिर वीर बहादुर सिंह के असामयिक निधन के बाद उत्तर प्रदेश में यादव राजनीति शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ते चले गए. जी फाइल्स के मुताबिक, अमर सिंह की विशेषता राजनीति में ग्लैमर शामिल करने को लेकर थी. यह गुण उन्होंने सुब्रत राय से सीखा, जिनके बिजनेस का यूएसपी था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे जमाकर्ताओं के साथ बच्चन, सुष्मिता सेन, राज बब्बर, कविता कृष्णमूर्ति, कपिल देव, अजय जडेजा, सुभाष घई, ऐश्वर्या राय एवं स्वप्ना बनर्जी के ग्लैमर का संयोजन. कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अमर सिंह बचपन से बॉलीवुड के दीवाने थे और कलाकारों के ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे भागते थे. वह फिल्म देखने के बाद उसके डॉयलाग दोहराते थे. उनके दोस्त बताते हैं कि यह अमर सिंह ही थे, जो अमिताभ बच्चन के एबीसीएल के खस्ताहाल होने के बाद उनकी मदद के लिए आगे आए थे. उनके दोस्तों का दावा है कि वही सुब्रत राय के बॉलीवुड कनेक्शन थे.

इसी तरह जी फाइल्स की स्टोरी उस डिबेट के बारे में बताती है कि वह कौन था, जिसने अंबानी को मुलायम सिंह कैंप तक पहुंचाया. सुब्रत राय के दोस्त बताते हैं कि सहाराश्री धीरू भाई अंबानी के बहुत बड़े प्रशंसक थे. वह अक्सर धीरू भाई से कंपनी में अनुशासन बरकरार रखने एवं निवेश आदि पर सलाह लेते थे. खैर, कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश की ज़रूरत थी और अपनी छवि भी चमकानी थी. मुलायम सिंह अमर सिंह को चाहते थे और अमर सिंह अमिताभ बच्चन एवं धीरू भाई अंबानी को पसंद करते थे (बाद में अनिल अंबानी ने दादरी में एक पॉवर प्रोजेक्ट भी लगाया). अमर सिंह सुब्रत राय के क़रीबी थे और ऐश्वर्या राय को बेटी एवं अभिषेक बच्चन को बेटे की तरह चाहते थे. ये सब एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह इकट्ठा हो गए. लेकिन, एक दिन अमर सिंह ने खुद को अलग-थलग पाया. पॉलिटिकल एनालिस्ट वीर सांघवी को उम्मीद थी कि अमर सिंह की सपा में वापसी होगी. पर सांघवी यह भूल गए थे कि एक बार आम खा लेने के बाद उसकी गुठली मुंह में कोई नहीं डालता. आज वहीं सांघवी खुद अपनी ही संस्था के लिए ग़ैर बन गए हैं और खुद को नीरा राडिया टेप विवाद से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं.

जी फाइल्स के मुताबिक, बिचौलिए (फिक्सर) उभरते हैं, स्टेज पर कद दिखाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं. आज़ादी के बाद की भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के समय यह शीर्ष बिचौलिया संस्कृति आई. इंदिरा गांधी को खुद ऐसे वफादार बिचौलियों की ज़रूरत थी, जो जगजीवन राम और मोरारजी देसाई जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं को रास्ता दिखाने में मदद कर सकें. जवाहर लाल नेहरू के वक्त कोई थी शख्स ऐसे डीलमेकर्स, फिक्सर्स और बिचौलियों से बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था. नेतृत्व साधारण था, ईमानदार था और मेहनती था. नौकरशाह कर्तव्यनिष्ठ थे. नेहरू अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा करते थे और सीधे उनके संपर्क में रहते थे. बहरहाल, जितने परिपक्व बिचौलिए होंगे, उनकी न किसी पार्टी, न किसी विचारधारा, न किसी व्यक्ति या देशहित के प्रति कोई प्रतिबद्धता होगी. पैसा ही उनके लिए सब कुछ होता है. पूर्व कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने एक बार कहा था कि दिल्ली 200 प्रभावशाली लोगों का शहर है.

लायजनर्स

नीरा राडिया से पहले भी कॉरपोरेट घरानों जैसे बिड़ला, सिंहानिया ने नौकरशाहों और नेताओं के क़रीब होने के लिए अपने यहां लायजन ऑफिसर्स (संपर्क अधिकारी) रखे थे, जिनका काम था समस्या का पता लगाना और फिर अपनी चतुराई से उसका समाधान निकालना. उक्त अधिकारी (पुरुष और महिला, दोनों) साधारण ढंग से रहते थे. वे ज़्यादा दिखते नहीं थे और दिल्ली या राज्यों की राजधानी में उनकी चर्चा नहीं के बराबर थी.

अर्थव्यवस्था पर सरकार और पब्लिक सेक्टर के नियंत्रण के दौर में इन लायजन ऑफिसर्स को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, सिवाय परचेज ऑर्डर पाने के लिए मंत्रियों के लंबित पड़ी फाइलों को सेक्शन ऑफिसर्स या एलडीसी के पास जाकर निपटवाने के. आधुनिक समय में लायजन ऑफिसर्स संसद सत्र से पहले ड्यूटी चेंज, एक्साइज कंसेशन से जुड़ी फाइलें निपटवाने का काम करने लगे. थोड़े ज़्यादा स्मार्ट लायजन ऑफिसर्स को तब अपने बॉस से ईनाम भी मिलता था, जब वे अपने हित से जुड़े किसी मसले पर संसद के भीतर किसी सांसद से सवाल उठवा पाने में सफल हो जाते थे, खासकर तारांकित सवाल.

इन लायजन ऑफिसर्स के अलावा निजी कंपनियों ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स (जनसंपर्क अधिकारी) नियुक्त किए, जो बेहतरीन अंग्रेजी में प्रेस रिलीज लिखने का काम करते थे, लेकिन उनकी भूमिका भी सीमित थी, क्योंकि तब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जमाना था और तत्कालीन मीडिया ज़्यादातर किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को खास तवज्जो नहीं देता था. वजह, इससे एक प्राइवेट कंपनी का एडवरटिजमेंट होने का ख़तरा रहता था. उदारवाद ने एक जबरदस्त बदलाव ला दिया. यह बदलाव सुनामी की तरह था. व्यापार का पूरा वातावरण बदल गया. प्राइवेट सेक्टर धीरे-धीरे पब्लिक सेक्टर पर हावी होता गया. इससे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना को बल मिलता गया. कहते हैं कि बिजनेस से बिजनेस बढ़ता है. व्यापार बढ़ाने के लिए पब्लिक रिलेशन एजेंसीज और पीआर फर्म्स की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगी. उनमें प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए अनुभवी पत्रकार नियुक्त किए जाने लगे. मीडिया के अपने पुराने संबंधों की वजह से इन पत्रकारों की, जो अब पीआर हो गए, कॉरपोरेट्स, मीडिया और सरकार के बीच मिडिलमैन (बिचौलिए) की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक खोज होने लगी. 1992 में उदारवाद की शुरुआत के बाद से लाइसेंस-परमिट राज के ख़ात्मे का संकेत मिलने लगा, लेकिन इस बदलाव का अर्थ यह नहीं था कि इससे सरकार की भूमिका कम हो गई. इसका मतलब था कि प्राइवेट सेक्टर को पॉवर, टेलिकॉम, माइनिंग, ऑयल एवं गैस आदि सेक्टरों में आने की अनुमति मिल गई.

इन सेक्टरों पर कभी सिर्फ़ पब्लिक सेक्टर का कब्जा था. यहां से बहुत कुछ पाने के लिए इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी की ज़रूरत थी. इस जटिलता के चलते अधिकाधिक अनुभवी पीआरओ की ज़रूरत पड़ी, जो संबंधित मंत्रालयों में बाबुओं को प्रभावित कर सकें और अव्यवहारिक एवं पेचीदा नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ सकें. इससे ऐसे संगठनों के लिए रास्ता खुला, जो नीति में बदलाव (पॉलिसी चेंज) के लिए लॉबिंग कर सकते हों. इस स्थिति ने ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत को जन्म दिया, जो तकनीक से लैस हों और किसी कॉरपोरेशन के लिए लॉबिंग कर सकें. पब्लिक रिलेशन कंपनीज ऐसे लोगों को नियुक्त करने के लिए अति उत्साहित हैं, जो लॉबिंग में महारथ रखते हों. ■ *जारी....*

वीर सांघवी

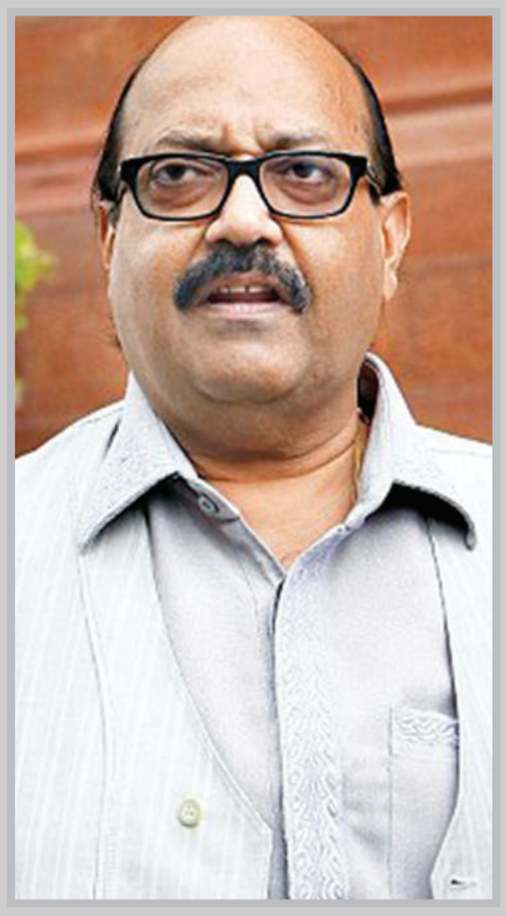

नीरा राडिया से पहले भी कॉरपोरेट घरानों जैसे बिड़ला, सिंहानिया ने नौकरशाहों और नेताओं के क़रीब होने के लिए अपने यहां लायजन ऑफिसर्स (संपर्क अधिकारी) रखे थे, जिनका काम था समस्या का पता लगाना और फिर अपनी चतुराई से उसका समाधान निकालना. उक्त अधिकारी (पुरुष और महिला, दोनों) साधारण ढंग से रहते थे. वे ज़्यादा दिखते नहीं थे और दिल्ली या राज्यों की राजधानी में उनकी चर्चा नहीं के बराबर थी. अर्थव्यवस्था पर सरकार और पब्लिक सेक्टर के नियंत्रण के दौर में इन लायजन ऑफिसर्स को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, सिवाय परचेज ऑर्डर पाने के लिए मंत्रियों के लंबित पड़ी फाइलों को सेक्शन ऑफिसर्स या एलडीसी के पास जाकर निपटवाने के.

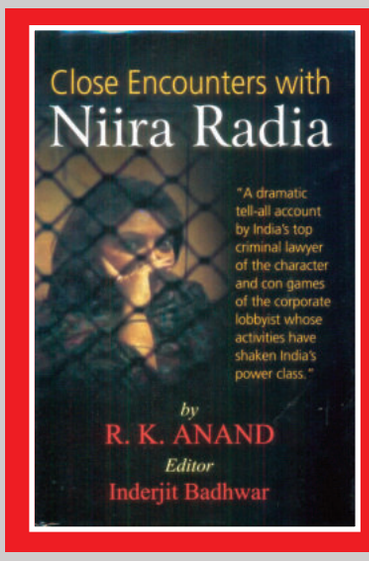

मशहूर वकील आर के आनंद की किताब *क्लोज इन्काउंटर्स विद नीरा राडिया* भारत की उस तस्वीर की कहानी है, जहां पैसा, चालाकी, धूर्तता, सुंदरता और चापलूसी का कॉकटेल सब पर भारी पड़ता है. यह कॉरपोरेट्स की ताकत यानी दलालों, लॉबिस्टों और लायजनर्स की अंतरंग दुनिया की कहानी है. चौथी दुनिया अगले कुछ अंकों में आपको इसी अंतरंग दुनिया की कहानी से रूबरू कराएगा.

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह हक़ीक़त है कि सीएजी द्वारा उजागर किए गए घोटालों से यूपीए को बहुत नुक़सान हुआ और चुनाव में उसका लगभग सफ़ाया हो गया, लेकिन इस वजह से आप उनसे यह श्रेय नहीं ले सकते कि उनके 10 साल के शासनकाल में सकल घरेलू उत्पाद दो गुना हो गया था. यह कोई छोटी बात नहीं है. हमें यह समझना चाहिए कि कोई देश एक या दो साल में कुछ ख़ास हासिल नहीं कर लेता. हां, चुनाव ज़रूर हर पांच साल में होते हैं, लेकिन किसी देश को दीर्घकालिक आधार पर काम करना होता है. ख़ासकर, भारत जैसे देश में यह और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहां एक बड़ी जनसंख्या है.

अच्छे दिन का क्या अर्थ है

भाजपा ने सत्ता में अपना एक वर्ष पूरा कर लिया है. अब उसे चुनाव के दौरान किए गए मुश्किल वादों से ख़तरा महसूस होने लगा है. काले धन के संबंध में यह कहना कि हर भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे, मज़ाक का विषय बना हुआ है. अमित शाह इसे चुनावी जुमला कहकर पहले ही ख़ारिज कर चुके हैं. अब अमित शाह ने भाजपा के चुनावी नारे–अच्छे दिन आने वाले हैं, पर बयान देते हुए कहा है कि अच्छे दिन आने में 25 साल लग जाएंगे. इस बयान का अर्थ हमें समझ में नहीं आया. बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका बयान भारत को अपने अतीत का गौरव प्राप्त करने से संबंधित था. ये सारी बातें शुभ संकेत नहीं हैं. चुनावी भाषण अलग बात है, लेकिन एक बार जब आप सत्ता में आ जाते हैं, तो आपको अपने वादों का यथार्थ पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए और यथार्थ पूर्ण वादे करने चाहिए.

बहरहाल, आपके अच्छे दिन का क्या अर्थ है? कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अच्छे दिन का यह अर्थ नहीं होगा कि श्रमिक वर्ग के भी अच्छे दिन आ गए. किसानों के अच्छे दिन वर्षा पर निर्भर हैं. ये बहुत ही जटिल विषय हैं. चुनावी हथकंडे के तौर पर या देश में व्याप्त नकारात्मकता के ज़रिये अपने पक्ष में वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से तो अच्छा है कि आप कहें कि अच्छे दिन लाने के लिए भाजपा का चुनाव करें. लेकिन, अमित शाह की यह कौन–सी रणनीति है, जिसके तहत वह अपने ही वादों की नई व्याख्या कर रहे हैं. आप 25 साल का समय कैसे मांग सकते हैं, यह बेतुकी बात है. जैसा कि किसी ने ट्वीटर पर जोक शेयर किया कि 25 साल मांग कर आप किसी वादे की बात कर रहे हैं या किसी पेंशन स्कीम की? 25 साल किसी वोटर को अपना वोट देने का निर्णय लेने के लिए अस्वाभाविक समय है.

अब यथार्थ की तरफ़ लौटते हैं. मुझे ख़ुशी है कि सरकार को यह एहसास हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ा था कि वह सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का व्यय बढ़ाने जा रही है, सामाजिक क्षेत्र पर और अधिक धन आवंटित कर रही है. यह एक स्वागत योग फ़ैसला है. शायद उन्होंने बाद में सोचा होगा कि मनरेगा या खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं से वास्तव में ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचा है. ये वे लोग थे, जिन्हें इस फ़ायदे की ज़रूरत थी. मिसाल के तौर पर एलपीजी गैस सिलेंडर की प्रत्यक्ष लाभ योजना प्रत्यक्ष रूप से ज़रूरतमंदों की मदद करेगी. सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर, सस्ता अनाज एवं सरकारी सहायता ग़रीबों तक पहुंचाने में बिचौलियों और लाल फीताशाही को जितना अधिक ख़त्म करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और कनेक्टिविटी द्वारा हम इन खामियों को कम कर सकते हैं.

मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी घटनाक्रमों से वाकिफ होंगे, लेकिन अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हैं. बिहार में चुनाव होने वाले हैं और शायद यह कोशिश है कि लोगों की अपेक्षाएं कम कर दी जाएं, ताकि वे किसी चमत्कार की आशा में बिहार चुनाव के दौरान यह न पूछने लगें कि एक साल पूरा हो गया, इस दौरान क्या हुआ? वास्तव में एक साल के दौरान यह सरकार बहुत भाग्यशाली रही है. पहली बात तो यह कि पिछले साल मानसून की बारिश पूर्वानुमान से बेहतर हुई. पेट्रोल की क़ीमतें लगातार कम रहीं, जिसकी वजह से महंगाई दर काबू में रही. इस साल अगर मानसून ठीकठाक नहीं रहता है, तो भी कोई खास फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वह ज़माना नहीं रहा, जब एक साल का खराब मानसून किसानों पर भारी पड़ता था. एक खराब मानसून किसान बर्दाश्त कर सकता है. हां, अगर दो मानसून खराब निकल गए, तो परेशानी पैदा कर सकते हैं. कुल मिलाकर देश में कोई संकट नहीं है. लेकिन, मेरे ख्याल में यदि संकट है, तो वह है नीति निर्धारण या शासन व्यवस्था का. उन्हें विरासत में वह मिला, जो पिछले दस सालों से चल रहा था. इस दौरान डॉ. मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिमान और चिदंबरम जैसे कुशल लोग जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे, उन्होंने किया.

यह हकीक़त है कि सीएजी द्वारा उजागर किए गए घोटालों से यूपीए को बहुत नुक़सान हुआ और चुनाव में उसका लगभग सफाया हो गया, लेकिन इस वजह से आप उनसे यह श्रेय नहीं ले सकते कि उनके 10 साल के शासनकाल में सकल घरेलू उत्पाद दो गुना हो गया था. यह कोई छोटी बात नहीं है. हमें यह समझना चाहिए कि कोई देश एक या दो साल में कुछ खास हासिल नहीं कर लेता. हां, चुनाव ज़रूर हर पांच साल में होते हैं, लेकिन किसी देश को दीर्घकालिक आधार पर काम करना होता है. खासकर भारत जैसे देश में यह और भी ज़रूरी है, क्योंकि यहां एक बड़ी जनसंख्या है, यह विविधता से भरा देश है और यहां अमीर–ग़रीब के बीच आय की गहरी खाई है. कोई भी सरकार एक ऐसी नीति बना सकती है, जिससे सब खुश हो जाएं. एक साल के भीतर इस सरकार से सबसे ज़्यादा निराश कॉरपोरेट सेक्टर है, जिसने कुछ अधिक ही चमत्कार की उम्मीद कर ली थी. वह शेयर मार्केट और एफडीआई में जबरदस्त उछाल की उम्मीद कर रहा था. ऐसा देशहित में था या नहीं, यह एक अलग विषय है.

मुझे लगता है कि सरकार को कृषि पर ध्यान देना चाहिए. इसमें अगले कुछ सालों तक निवेश होना चाहिए. हमें नहीं मालूम कि पांच साल बाद इस सरकार को कैसा बहुमत मिलेगा, लेकिन सरकार को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए. मैं यह मानता हूं कि इतिहास डॉ. मनमोहन सिंह के प्रति आज के मीडिया के मुक़ाबले ज़्यादा उदार रहेगा. तत्कालीन मीडिया तत्कालीन तर्कों के हिसाब से चलता है. पिछले दस साल कुल मिलाकर ठीक थे. भारत ने इस दौरान विकास किया. यदि बिना किसी घोटाले के ऐसा नतीजा आता, तो और बेहतर होता. मुझे नहीं मालूम कि आर्थिक नीतियों, वित्तीय नीतियों, कॉरपोरेट लॉ, सेबी आदि पर कौन लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं. मुझे लगता है कि इस सबमें बेहतर प्रशासन और क्षमता की ज़रूरत है. सत्ता में आते ही सरकार ने कर–आतंकवाद ख़त्म करने की बात कही थी, लेकिन नौकरशाह इसकी अनुमति नहीं देंगे. आयकर विभाग अपनी कोई भी ताकत नहीं खोना चाहेगा. अगर सरकार कर छूट की सीमा और बढ़ाकर लोगों को राहत देना चाहती है, तो भी नौकरशाह एवं अर्थशास्त्री इसकी अनुमति नहीं देंगे. वे कर का दायरा और बढ़ाने की बात करेंगे. लेकिन भारत में आप कर का दायरा अधिक नहीं बढ़ा सकते, बिना किसानों एवं कृषि क्षेत्र को शामिल किए, जो आप संविधान के अनुसार कर नहीं सकते.

इसलिए आपके पास यही उपाय बचा है कि आप ऐसे लोगों पर कर न लगाएं, जो बमुश्किल इतना भी नहीं कमा पाते, जिससे वे अपने परिवार को साथ रख सकें. छूट की सीमा बढ़नी चाहिए, ताकि करदाताओं की संख्या में कमी आए और जो बच जाते हैं, उनसे प्रभावी तरीके से कर वसूला जाए. यहां कर की चोरी आम बात है. फिर आप काले धन की बात करते हैं. आख़िर यह बाहर जाता कैसे है? ज़रूर आपकी व्यवस्था में खामी है. एक साल से अधिक हो चुके हैं. प्रधानमंत्री जी को इन लोगों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए. अगर ज़रूरी हो, तो उन्हें विपक्ष से भी बात करनी चाहिए. उन्हें कांग्रेस के लोगों से बात करनी चाहिए, जो देश चला चुके हैं. ठीक है कि उनकी बात आप न मानें, लेकिन देशहित के लिए मिलकर नीतियां तो बना सकते हैं. सरकार के पास अभी चार साल हैं, लेकिन यह कहना कि 25 साल लगेंगे, ग़लत है. इससे यह संदेश जाता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागना चाहते हैं. यह सही नहीं है.

दूसरी बात, जस्टिस लोढ़ा ने आईपीएल पर एक रिपोर्ट दी है. मेरे हिसाब से ऐसे छोटे मामले देखना सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था का काम नहीं है. यह एक खेल है, मोटा पैसा लगने की वजह से यह बड़ा हो गया है. जहां भी पैसा होगा, समस्या होगी. ज़्यादा पैसा, ज़्यादा समस्या. अब एक जज ने रिपोर्ट दी है कि इस टीम को बैन करो, इस आदमी को हटाओ. ठीक है, लेकिन यह छोटी बात है. सवाल यह है कि आप क्रिकेट प्रशासन में सिस्टमेटिक चेंज कैसे लाएंगे? इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है. एक आदमी बेटिंग कर रहा है, कुछ ग़लत कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन इससे चीजें ठीक नहीं होने वाली. क्रिकेट बोर्ड एक बेहतरीन खेल संस्था है. इससे बेहतर कोई भी खेल संस्था काम नहीं कर रही है. सही बात है कि हर चीज में सुधार हो सकता है. बीसीसीआई में भी सुधार की ज़रूरत है.

मुझे लगता है कि जस्टिस लोढ़ा को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में बदलाव वाले सुझाव के लिए कहा होगा. मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन यह ज़रूर है कि एक गंभीर कमेटी बने, जो चीजों को क्रम में सजा सके, सुधार सके, भ्रष्टाचार कम कर सके. यही वक्त की ज़रूरत है. अन्यथा कुछ दिनों के लिए कुछ लोगों के नाम उछलने का काम मीडिया में छाया रहेगा और कुछ लोग शर्मिंदा होंगे, लेकिन इस सबसे देश का भला नहीं होने वाला. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतत: छविराम मारा गया-2

अति आत्मविश्वास बना मौत का कारण

छविराम नौ फरवरी से पुन: भूमिगत हो गया. लेकिन अब भी उसे आशा थी कि सतीश अजमानी द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. इसी कारण उसने सामान्य तौर पर गुप्त रखी जाने वाली अपनी गतिविधियां भी गुप्त नहीं रखीं. वह अपने आश्रय–क्षेत्र घिरोर तथा औंछा के बीच निर्द्वंद्व घूमता रहा. उसकी इस बेफिक्री ने भी उसके ख़ात्मे में अपनी भूमिका निभाई. इसमें संदेह नहीं कि छविराम को समाप्त करने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी पुलिस महानिरीक्षक नरेश वर्मा की रणनीति, जिसके तहत उन्होंने चरण सिंह के विश्वासपात्र पुलिस उप–अधीक्षक सुकरमपाल सिंह को उनके साथियों मेघ सिंह राणा और विजय सिंह सहित मैनपुरी भेजा. सुकरमपाल सिंह जाट हैं. उन्होंने आस–पास के ज़िलों में कुछ और जाट इंस्पेक्टर भी बुला लिए. इस क्षेत्र में उनका पहला काम था, धारा 216 में यादवों की गिरफ्तारी रोकना. पुलिस द्वारा निरपराध लोगों की ठुकाई और मार–पीट व घर जलाना भी उन्होंने ही बंद कराया. इसी का नतीजा था कि उन्हें छविराम की गतिविधियों की सूचना देने वाले सटीक मुखबिर मिल सके. दूसरी तरफ़ यह स्थिति थी कि जन–साधारण में मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक कर्मवीर सिंह के लिए निर्णायक रूप से कुछ करना ज़रूरी हो गया था. अत: उन्होंने सुकरमपाल सिंह व युद्धपाल सिंह के साथ बैठकर छविराम को घेरने की योजना बना डाली. उधर छविराम न केवल बेफिक्र था, बल्कि उसे अपने ऊपर अति आत्मविश्वास हो चला था. उसका मानना था कि अख़बारों में छपाने के लिए पुलिस भले ही गोलियां चला ले, लेकिन छविराम से मोर्चा लेने की हिम्मत उसमें नहीं है. वह हरनागरपुर में इस आशय के वक्तव्य भी दे चुका था. लेकिन जब 16 फरवरी को घिरोर क्षेत्र के नयागांव में पुलिस ने उसे घेर लिया, तो उसका यह आत्मविश्वास डगमगा गया, पर साढ़े सात घंटे की गोलीबारी के बाद वह अंतत: बचकर निकल गया. इस मुठभेड़ में छविराम का गोला–बारूद बहुत खर्च हुआ.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

कर्मवीर सिंह व सुकरमपाल सिंह की योजना यह थी कि छविराम को घेरकर घिरोर व औंछा क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वहां वह इतना लोकप्रिय था कि उसे मारना असंभव लग रहा था. लेकिन छविराम को उसके क्षेत्र से निकाल बाहर करना भी आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस जाती थी और लौटकर आ जाती थी. छविराम जैसे ज़मीन में समा गया था. पर छविराम का गिरोह निष्क्रिय नहीं था. 19 फरवरी की रात में बल्लमपुर गांव में छविराम गिरोह के एक सदस्य भूरा ने अपने पड़ोसी मुरारी यादव व उसके बेटे ओम प्रकाश को गोली मार दी. जब उन्हें बचाने मुरारी यादव की पत्नी व उसकी छोटी बेटी आईं, तो भूरा ने उन्हें भी मार दिया तथा मुरारी यादव की बड़ी लड़की ओमवती को लेकर भाग निकला. उसने 16 वर्षीय ओमवती को बरी के नगला में किसी यादव के यहां रखा तथा उसके साथ बलात्कार भी किया. भूरा पहले चोरी करता था. सन् 74 में मुरारी व भूरा का मैनपुरी की एक दुकान से राइफलें चुराने के आरोप में चालान भी हुआ था. पिछले एक साल से मुरारी पुलिस का मुखबिर बन गया था, इसी शक में भूरा ने उसे गोली मारी थी. ओमवती बरी के नगला से छह कोस दूर 22 फरवरी को ले जाई गई, जहां भूरा की छविराम और उसके गिरोह से भेंट हुई. छविराम ने ओमवती के अपहरण के लिए भूरा को बहुत डांटा–फटकारा, पर भूरा ने ओमवती को छोड़ने से इंकार कर दिया. तब छविराम ने उसे मार डालने की धमकी दी. 27 फरवरी को मडमई गांव में एक यज्ञ हुआ, जिसमें छविराम अपने सभी साथियों सहित शामिल हुआ. लेकिन जब पुलिस पहुंची, तब तक वह जा चुका था. वस्तुत: 16 फरवरी की मुठभेड़ के बाद उसका आत्मविश्वास कुछ आहत तो हुआ था, किंतु वह समझ यही रहा था कि यह सब पुलिस की सामान्य गतिविधि है, जिसका उद्देश्य मात्र यह दिखाना है कि पुलिस निष्क्रिय नहीं है. चार दिनों तक उसे रहेरा गांव के आस–पास देखकर भी पुलिस अनदेखा कर गई, इससे उसे निश्चिंत होने में मदद मिली. हालांकि, सच्चाई यह थी कि पुलिस को केवल उसके क्षेत्र का पता था, निश्चित स्थान का नहीं, इसीलिए वे लोग निराश होकर लौट आते थे. 28 फरवरी को बर्नाहर थानाध्यक्ष एपी सिंह को फिर सूचना मिली कि छविराम का गिरोह उनके क्षेत्र में घूम रहा है. उन्होंने इसकी सूचना कर्मवीर सिंह को दी. कर्मवीर सिंह ने सुकरमपाल सिंह,

कर्मवीर सिंह व सुकरमपाल सिंह की योजना यह थी कि छविराम को घेरकर घिरोर व औंछा क्षेत्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वहां वह इतना लोकप्रिय था कि उसे मारना असंभव लग रहा था. लेकिन छविराम को उसके क्षेत्र से निकाल बाहर करना भी आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस जाती थी और लौटकर आ जाती थी. छविराम जैसे ज़मीन में समा गया था. पर छविराम का गिरोह निष्क्रिय नहीं था. 19 फरवरी की रात में बल्लमपुर गांव में छविराम गिरोह के एक सदस्य भूरा ने अपने पड़ोसी मुरारी यादव व उसके बेटे ओम प्रकाश को गोली मार दी.

विजय सिंह, मेघ सिंह तथा ज्ञान सिंह को बुलाकर गहन खोजबीन की योजना बनाई. लगता है, इस समय तक छविराम की अपनी मुखबिर व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी, अन्यथा उसे अवश्य पता चल जाता कि पुलिस उसे ख़त्म करने की अपनी योजना में पूरी तरह गंभीर है. 28 फरवरी और एक मार्च को छविराम छिपा रहा तथा पुलिस उसे तलाश कर लौट आई. दो मार्च को छविराम ने ओमवती से कहा कि वह अपने गांव चली जाए तथा चाचा के यहां रहे, क्योंकि ओमवती इस भाग–दौड़ में बोझ साबित हो रही थी. ओमवती जैसे ही अपने गांव पहुंची कि पुलिस को पता चल गया तथा उसने ओमवती से पूछताछ की. इससे पता चला कि छविराम बरी के नगला के आस–पास है.

कर्मवीर सिंह ने पीएसी के लगभग छह सौ और पुलिस के सौ सिपाहियों के साथ तीन मार्च को छविराम की तलाश शुरू की. मेघ सिंह राणा, ज्ञान सिंह, विजय सिंह तथा कर्मवीर सिंह व सुकरमपाल सिंह के नेतृत्व में चार हिस्सों में बंटे सिपाहियों ने बीस किलोमीटर क्षेत्र को घेर लिया तथा क्रमश: अपना घेरा छोटा करना शुरू किया. मैनपुरी से आगरा जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे चल रहा मेघ सिंह राणा का दल जब ताखा रेलवे स्टेशन के सामने बसे गांव खेरिया के पास पहुंचा, तो उसे गांव में कुछ असामान्य हलचल का आभास हुआ. वस्तुत: उस समय वहां छविराम के पैर छूने की रस्म चल रही थी. जब उसके साथियों ने पुलिस को आते देखा, तो वे दूसरे सिरे से निकल कर पीतेपुर की ओर बढ़े. मेघ सिंह राणा ने तत्काल अपने मैन पैक वायरलेस सेट पर दूसरी टुकड़ियों को इसकी सूचना दी तथा खुद छविराम का पीछा किया. छविराम के दो साथियों ने मेघ सिंह पर गोली चलाकर उन्हें रोका. उस वक्त साढ़े ग्यारह बज रहे थे तथा कर्मवीर सिंह व सुकरमपाल सिंह बर्नाहर पर थे. जब उन्हें छविराम के मुकाम की सूचना मिल गई, तो उन्होंने बाकी टुकड़ियों को भी एक खास बिंदु के इर्द–गिर्द घेरा तंग करने का आदेश दिया. ■ *क्रमश:*

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आप देश के प्रधानमंत्री हैं राज्य के मुख्यमंत्री नहीं

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही एक छोटी चूक हो रही है. देश में मुसलमान हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हों या सिख हों, इन सबके बड़े त्योहारों में शामिल होना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है. अब यहां पर प्रधानमंत्री से एक और चूक होने वाली है. प्रधानमंत्री सिखों के त्योहारों में तो शामिल होंगे, हिंदुओं के त्योहारों में शामिल होंगे, लेकिन ईसाई, पारसी, जैन एवं मुसलमानों के त्योहारों में शामिल नहीं होंगे. मुझे लगता है कि यह ग़लत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने जो मुख्यमंत्री रहते हुए किया, अगर उसी को हम प्रधानमंत्री रहते हुए भी लागू करेंगे, तो हम देश में नए अंतर्विरोधों, नए कंट्राडिक्शन को जन्म देंगे.”

बीती 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना की लंबी–चौड़ी शुरुआत की. विज्ञान भवन में एक और बड़ा जमावड़ा हुआ. इन सारे प्रयासों का सभी को स्वागत करना चाहिए. हम भी स्वागत कर रहे हैं. लेकिन, 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री ने एक और करिश्मा किया. उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इफ्तार पार्टी में जाने से मना कर दिया. साफ़ मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस समय कुछ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ भी करने का अधिकार है. यह सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तब भी वह किसी इफ्तार पार्टी में नहीं गए और न उन्होंने अपने यहां इफ्तार पार्टी दी. इफ्तार पार्टी में मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम, दोनों को आमंत्रित किया जाता है. दरअसल, एक यह प्रतीक है कि हिंदू और मुसलमान साथ में बैठकर खाएं–पीएं और एक–दूसरे से प्यार की बातें करें.

हम बहुत सारे दिन मनाते हैं, जिनका सांकेतिक मतलब होता है. वे चीजें अमल में कितनी आती हैं, कितनी नहीं आतीं, यह बाद की बात है. लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें मनाते हैं. यह ठीक उसी तरह है, जैसे सत्य बोलना आवश्यक है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हम जीवन में कभी सत्य नहीं बोलते और कभी अहिंसा का पालन नहीं करते. इसके बावजूद हम सत्य और अहिंसा का आदर करते हैं और बड़े आदर के साथ इन वाक्यों को दोहराते हैं. हम जब श्मशान घाट जाते हैं, तो हमें अक्सर लगता है कि दो दिन की ज़िंदगी है, क्या किसी से बैर करना, क्या किसी से झगड़ा करना, क्या किसी की बुराई करना, जाना खाली हाथ है. पर जैसे ही हम श्मशान घाट से निकलते हैं, हम रेडियो चला देते हैं और श्मशान घाट में ली हुई प्रतिज्ञा फौरन भूल जाते हैं. और, किसे कैसे परेशान करना है, यह 15 मिनट के भीतर हम सोचने लगते हैं या किससे किस तरीके से बदला निकालना है, यह हम 15 मिनट के भीतर ही सोचने लगते हैं.

रोजा इफ्तार, ईद मिलन, होली मिलन जैसे नाम या अवसर किसी मजहब से नहीं जुड़े हैं. ये एक सम्मान के प्रतीक हैं. अगर मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को नहीं बुलाया, इफ्तार पार्टी नहीं दी, उनके यहां समारोहों में नहीं गए या किसी इफ्तार की दावत में नहीं गए, तो यह गुजरात की परिस्थिति में मान्य हो सकता है. लेकिन, जब व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, तब उसके ऊपर यह ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वह देश में रहने वाले तमाम तबकों को यह भरोसा दे कि उनके लिए प्रधानमंत्री के मन में आदर की भावना है, स्नेह की भावना है और वह उनके धार्मिक त्योहारों एवं रीति–रिवाजों में शामिल होने से परहेज नहीं करते. प्रधानमंत्री होने का मतलब देश में रहने वाले तमाम वर्गों का प्रधानमंत्री होना है. आप हिंदू रीति–रिवाजों को कितना भी मानें, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक है कि उनके रीति–रिवाजों को मानें, जो संख्या में कम हैं, लेकिन आपके देश में रहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं कर रहे हैं. ऐसा न करने से देश के अल्पसंख्यक तबकों में यह संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री के मन में उनके लिए कोई आदर नहीं है.

प्रधानमंत्री को यह बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सम्मान देना उतना ही आवश्यक है, जितना सम्मान लेना. पर जो प्रधानमंत्री सारे देश को मुख्यमंत्री की तरह चला रहा हो, उससे यह अपेक्षा कैसे की जाए? मुख्यमंत्री का पद हथेली की तरह होता है. आप अपनी हथेली देखिए, आपको एक–एक रेखा समझ में आएगी. आप हथेली पलट के देखिए, तो भी आपको एक–एक नस और एक–एक झुर्री नज़र आ जाएगी. लेकिन, यदि आप अपनी पीठ देखना चाहें, पैर का पिछला हिस्सा देखना चाहें, कान का पिछला हिस्सा देखना चाहें या सिर का पिछला हिस्सा देखना चाहें, तो आप नहीं देख सकते. प्रधानमंत्री का पद ऐसा ही है. जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं, तब आपको सारे शरीर को देखना पड़ता है, सिर्फ़ हथेली को नहीं और वह हिस्सा आप नहीं देख सकते. उसे देखने के लिए एक विशेष कौशल की ज़रूरत है, कुछ आईनों की ज़रूरत है, ऐसे साथियों की ज़रूरत है, जो आपको बताएं कि सारे देश में क्या हो रहा है. सारा देश 125 करोड़ लोगों का देश हो जाता है और लगभग 28 से ज़्यादा प्रदेशों का देश हो जाता है.

रोजा इफ्तार, ईद मिलन, होली मिलन जैसे नाम या अवसर किसी मजहब से नहीं जुड़े हैं. ये एक सम्मान के प्रतीक हैं. अगर मुख्यमंत्री रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को नहीं बुलाया, इफ्तार पार्टी नहीं दी, उनके यहां समारोहों में नहीं गए या किसी इफ्तार की दावत में नहीं गए, तो यह गुजरात की परिस्थिति में मान्य हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही एक छोटी चूक हो रही है. देश में मुसलमान हों, ईसाई हों, जैन हों, पारसी हों या सिख हों, इन सबके बड़े त्योहारों में शामिल होना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है. अब यहां पर प्रधानमंत्री से एक और चूक होने वाली है. प्रधानमंत्री सिखों के त्योहारों में तो शामिल होंगे, हिंदुओं के त्योंहारों में शामिल होंगे, लेकिन ईसाई, पारसी, जैन एवं मुसलमानों के त्योहारों में शामिल नहीं होंगे. मुझे लगता है कि यह ग़लत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमने जो मुख्यमंत्री रहते हुए किया, अगर उसी को हम प्रधानमंत्री रहते हुए भी लागू करेंगे, तो हम देश में नए अंतर्विरोधों, नए कंट्राडिक्शन को जन्म देंगे. बहुत सारी चीजें सिर्फ़ प्यार से, अच्छी भाषा से हल हो जाती हैं. लेकिन ग़लत ढंग से कही हुई बात, कटु भाषा में की गई बात मसलों को हल नहीं करती, दिलों को नहीं जोड़ती और प्यार नहीं बढ़ाती, बल्कि दिलों को तोड़ती है और प्यार ख़त्म कर नफरत पैदा करती है. मुझे लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अनुरोध करना चाहिए कि देश में रहने वाले तमाम तबकों के त्योहारों में अगर वह शिरकत करेंगे, तो उनका मान और सम्मान बढ़ेगा ही.

इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी प्रधानमंत्री एक चूक कर रहे हैं. प्रधानमंत्री विरोधी दलों की कोई बैठक नहीं बुला रहे हैं. बहुमत का अहंकार या बहुमत की दबंगई लोकतंत्र में अच्छी नहीं होती. प्रधानमंत्री के पास अभी कम सीटें हैं. राजीव गांधी के पास तो 412 सीटें थीं, लेकिन राजीव गांधी की साख ढाई साल के भीतर गिरने लगी थी. 412 के बहुमत वाली कांग्रेस अपने बहुमत के बोझ को नहीं संभाल पाई. प्रधानमंत्री जी, बहुमत के बोझ को ऐसा लगता है कि आप भी नहीं संभाल पा रहे हैं. आपके पास अगर 440 सीटें होतीं, तो भी लोकतंत्र का सम्मान करना और विरोधी दलों से दो महीने, तीन महीने में एक बार विचार–विमर्श करना लोकतंत्र की मांग है. अगर आप यह करेंगे, तो लगेगा कि आपकी लोकतंत्र में आस्था है. कोई दो राय नहीं है, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है यह मानने में कि आपके मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान है. आप भारत में पैदा हुए, भारत में पैदा हुआ हर शख्स लोकतंत्र का सम्मान करेगा ही, पर उसे व्यक्त करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि उसके मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान है. इसलिए आप भारत में रहने वाले तमाम वर्गों के किसी एक त्योहार में शामिल होइए या उन्हें अपने यहां बुलाइए और विपक्षी दलों को भी अपने यहां आमंत्रित कीजिए, उनसे विचार–विमर्श कीजिए.

इस देश में रहने वाले एक नागरिक के नाते और एक पत्रकार होने के नाते प्रधानमंत्री से यह निवेदन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं. ■

editor@chauthiduniya.com

मोदी जनाधार का सम्मान करते हैं

मोदी की चुप्पी न तो टालमटोल की तरफ़ इशारा करती है और न जवाबदेही से बचने की तरफ़. इन मामलों पर उचित कार्रवाई यह होगी कि जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, उनके विरुद्ध पार्टी की राज्य इकाई अविश्वास प्रस्ताव लाए और तब तक इंतज़ार किया जाए. यही बात सुषमा स्वराज के बारे में भी कही जा सकती है. इस बात की औपचारिक जांच होनी चाहिए कि मामले में उनके हितों का टकराव था या नहीं.

मेघनाद देसाई

संसद का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है. सरकार अपने दूसरे साल में प्रवेश कर चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मित्र देशों और पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए यात्रा कार्यक्रमों में व्यस्त हैं. इन यात्राओं में वह अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं. उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने विदेश नीति को इतने बड़े पैमाने पर और निरंतरता के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया था. लेकिन, उनकी वास्तविक परेशानी उनके अपने घर के अंदर की है. एक तरह से देखा जाए, तो पिछले साल ठीक इसी समय लोगों को जो अपेक्षाएं सरकार से थीं, वे और अधिक वास्तविक हो गई हैं. दरअसल, कुछ लोग यह बताते नहीं थक रहे हैं कि ये अपेक्षाएं अब कम हो गई हैं. विकास दर पिछले पांच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रही है. यहां तक कि यह चीन से भी आगे निकल गई है. महंगाई दर असाधारण रूप से कम रही है. विनिमय दर जस की तस है. डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो गई है. कम बारिश की चिंताएं अब काफी कम हो गई हैं और किसानों की दुर्दशा अब बीती बात होगी. यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ब्याज दर में कटौती करता है, तो यह एक अच्छा क़दम होगा. लेकिन ऐसा नहीं भी हुआ, तो भी निश्चित रूप से उसका झुकाव नीचे की तरफ़ ही होगा.

इन सब तथ्यों के बावजूद सरकार का प्रदर्शन जितना अच्छा होना चाहिए, उतना अच्छा नहीं हुआ. आर्थिक मोर्चे पर अच्छी ख़बर को राजनीतिक मोर्चे की बुरी ख़बरों ने धुंधला कर दिया है. टीवी चैनल के पैनलिस्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों खामोश और निष्क्रिय हो गए हैं? उन्होंने सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह को अभी तक हटाया क्यों नहीं? त्वरित इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके कई कारण हैं. सबसे पहला कारण तो यह है कि इस तरह की बर्ख़ास्तगी कांग्रेस के व्यक्तिवादी नियंत्रण की संस्कृति है. यह वह संस्कृति है, जिसके लोग अभ्यस्त हैं. 1920 में जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी, उसी समय से राजनेता पार्टी से निकाले जाते रहे हैं. चाहे वे जनता द्वारा निर्वाचित रहे हों या फिर कितने ही कद्दावर क्यों न रहे हों. कांग्रेस के प्रतिनिधियों (डेलीगेट्स) के सुभाष चंद्र बोस के प्रति समर्थन के बावजूद गांधी जी ने उन्हें दबा दिया. उसी तरह प्रांतीय कांग्रेस समिति के बहुमत द्वारा सरदार पटेल को नेता चुने जाने के बावजूद गांधी जी ने जवाहर लाल नेहरू को आगे कर दिया. बाद में नेहरू ने पुरुषोत्तम दास टंडन को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया और जेबी कृपलानी की इस आलोचना को नज़रअंदाज़ कर दिया कि यह प्रधानमंत्री की ज़िम्मेदारी है कि वह सरकार का कामकाज चलाने में पार्टी की सहमति लें. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही मामला रहा. सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जल्दबाजी में पद से हटा दिया और पृथ्वीराज चव्हाण को उनकी जगह बैठा दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी.

भाजपा कांग्रेस की तरह नहीं है. उसमें पार्टी की सत्ता नेताओं की क्षेत्रीय लोकप्रियता, आरएसएस से उनके समीकरण और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद–नापसंद के मुताबिक तय होती है. पिछले चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष नेता पद की लड़ाई में एक अनौपचारिक दौड़ जारी थी. आडवाणी, गडकरी, राजनाथ सिंह एवं शिवराज सिंह चौहान इस दौड़ में शामिल थे. इस

भाजपा कांग्रेस की तरह नहीं है. उसमें पार्टी की सत्ता नेताओं की क्षेत्रीय लोकप्रियता, आरएसएस से उनके समीकरण और पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद-नापसंद के मुताबिक तय होती है. पिछले चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष नेता पद की लड़ाई में एक अनौपचारिक दौड़ जारी थी. आडवाणी, गडकरी, राजनाथ सिंह एवं शिवराज सिंह चौहान इस दौड़ में शामिल थे. इस दौड़ में मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन और संघ से अपने संबंधों के कारण कामयाब हुए. यह सच है कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनका आदर करते हैं और उनसे खौफ भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव सीमित है. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में उन्हें नहीं हटा सकते थे, उसी तरह वह वसुंधरा राजे को नहीं हटा सकते.

दौड़ में मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन और संघ से अपने संबंधों के कारण कामयाब हुए. यह सच है कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनका आदर करते हैं और उनसे खौफ भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव सीमित है. जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में उन्हें नहीं हटा सकते थे, उसी तरह वह वसुंधरा राजे को नहीं हटा सकते. मोदी शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं हटा सकते. ऐसा इसलिए है कि वह क्षेत्रीय नेताओं की स्वायत्तता का सम्मान कांग्रेस नेतृत्व से अधिक करते हैं. वह सही मायनों में एक संघवादी (फेडरलिस्ट) हैं. वह राज्यों को केंद्र के समान दर्जा देना चाहते हैं. उन्हें यह भी मालूम है कि तीनों में से किसी भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है. इसलिए संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह किसी मुख्यमंत्री को बर्ख़ास्त कर दें, जिसे पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल हो. कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों को चपरासी की तरह बर्ताव के काबिल समझती है. इसके लिए उसे विधायकों की नहीं, बल्कि परिवार की वैधता चाहिए.

लिहाज़ा, मोदी की चुप्पी न तो टालमटोल की तरफ़ इशारा करती है और न जवाबदेही से बचने की तरफ़. इन मामलों पर उचित कार्रवाई यह होगी कि जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, उनके विरुद्ध पार्टी की राज्य इकाई अविश्वास प्रस्ताव लाए और तब तक इंतज़ार किया जाए. यही बात सुषमा स्वराज के बारे में भी कही जा सकती है. इस बात की औपचारिक जांच होनी चाहिए कि मामले में उनके हितों का टकराव था या नहीं. यह जांच टीवी चैनल की बहस में नहीं होनी चाहिए. इसके लिए उचित यह होगा कि न्यायिक जांच की अनुशंसा की जाए. लेकिन, ऐसा लगता नहीं है कि मामले की जांच कराई जाएगी. यहां अपराध बहुत मामूली था. यहां ब्रिटिश सरकार द्वारा ललित मोदी के लिए यात्रा दस्तावेज़ दिए जाने पर रजामंदी ज़ाहिर की गई थी. ललित मोदी की महत्वहीनता को नरेंद्र मोदी समझते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

डेंगू से जुड़ी कुछ अहम बातें

मोनिशा भटनागर

feedback@chauthiduniya.com

बारिश में जगह–जगह पानी जमा होने के कारण डेंगू फैलने की संभावना ज्यादा होती है. ये तो सभी को पता है कि डेंगू बीमारी मच्छर के काटने से होती है लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि यह बुखार सिर्फ मच्छरों से फैलता है यानि एक मरीज से दूसरे स्वस्थ आदमी को यह बीमारी नहीं हो सकती. दूसरे शब्दों में कहें तो डेंगू संक्रामक बीमारी नहीं है. यह एक वायरल बुखार है, जो 4 प्रकार के डेंगू वायरस (डेन–1, डेन–2, डेन–3, डेन–4) से होता है. डेंगू के बारे में दूसरी अहम बात है कि एडीज इज़िप्टिस नामक जिस मच्छर के काटने से यह बीमारी फैलती है, वह साफ़ पानी में पनपता है. मलेरिया फैलाने वाले मच्छर की तरह गंदे पानी में नहीं. यह मच्छर साफ, इकट्ठे पानी में पनपते हैं, जैसे घर के बाहर पानी की टंकियों या जानवरों की पानी पीने की हौद, कूलर में इकट्ठा पानी, पानी के ड्रम, पुराने ट्यूब या टायरों में इकट्ठा पानी, गमलों में इकट्ठा पानी, फूटे मटके में इकट्ठा पानी आदि. इसलिये ही डेंगू से बचाव के लिए केवल गंदे पानी की साफ–सफाई ही नहीं ज़रूरी बल्कि साफ़ पानी भी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. डेंगू के मच्छर की एक और अहम बात यह है कि यह मच्छर ज्यादा दूर तक उड़ कर नहीं जाता यानि घर या ऑफिस के अन्दर या आसपास ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं. एक और ध्यान देने वाली बात यह है की डेंगू दिन में काटने वाला मच्छर से होता है. यह डेंगू के मच्छर की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है.

ऐसे मच्छर साफ, इकट्ठे पानी में पनपते हैं, जैसे घर के बाहर पानी की टंकियां या जानवरों के पानी पीने की हौद, कूलर में इकट्ठा पानी, पानी के ड्रम, पुराने ट्यूब या टायरों में इकट्ठा पानी, गमलों में इकट्ठा पानी, फूटे मटके में इकट्ठा पानी आदि. इसलिए, डेंगू से बचाव के लिए केवल गंदे पानी की साफ–सफाई ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि साफ़ पानी भी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए.

लक्षण

डेंगू के लक्षण संक्रमित मच्छर के काटने के बाद 4–10 दिन में दिखाई पड़ते हैं. डेंगू के लक्षण फ्लू जैसे लगते हैं और यह 2–7 दिनों के लिए रहता है. डेंगू के शुरुआती लक्षण हैं तेज ठंड लगना, हल्के बुखार से लेकर बहुत तेज़ बुखार होना, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द और आंखों के पीछे तेज दर्द. डेंगू का पता लगा पाना मुश्किल है क्योंकि इसके लक्षण भी काफी हद तक मलेरिया से मिलते हैं लेकिन बदन पर चकत्ते यानि रैशेस डेंगू का खास लक्षण है. अगर बाकी लक्षणों के साथ पूरे शरीर में कही पर भी रैशेस नज़र आएं तो तुरंत डेंगू की जांच करानी चाहिए. इसके अलावा, मांसपेशियों में दर्द, बेचैनी, उल्टियां, लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. साधारणतः डेंगू की शुरुआत 1 से 5 दिनों तक

तेज बुखार व ठंड के साथ होती है. अन्य लक्षण जैसे सिरदर्द, कमर व जोड़ों में दर्द, थकावट और कमजोरी भी डेंगू की ओर इशारा करते हैं. डेंगू का गंभीर रूप डेंगू हेमोरेजिक बुखार के नाम से जाना जाता है. डेंगू हेमोरेजिक बुखार, जो एक संभावित घातक जटिलता है, डेंगू संक्रमण से ही विकसित हो सकता है. इसके लक्षण बुखार, पेट में तेज़ दर्द, लगातार उल्टी होना, खून की उल्टी, मसूढ़ों से खून बहना और सांस लेने में तकलीफ होना है. डेंगू जब गंभीर डेंगू में विकसित होने लगता है तब सबसे क्रिटिकल फेज बीमारी के पहले संकेत दिखने के 3–7 दिन के बाद होता है. ऐसे में बुखार कई बार कम भी हो जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि मरीज़ में सुधार हो रहा है. सीवियर डेंगू का तुरंत और सही इलाज बहुत आवश्यक है, तुरंत मेडिकल हेल्प न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है.

डेंगू के इलाज के लिए कोई टीका या कोई विशिष्ट दवा नहीं है लेकिन जल्दी पता लगने पर और उचित चिकित्सा और देखभाल से डेंगू से होने वाले मृत्यु दर को काफी कम किया जा सकता है. बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल ली जाती है लेकिन इसके अलावा डेंगू का किसी भी तरह का उपचार बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए. डेंगू की ज़रा सी भी आशंका होने पर डॉक्टर से मिलना चाहिए. डेंगू बुखार में अधिक से अधिक पानी व तरल पदार्थ का सेवन करें और पूरा आराम करें. साथ ही ध्यान रहे की डिस्प्रिन और अस्प्रिन जैसी दर्द निवारक दवा का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए, यह घातक हो सकता है. डेंगू से बचाव के लिए हमारी सजगता ही सबसे जरूरी है. डेंगू का वायरस मच्छरों द्वारा संक्रमित होता है इसलिए सबसे अधिक जरूरी है कि मच्छरों को घर में या आसपास बिल्कुल न होने दें. डेंगू से बचाव के लिए मच्छरदानी में सोएं, डेंगू के मरीज को दिन में भी मच्छरदानी में सुलाएं. पूरी बांह के कपड़े पहने, खिड़की और दरवाजे पर मच्छर जाली लगाएं. सबसे ज़रूरी घर में कूलर, गमले, छत, पुराने टायर, टूटे–फूटे बर्तन में पानी जमा न होने दें और अगर कोई पानी से भरी चीज़ घर में हो तो उसका पानी नियमित रूप से बदलते रहें ताकि उसमे मच्छर ना पनपें. डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण पूरी तरह से प्रभावी वेक्टर नियंत्रण के उपायों पर निर्भर करती है.■

रोज़ की सूचनाओं पर भरोसा करते थे कॉनफेडरेट अधिकारी

अरुण तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

रोज़ ओ'नील ग्रीनहाव का नाम अमेरिकी गृह युद्ध में जासूसी करने वाली महिलाओं में अग्रणी रूप से आता है. उन्होंने अमेरिकी संघ से अलग होकर युद्ध छेड़ने वाले सात कॉनफेडरेट राज्यों की तरफ से जासूसी की थी. रोज़ की वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों तक अच्छी पहुंच थी. इस पहुंच का इस्तेमाल उन्होंने अमेरिकी संघ के अधिकारियों से खुफिया सूचनाएं निकलवाकर उसे कॉनफेडरेट प्रशासन तक पहुंचाने में किया. इसके अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति से भी भलिभांति परिचित थीं. रोज़ ने शायद सबसे ज्यादा खुफिया सूचनाएं कॉनफेडेरेट राज्यों तक पहुंचाई थीं. उनकी इस काबिलियत को देखते हुए कॉनफेडेरेट राज्यों की खुफिया एजेंसियों ने रोज़ को अमेरिकी संघ के लगभग सभी राज्यों में चल रहे जासूसी तंत्र का मुखिया बना दिया था. अगर कोई भी सूचना किसी जासूस के पास आती थी, तो वह तभी कॉनफेडरेट राज्यों तक पहुंचती थी जब रोज़ उस सूचना की पुष्टि कर दिया करती थीं. उनकी हैसियत कॉनफेडेरेट महिला जासूसों की पहली पंक्ति में थी.

रोज़ की इच्छा के बारे में कॉनफेडरेट अधिकारियों को जानकारी लगी. उन्होंने गोपनीय सूत्रों के जरिये रोज़ से संपर्क साधा तो रोज़ ने उनके लिए काम करने की हामी भर दी. अमेरिकी संघ के अधिकारियों को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि रोज़ कॉनफेडरेट राज्यों के लिए काम कर रही हैं.

रोज़ का जन्म 1813 में वाशिंगटन के नजदीक मैरीलैंड नामक जगह पर हुआ था. कुछ दस्तावेज रोज़ की उम्र 1817 में होना भी बताते हैं. जब वे छोटी थीं तभी उनके पिता की हत्या कर दी गई. उनकी मां के लाख प्रयास करने के बावजूद भी उनके पिता के कातिलों का पता नहीं लगाया जा सका. पिता की मौत के साथ ही रोज़ और उनकी तीन बहनों पर समय से पहले ही जिम्मेदारी आ गई. पिता की मृत्यु के बाद रोज़ और उनकी बहन को रहने के लिए वाशिंगटन में उनकी एक रिश्तेदार ने बुला लिया. उनकी वो रिश्तेदार वाशिंगटन में एक बोर्डिंग हाउस चलाती थीं. वे काफी रसूखदार महिला थीं और वाशिंगटन के कई अधिकारी और बड़े लोग उनके परिचित थे. रोज़ भी उसी बोर्डिंग हाउस में रहती थीं. रोज़ बहुत खूबसूरत थीं, इस वजह से सभी के आकर्षण का केंद्र हुआ करती थीं. सभी उनकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे. यही समय था जब रोज वाशिंगटन के अधिकारियों के नजदीक आईं. उनकी भी वाशिंगटन के संभ्रांत समाज में पैठ बनने लगी. इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर डॉक्टर और भाषा विज्ञानी रॉबर्ट ग्रीनहाव से हुई. दोनों में प्रेम हुआ और यह रिश्ता शादी तक पहुंचा. इस रिश्ते को वाशिंगटन के संभ्रांत समाज में काफी वाहवाही मिली. दोनों की शादी साल 1835 में हुई. अगले कुछ सालों में रोज़ और रॉबर्ट की जोड़ी वाशिंगटन में बहुत मशहूर हो गई थी. इस दौरान रॉबर्ट की बहन अक्सर घर पर आया करती थीं. उनकी और रोज़ की आपस में बहुत ज्यादा बनती थी. दोनों रिश्तेदार होने के साथ बहुत अच्छे मित्र भी हो गए थे.

सन 1854 में रॉबर्ट की मौत एक दुर्घटना में हो गई. उनकी मौत के बाद रोज़ अकेली हो गईं और ज्यादा दिन नहीं बीते जब अमेरिका में गृह युद्ध की आहटें सुनाई पड़ने लगीं. ऐसा लगने लगा कि देश के टुकड़े होने वाले हैं. ऐसा हुआ भी. सात राज्यों ने खुद अमेरिकी संघ से अलग घोषित कर एक नया राज्य बना लिया. रोज़ वाशिंगटन में रह रहे उन लोगों में शामिल थीं जिन्हें इन राज्यों से सहानुभूति थी. उन्होंने यह बात कई सार्वजनिक जगहों पर भी ज़ाहिर की थी. रोज़ की इच्छा के बारे में कॉनफेडरेट अधिकारियों को जानकारी लगी. उन्होंने गोपनीय सूत्रों के जरिये रोज़ से संपर्क साधा तो रोज़ ने उनके लिए काम करने की हामी भर दी. अमेरिकी संघ के अधिकारियों को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि रोज़ कॉनफेडरेट राज्यों के लिए काम कर रही हैं. रोज़ को जासूस के तौर पर नियुक्त कर दिया गया. रोज़ ने गोपनीय संदेश भेजने के नए तरीके विकसित किए और उसके लिए 26 नए संकेत बनाए जिनके जरिये कॉनफेडरेट अधिकारियों को संदेश भेजे जाते थे और संघ के अधिकारियों को इस बात की भनक भी नहीं लगती थी. रोज ने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए संघ के अधिकारियों की गतिविधियों की ज्यादातर जानकारी कॉनफेडरेट कैंप तक पहुंचाने का काम जारी रखा. उनके इस काम से खुश होकर उन्हें वाशिंगटन के पूरे जासूसी नेटवर्क का जिम्मा सौंप दिया गया.

साल 1961 की 9 और 16 जुलाई को रोज़ ने संघ की कॉनफेडरेट पर हमला करने की गोपनीय सूचना को कॉनफेडरेट जनरल पीजीटी बियूगार्ड तक पहुंचा दिया. संघ की सेना पूरी तैयारी में थी कि वह मेनासास के इस हमले में आसानी से विजय पा जाएगी और वहां कॉनफेडरेट के कब्ज़े को समाप्त कर देगी. लेकिन यह जानकारी पहले ही रोज़ ने लीक कर दी थी इस वजह से कॉनफेडरेट कैंप अपनी पूरी तैयारी कर चुका था. इस युद्ध में संघ की सेना को मुंह की खानी पड़ी. इस युद्ध को फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन कहा जाता है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद कॉनफेडरेट अधिकारी जॉर्डन ने रोज़ को कृतज्ञतापूर्ण एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने रोज़ को कॉनफेडरेट राष्ट्रपति और जनरल की ओर से धन्यवाद दिया था. उन्होंने यह भी लिखा था कि आगे से हम किसी भी तरह की जानकारी के लिए सिर्फ आप पर ही भरोसा करेंगे. हम आपके एहसानमंद हैं. इसके बाद उन्हें विद्रोही राज्यों में रेबेल रोज़ के नाम से ख्याति मिली.

जब खबर फैलने लगी कि इस युद्ध में हार की वजह रोज़ की जासूसी है तो रोज़ ने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया और खुद जासूसी के काम में लगी रहीं. उन्हें यह भय तो सताता रहता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन रोज़ पर तो जैसे कॉनफेडरेट राज्यों को जीत दिलाने का भूत सवार था. इस बीच अमेरिकी अधिकारी एलन पिनकरटन को खफिया विभाग का प्रमुख बना दिया. पद पर नियुक्ति के तुरंत बाद एलन ने इस बात के आदेश दे दिए रोज़ की गिरफ्तारी करने के सुबूत जुटाए जाएं, क्योंकि रोज़ के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सुबूत संघीय अधिकारियों को हाथ नहीं लगा था. जल्द ही अधिकारियों को यह मौका भी मिल गया. रोज़ पर यह आरोप लगाया गया कि उनसे मिलने के लिए कॉनफेडरेट अधिकारी आए हुए थे. रोज़ को उनके घर में ही कैद कर लिया गया. इसी दौरान एलन को यह जानकारी मिली कि अगर रोज़ के घर की तलाशी ली जाए तो वहां से काफी सुबूत हासिल किए जा सकते हैं. एलन ने इसमें देर नहीं लगाई और उनके घर की तलाशी लेने के लिए पहुंचा. रोज़ के घर से जासूसी के काफी दस्तावेज बरामद किए गए. इनमें कई पत्र ऐसे थे जिन्हें कॉनफेडरेट अधिकारी को भेजा गया था. सुबूत मिलने के बाद रोज़ को कारावास में भेज दिया गया. ऐसा बताया जाता है कि रोज़ इकलौती कैदी थीं जो अपनी जेल की खिड़की पर कॉनफेडरेट सरकार झंडा लगाती थीं.

रोज़ के संबंधों का ही प्रभाव था कि जेल में बंद किए जाने के बाद अमेरिकी संघ पर दुनियाभर के कई देशों से दबाव पड़ने लगा. रोज़ को बिना ट्रायल चलाए छोड़ दिया गया लेकिन उन्हें यह हिदायत दी गई कि अब वे कॉनफेडरेट राज्यों में ही रहेंगी. इसके बाद वे वर्जिनिया चली गईं. यहां पहुंचने पर उनका स्वागत करने खुद राष्ट्रपति आए थे और उनका स्वागत एक हीरोइन की तरह किया गया था. इसके बाद रोज़ ने जासूसी का काम जारी रखा. लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को संघ के ही एक हमले में उनकी मौत हो गई. उनके मरने के बाद भी आज लोग उन्हें इन राज्यों में याद करते हैं. रोज़ को ऐसी वीर महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने मन की सुनी और मन की ही की.■

प्रधानमंत्री का मध्य एशिया दौरा

रिश्तों को जोड़ने की कोशिश

मध्य एशिया के देश तेल, सोना, गैस, लोहा, तांबा के साथ विविध प्रकार के कीमती खनिज संपदा से भरपूर हैं. सिर्फ पांच मध्य एशियाई देशों को भारत का निर्यात 60.43 करोड़ डॉलर और आयात 77.57 करोड़ डॉलर है. आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी मध्य एशियाई देशों के दिलों में छोटा भारत बसता है, लेकिन भारत सरकार ने रूस की नाराजगी के डर से इन देशों से जुड़ने का कभी सार्थक प्रयास नहीं किया. हालांकि वैश्विकरण के इस दौर में भारत के लिए इन देशों की अनदेखी करना अब संभव नहीं है. पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के साथ इन देशों के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश के साथ ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया. ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मोदी ने इन देशों से शिक्षा, संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए, उसके दूरगामी परिणाम किस रूप में सामने आएंगे.

राजीव रंजन

फोटो–प्रभात पाण्डेय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य एशिया और रूस का दौरा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक उद्देश्यों को साधने के अलावा कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है. साल 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की जो शुरुआत हुई थी, उस तरफ भारत सरकार का यह पहला कदम था. एशिया का मर्मस्थल समझे जानेवाले उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान की अतिसंवेदनशील भू–राजनीतिक स्थिति से भारत अनजान नहीं है, लेकिन इन देशों के साथ संबंधों को उचित मुकाम पर पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है. रूस और चीन की सरहद को छूनेवाले ये राज्य ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक के सामरिक सरोकारों को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त दुर्लभ खनिज संपदा और तेल–गैस भंडार के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ये देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. सुदूर पूर्वी एशिया और हमेशा अस्थिर रहने वाले पश्चिम एशिया या अरब जगत को जोड़नेवाले इस विस्तारित भू–भाग की अनदेखी हम नहीं कर सकते. इन देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंध नगण्य हैं. इस क्षेत्र से गैरहाजिर रहना भारत के हित में नहीं है. इन देशों में पशुपालन, तकनीकी शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणविक ईंधन जैसे क्षेत्रों में भारत अपार संभावनाएं तलाश सकता है.

भारतीय प्रधानमंत्री की मध्य एशियाई देशों की यात्रा के क्रम में पहला पड़ाव उज्बेकिस्तान था. उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति करिमोव ने कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक सशक्त बनाने का समर्थन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान से यूरेनियम की आपूर्ति संबंधी समझौते को अमल में लाने के लिए जरूरी कदमों के बारे में भी चर्चा की. इस समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किये जा चुके हैं, जिसके तहत उज्बेकिस्तान भारत को 2000 मीट्रिक टन यूरेनियम की सप्लाई करेगा. राष्ट्रपति करिमोव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सम्पर्क बढ़ाने के बारे में चर्चा की. साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के बारे में चर्चा की और उज्बेकिस्तान को उसका सदस्य बनने का प्रस्ताव किया. प्रधानमंत्री ने उज्बेकिस्तान से अश्गाबात समझौते में भारत के सम्मिलित होने के लिए उनका समर्थन मांगा. उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में कई समझौते किए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा का दूसरा पड़ाव कजाकिस्तान रहा. पांच देशों में कजाखस्तान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है. मध्य एशियाई देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कजाखस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा समझौता और यूरेनियम की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट समेत पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इन्होंने आतंकवाद और चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में सक्रियता से सहयोग करने का निर्णय किया. मोदी ने कहा कि भारत और हाइड्रोकार्बन की प्रचुरता वाले कजाकिस्तान के बीच ढांचागत अवरोधों को द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार से दूर करने की दिशा में करीबी सहयोग पर भी सहमति व्यक्त की गई है. कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान किया गया, जिसमें क्षेत्रीय शांति, कनेक्टिविटी, समन्वय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शामिल है. दोनों देशों के बीच सामरिक गठजोड़ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण आयाम है. रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच जो सहमति बनी है, उससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का दायरा और व्यापक होगा, जिसमें नियमित आदान–प्रदान यात्राएं, विचार–विमर्श, सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग, संयुक्त अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सहयोग, विशेष बलों का आदान प्रदान शामिल है.

भारतीय पीएम की यात्रा का तीसरा पड़ाव तुर्कमेनिस्तान था. भारतीय प्रधानमंत्री और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहमदोव के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति से तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की वकालत की है. आतंकवाद, संगठित अपराध और गैर कानूनी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कदम उठाने का संकल्प व्यक्त किया गया. दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर दस्तखत किए गए, वे इस प्रकार हैं. भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और तुर्कमेनिस्तान की सरकारी कंपनी तुर्कमेनहिमिया के बीच सहमति पत्र पर समझौता हुआ. भारतीय गणराज्य के विदेश मंत्रालय के तहत विदेश सेवा संस्थान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय के तहत अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान के बीच सहमति पत्र पर बात बनी. भारतीय गणराज्य के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय तथा तुर्कमेनिस्तान की खेल संबंधी सरकारी समिति के बीच खेल के क्षेत्र में समझौता हुआ. भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच 2015–17 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम होगा. दोनों देशों के बीच योग और पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में सहयोग का सहमति पत्र जारी हुआ. भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के साथ–साथ दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग का समझौता भी हुआ.

भारत के पीएम का चौथा पड़ाव किर्गिस्तान था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अलमाजबेक अतमबायेव के साथ चार महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए. इनमें रक्षा सहयोग बढ़ाना तथा चुनाव के क्षेत्र में एकसाथ काम करने से संबंधित समझौता भी शामिल है. दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित पड़ोसी की जरूरत है. भारत और किर्गिस्तान दोनों ही देश आतंकवाद से परेशान हैं, इसलिए दोनों ही देश आतंकवाद के खिलाफ आर–पार की लड़ाई चाहते हैं. इसे देखते हुए रक्षा समझौते के तहत रक्षा, सुरक्षा, सैन्य शिक्षण तथा प्रशिक्षण में किया जाएगा.

सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, अनुभवों तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान, सैन्य निर्देश तथा पर्यवेक्षण का आदान–प्रदान किया जाएगा. दोनों देशों की सेनाओं के बीच समय–समय पर संयुक्त अभ्यास होते रहे हैं, जिसे सालाना करने का फैसला किया गया है. मोदी ने निर्वाचन आयोगों के बीच सहयोग समझौते पर भी खुशी जाहिर की और कहा कि वह चाहते हैं कि किर्गिस्तान का एक संसदीय दल भारत का दौरा करे. तीसरा समझौता किर्गिस्तान के आर्थिक मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन कॉर्पोरेशन के बीच हुआ, जिसके तहत मानकीकरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. चौथा समझौता संस्कृति को लेकर किया गया है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किया जाएगा. लोक कला, नाटक तथा युवा महोत्सव के लिए एक संस्था स्थापित किया जाएगा.

मोदी अपनी यात्रा के क्रम में आखिर में ताजिकिस्तान पहुंचे. पीएम मोदी की अगुवाई में ताजिकिस्तान से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई. पीएम मोदी ने कहा हम ताजिकिस्तान से रक्षा एवं पर्यटन संबंध को और मजबूत करने के लिए कृतसंकल्प हैं. पीएम ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं. उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी हमारे बीच व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का कद बढ़ा है और मध्य एशिया को हम अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे हैं. इससे इस सोच को बल मिलता है कि भारत एशिया का केंद्र बने, तभी इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता और शांति आएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

ब्रिक्स में भारत

7 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (2015) रूस के उफा में 8–9 जुलाई 2015 को संपन्न हुआ. ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं. वैश्विक भू राजनीति में, ब्रिक्स के पांच देशों के पास दुनिया की आबादी का 40 प्रतिशत और विश्व का एक चौथाई भूभाग है. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स के पांच देशों का 40 प्रतिशत हिस्सा शामिल है. अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में ब्रिक्स एक ऐसा संगठन बन चुका है, जिसके नतीजे बहुत जल्द दिखने लगे हैं. यह संगठन न केवल निर्णय ले रहा है, बल्कि उसको लागू भी कर रहा है. इसी क्रम में न्यू डेवलपमेंट बैंक की नींव भी रखी गई. ब्रिक्स बैंक (न्यू डेवलपमेंट बैंक) में 18 अरब डॉलर का भी भारत योगदान देगा. यह बैंक 100 अरब डॉलर के साथ शुरू हो रहा है. इस न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) की स्थापना ब्रिक्स के ही पांच देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साऊथ अफ्रीका) ने की है. इस बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के प्रतिष्ठित बैंक के पूर्व चेयरमैन रहे केवी कामथ को बनाया गया है. यह बैंक पांच उभरते बाजारों के बीच वित्त और विकास, दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गठित किया गया है. हालांकि, यह गैर–ब्रिक्स देशों की भी मदद करेगा और इसे विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. 7वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ ने भाग लिया. सम्मेलन के एजेंडे में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे शामिल रहे, लेकिन मुख्य बल आर्थिक सहयोग पर रहा. इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच बड़े प्रस्ताव रखकर भारत की स्थिति और मजबूत की. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच जलवायु और खेती के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हम सभी को इन दिशाओं में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में जलवायु परिवर्तन इस समूचे विश्व के सामने एक चिंता का विषय बना हुआ है. मोदी ने कृषि की महता पर जोर देते हुए ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोलने की भी बात कही. ब्रिक्स ट्रेड फेयर पर भी जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें आपस में सांस्कृतिक आदान–प्रदान के बारे में भी सोचना चाहिए. भारत ने साल में एक बार ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

शंघाई सहयोग संगठन और भारत

शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी. इस संगठन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद व मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लड़ाई और आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है. शंघाई सहयोग संगठन का सालाना सम्मेलन उफा में हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की. इस संगठन को नेटो के समतुल्य माना जाता है. शंघाई सहयोग संगठन के छह सदस्य देशों का भूभाग यूरोशिया का 60 प्रतिशत है. यहां दुनिया के एक चौथाई लोग रहते हैं. मोदी की विदेश यात्रा के दौरान इस बार के संघाई सहयोग सम्मेलन में भारत के लिए एक अच्छी बात यह हुई कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेश में भारत दस साल से पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ, लेकिन इस बार हम सदस्य देश बनकर लौटे. भारत अगले साल तक कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तकनीकी रूप से इस संगठन का पूर्ण सदस्य बन जाएगा. बीजिंग आधारित इस संगठन के अभी चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सदस्य हैं. हालांकि इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर मध्य एशिया के देश भारत के लिए जमीन क्यों तैयार करेंगे? इसका ठोस जवाब यह हो सकता है कि जमीनी क्षेत्रों से घिरे इसके देशों को भारत हिंद महासागर में अवसर दे सकता है.

एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान–भक्ति का प्रवचन दे रहे थे. तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता, हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराये और उन्होंने एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया.

बाबा की भक्ति का आधार ही श्रद्धा और सबूरी है

चौथी दुनिया ब्यूरो

आध्यात्मिक सत्यता एक अलौकिक अनुभूति

आध्यात्मिक सत्यता वह नहीं है, सामान्यत: जो हम समझते हैं. धार्मिक मार्ग में चलते समय लोग अपने छोटे–मोटे अनुभवों, रोमांच, स्वप्न, भावावेश, हृदय को विगलन आदि को आध्यात्मिक सत्यता की पहचान मान बैठते हैं, जबकि वस्तुत: ऐसा नहीं है. आध्यात्मिक अनुभव सभी को होता है, पर सबको अपने स्तर के अनुसार आध्यात्मिक अनुभव होता रहता है. जैसे–जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता जाता है, वह स्तर–दर–स्तर आगे बढ़ता जाता है. इस प्रकार स्तरीभूत होता हुआ वह परम आध्यात्मिक सत्यता का अनुभव करने लगता है. जब परम आध्यात्मिक चेतना के शीर्ष स्थान में ईश्वर एक सत्यता के रूप में खड़े हो जाते हैं, वही असली आध्यात्मिक सत्यता एक अवर्णनीय, अलौकिक परम अनुभूति है, जिसकी अनुभव किसी विरले को होता है.

परम आध्यात्मिक सत्यता किसी विरले में ही क्यो होती है?

वैसे तो आध्यात्मिक सत्यता का अनुभव हर व्यक्ति को हो सकता है, पर उसे धारण करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती. आध्यात्मिक सत्यता या अनुभव ईश्वर कृपा से गुरु के माध्यम से कृपा स्वरूप ऊपर से आता है. उसे धारण करने के लिए पात्र में पात्रता एवं शक्ति होनी चाहिए वह सबमें जागृत नहीं होती और अगर जागृत भी हो तो भिन्न–भिन्न स्तर की होती है. इसके लिए कई जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है. कोई सोचे कि मंदिरों में रो लेने से या भावनाओं का प्रदर्शन करने से आध्यात्मिक सत्यता आ जाएगी, तो वह एक मानसिक भ्रम है. इसके लिए मानसिक स्थिरता और एकाग्रता परम आवश्यक है. साथ ही इस अनुभव के लिए सद्गुरु की अनुकम्पा एवं आध्यात्मिक साधक में ठोस आधार भूमि दोनों आवश्यक हैं. यदि मिट्टी ही सही नहीं है, वह ठीक से तैयार नहीं है, तो बीज बोने से क्या लाभ होगा? इस मिट्टी के तैयार होने में कई–कई जन्म लग जाते हैं. इस प्रक्रिया को सामान्यत: साधना कहते हैं. अगर आधारभूमि में सुदृढ़ता नहीं होगी, तो कुछ बीज अंकुरित होने पर भी बड़ा पेड़ नहीं बन सकते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि कमजोर आधार होने पर थोड़ा सा भी दिव्य अनुभव लोगों को पागल बना देता है. कई लोग तो भ्रमित या मूर्क्षित हो जाते हैं. कुछ लोग समझते हैं कि वह आध्यात्मिक उपलब्धि के शिखर पर पहुंच चुके हैं.

सत्यता को ग्रहण अथवा धारण करने योग्य बनने के लिए क्या प्रयास करें?

सबसे अच्छा है कि अपनी सरलता एवं सहजता को बनाए रखें और अनावश्यक सांसारिक बातों से अपनी शक्ति को बचाए रखें. साथ ही अन्त:करण में अपने गुरु को ही धारण करें. जब व्यक्ति गुरु को ही धारण कर लेगा तो उसके अंदर गुरुभाव जागृत होगा और स्वयमेव सरल एवं विनम्र हो जाएगा. इस प्रकार सरल होकर सहनशीलता एवं अपनी–कार्यक्षमता का विकास करते हुए वह गुरु–कृपा से सत्यता को धारण करने योग्य बन जाता है.

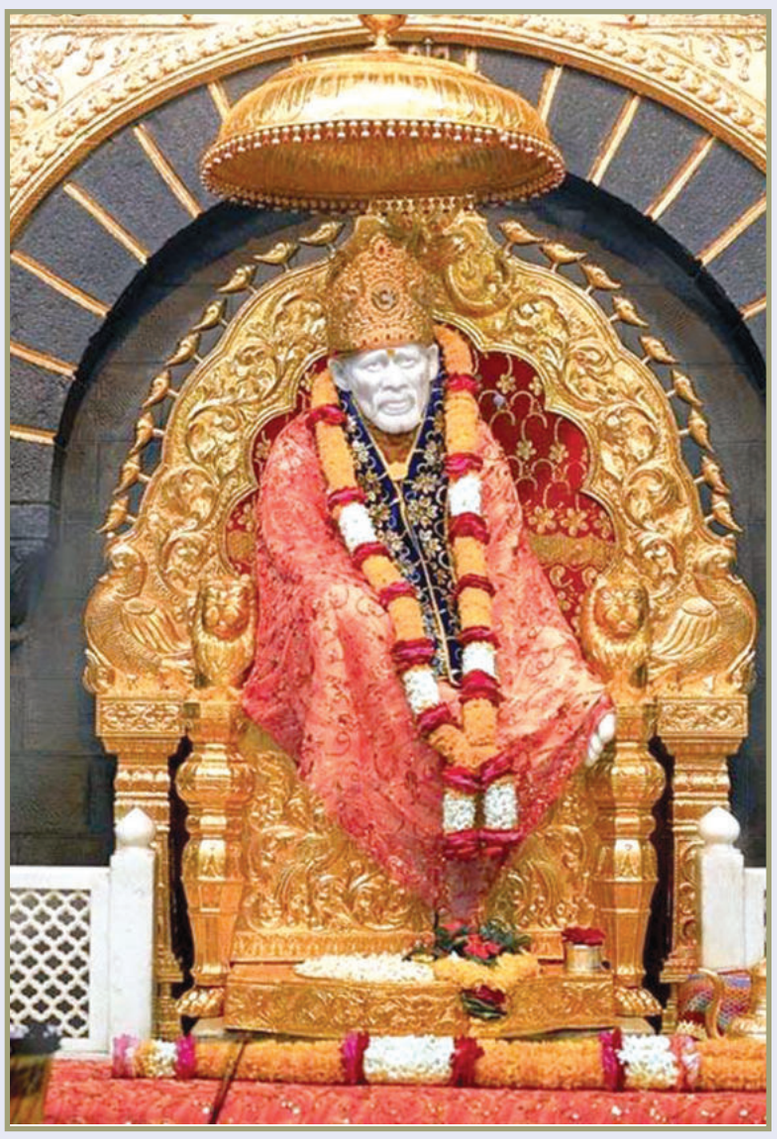

आप कहते हैं कि सत्यता के आगे असहाय हो जाओ. इसका क्या अर्थ है?

सत्यता के आगे असहाय होने का अर्थ है कि ईश्वर ही मूल सत्य हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है. अत: इस संबंध में बिना कोई प्रश्न किए उसी धारा में बहना, सत्यता के आगे असहाय होना है. इस प्रकार की असहायता अहंशून्यता को दर्शाती है. बाबा की भक्ति का आधार ही श्रद्धा और सबूरी है. श्रद्धा और सबूरी का ही चरम–रूप सत्य के आगे असहाय होना है. इसी को रज़ा कहते हैं. जो व्यक्ति सत्य के आगे असहाय होगा, भगवान उसके सहायक होंगे और वह फिर किसी और के आगे असहाय न होगा.

ईश्वरीय आनंद : एक आत्मानुभूति

ईश्वरीय आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

ईश्वरीय आनंन ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया और दूसरे को वह अनुभव हो जाएगा. इसके लिए स्वयं यत्न करना पड़ता है. सासांरिक जीवन व्यतीत करते हुए यह स्थिति मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के सदृश है. जैसे छत्ते से शहद निकालने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है–पहले सूखी लकड़ी को जलाकर धुआं उत्पन्न करना होता है. मधुमक्खियों को भगाना होता है, तब जाकर कहीं शहद प्राप्त कर पाते हैं. उसी प्रकार आध्यात्म की दिशा में भी पहले स्वयं को लकड़ी समान बनाना होता है– अर्थात कामना, वासना आदि को सुखा देना पड़ता है. उसके बाद उसे ज्ञानाग्नि में जलाना होता है. उस ज्ञानाग्नि में जब क्रोध, मद, लाभ मोह आदि विकार पूर्णत: जल जाते हैं, तब भक्ति का धुआं उठता है. यह सांसारिक माया हमारे प्रारब्ध कर्म के पाप, मनोविकार आदि मधुमक्खियों की भांति हैं. ज्ञानाग्नि एवं तपाग्नि से माया–रूपी बाधाएं हट जाती हैं और ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है. इस दिशा में यदि व्यक्ति सही मार्ग से नहीं जाएगा, तो सांसारिक मायारूपी मधुमक्खियां उसे डंक मारती रहेंगी. जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति सदैव पीड़ित होता रहेगा और अलौकिक आनंद के अनुभव से वंचित रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सिर्फ मैगी ही नहीं, सभी फास्ट फूड की जांच हो

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्वों की उपस्थिति के कारण मैंगी की बिक्री पर पूरे देश में रोक लगा दी गई है. भारतीय खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता प्राधिकरण ने ही खुलासा किया था कि नई पीढ़ी जिस मैगी कि दीवानी है, उसमें हानिकारक तत्वों की उपस्थिति मानक से कई गुना अधिक है. प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ मैगी ही हानिकारक खाद्य पदार्थ है. प्राधिकरण के अनुसार देश में कई सौ ऐसे फास्ट या जंक फूड हैं, जिनमें मिलावट होने का शक है. कुछ खाद्य पदार्थ तो बिना सरकारी अनुमति के ही बेचे जा रहे हैं. देश में सिर्फ डिब्बा बंद उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोग शालाओं की संख्या बढ़ाकर अन्य सभी हानिकारक खाद्य व पेय पदार्थों की जांच कराई जाए.

–राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

धोखेबाज पाकिस्तान

पाकिस्तान अपनी बात से एक बार नहीं कई बार पलट चुका है. अब तो भारत सरकार को पाकिस्तान पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए. पाकिस्तान में बस नाम का लोकतंत्र है, क्योंकि वहां पर जनता द्वारा चुनी सरकार का राज नहीं चलता है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना का पाकिस्तान की सरकार पर कंट्रोल है, उन्हीं के इशारे पर सरकार चलती है. कुछ दिनों पहले रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगार जकी–उर–रहमान लखवी के आवाज का सैंपल देने के लिए राजी हो गया था. लेकिन वह अपने ही बातों से दो दिन बाद पलट गया. पाकिस्तान के राष्ट्री सुरक्षा सलाहकार एवं विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जब तक कश्मीर एंजेंडे में नहीं होगा कोई वार्ता नहीं होगी. और साथ ही उसने लखवी के आवाज का सैंपल देने से भी मना कर दिया. अब भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर देनी चाहिए और सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है.

–रमाशंकर तिवारी, बक्सर, बिहार.

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं पर विपक्ष हल्ला मचाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी की विदेश यात्राएं भारत के लिए फायदेमंद है. प्रधानंमत्री नरेन्द्र मोदी 20 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और अभी हाल ही में उन्होंने पांच देशों की यात्रा से लौटे हैं. प्रधानमंत्री की जिस देश की यात्रा पर जाते हैं, उन देशों से भारत का रिश्ता मजबूत होता है, जो देश के लिए अच्छी बात है. भारत ने कजाकिस्तान के साथ पांच हजार टन यूरेनियम व गैस उत्खलन का समझौता किया है. इससे भारत परमाणु बिजली उत्पादन और अधिक कर पाएगा. रेल परियोजना के लिए रूस से भी समझौता हुआ है. मोदी की विदेश यात्रा से देश को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा.

–हरनीत सिंह भसीन, रोहिणी, दिल्ली.

जामिया हमदर्द को बचाए सरकार

कवर स्टोरी–जामिया हमदर्द को बर्बाद करने की साजिश(13 जुलाई –19 जुलाई 2015) पढ़ा. डॉ. क़मर तबरेज़ की द्वारा लिखी गई कवर स्टोरी काफी विचारोत्तेजक है. चौथी दुनिया ने पहले जामिया हमदर्द में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. ग़ैर–क़ानूनी गतिविधियों की वजह से जामिया हमदर्द आज एक अवैध यूनिवर्सिटी बनकर रह गई है. चौथी दुनिया अखबार ने एक बार फिर नए तथ्यों के साथ जामिया हमदर्द के भ्रष्टाचार को उठाया है और जनता के सामने लाया है. अब सरकार एनडीए की है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुद आगे आना चाहिए और जामिया हमदर्द को बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह मामला छात्रो के भविष्य से जुड़ा हुआ है.

–नवनीत भारद्वाज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

उम्मीदें न टूटने पाएं

जब तोप मुकाबिल हो–प्रधानमंत्री जी देश की उम्मीदें न टूटने पाएं(13 जुलाई –19 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि प्रधानंत्री जी देश की उम्मीदें न टूटने पाए, क्योंकि देश को आपसे बहुत उम्मीदे हैं. देश की जनता आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है कि आप उनके अच्छे दिन लाएंगे और उनके दुखों को दूर करेंगे. अगर उनका भरोसा आपसे टूट गया, तो फिर जनता किसी राजनेता पर विश्वास नहीं करेगी. देश की जनता ने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और लूट से तंग आकर आपको चुना था. प्रधनामंत्री जी देश के लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए.

–रघुवीर सिन्हा, दरभंगा, बिहार.

सरकार और विपक्ष दोनों अपना कर्तव्य निभाएं

मैं चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं और हर सप्ताह चौथी दुनिया समाचार पत्र का बेसब्री से इंतजार रहता है. चौथी दुनिया हमेशा तथ्यों आधारित और सच्ची खबरें प्रकाशित करता है. इसमें प्रकाशित सभी आलेख बेहद प्रभावित करने वाले होते हैं. इसमें प्रकाशित आलेख–विपक्ष को जिम्मेदार और सरकार को उत्तरदायी होना चाहिएं(13 जुलाई –19 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावति किया. कमल मोरारका ने सही कहा है कि विपक्ष को जिम्मेदार और सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए. लेकिम मौजूदा दौर में न ही सरकार अपना दायित्व निभा रही है और न विपक्ष जिम्मेदारी निभा रहा है.

–कमलेश राय, गोरखपुर, बिहार.

भगवान और भक्त

चौथी दुनिया ब्यूरो

तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक प्रसिद्ध संत हुए. कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे. बाल–काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया तो वे उसे लेकर मंदिर पहुंचे और उनके हठ के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा.

एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान–भक्ति का प्रवचन दे रहे थे. तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता, हम कैसे मान लें कि वो सचमुच है और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराये और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया.

शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया. वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का प्रश्न से क्या सम्बन्ध, तभी संत नामदेव ने पुन: उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डाल कर मिला दो. शिष्य ने ठीक वैसा ही किया. संत बोले, बताइये, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिए. ठीक है!, संत ने पुछा. अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? जी, एक शिष्य पानी चखते हुए बोला. अच्छा, संत ने निर्देश दिया, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो. कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बन कर उड़ गया, तो संत ने पुन: शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पुछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? एक शिष्य बोला, जी, हमें नमक के कण दिख रहे हैं. संत मुस्कुराये और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाये पर उसे देख नहीं पाये उसी प्रकार इस जग में तुम्हे ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो. और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बन कर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

बेस्टसेलर की बिक्री पर विवाद

अनंत विजय

शिवा ट्राएलॉजी लिखकर लेखन की दुनिया में अपनी पहचान और धमक कायम करने वाले अंग्रेजी के बेस्टसेलर लेखक अमिष त्रिपाठी की नई किताब–सिआॅन ऑफ इच्छवाकु को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. विवाद किताब को लेकर नहीं, किताब के चरित्र को लेकर नहीं, किताब के कथानक को लेकर नहीं, बल्कि उसके बेचे जाने के करार को लेकर हुआ है. विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा. इस किताब के प्रकाशक वेस्टलैंड ने फ्लिपकार्ट पर कॉपीराइट और आईटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रकाशक का आरोप है कि बगैर उसकी इजाजत के फ्लिपकार्ट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमिष का नया उपन्यास बेच रहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में फ्लिपकार्ट को नोटिस भेजकर चार अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है. फ्लिपकार्ट का तर्क है कि वह सिर्फ़ ग्राहकों और विक्रेता को खरीद–फरोख्त के लिए मंच मुहैया कराता है और अगर कोई पुस्तक विक्रेता उसके मंच पर किताबें बेचना चाहता है, तो वह उसे रोक नहीं सकता है. दरअसल, अमेजन ने अमिष त्रिपाठी और उनके प्रकाशक वेस्टलैंड के साथ उनकी इस किताब को बेचने का एक्सक्लूसिव करार कर रखा है. आईपीएल के मैचों के दौरान अमेजन ने अमिष त्रिपाठी की इस किताब को लेकर टीवी पर आक्रामक तरीके से प्रचार किया था, मार्केटिंग की थी, लेकिन जब किताब बिक्री के लिए उपलब्ध हुई, तो वह एमेजन के अलावा फ्लिपकार्ट पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध थी. दरअसल, अगर हम देखें, तो हाल के दिनों में अंग्रेजी के बेस्टसेलर लेखकों या फिर मशहूर शख्सियतों की किताबों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री को लेकर विवाद होते रहे हैं. चंद महीने पहले जो तर्क अमेजन दे रहा था, वही तर्क अब फ्लिपकार्ट दे रहा है. इसी स्तंभ में चेतन भगत की किताब– हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर उठे विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई थी. हाफ गर्लफ्रेंड के लिए उसके प्रकाशक ने ऑनलाइन वेबसाइट फ्लिपकार्ट से समझौता किया था. उस करार के मुताबिक, प्रकाशक ने फ्लिपकार्ट को यह अधिकार दिया था कि पहले कुछ दिनों तक चेतन भगत की किताब सिर्फ़ फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन बुक स्टोर पर ही मौजूद रहेगी. बदले में फ्लिपकार्ट ने भी प्रकाशक को एकमुश्त साढ़े सात लाख प्रतियों का ऑर्डर दिया था. चेतन भगत के उपन्यास की प्री–बुकिंग जमकर हुई. इस एक्सक्लूसिव करार की वजह

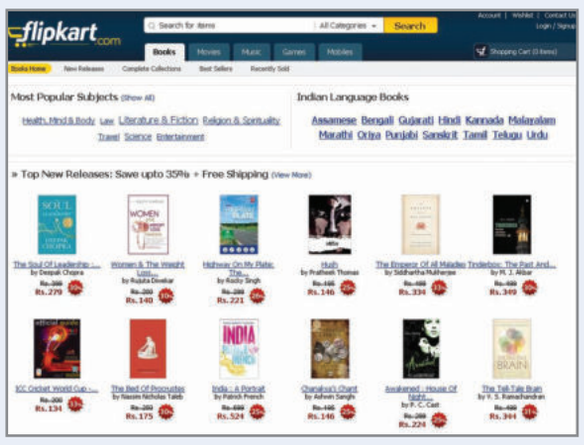

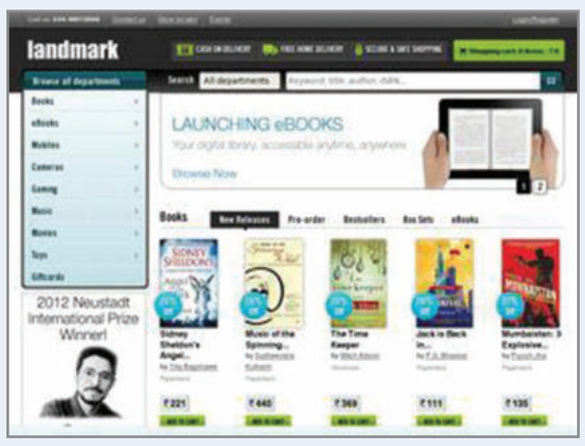

से भारत में चेतन के लाखों प्रशंसकों ने फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन स्टोर पर जाकर किताब खरीदी थी. लेकिन, उस वक्त अमेजन ने भी कुछ इसी तरह का तर्क दिया था कि उसकी कंपनी तो विक्रेता और क्रेता के बीच मंच प्रदान करती है, लिहाजा वह किसी को चेतन की किताब बेचने से रोक नहीं सकती. उस वक्त भी चेतन की किताब के प्रकाशक और अमेजन के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद यह स्थिति भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब–द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स को लेकर भी सामने आई. जिस प्रकाशक ने चेतन भगत की किताब की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया था, उसी ने प्रणब मुखर्जी की किताब के लिए अमेजन से समझौता किया. उस करार के मुताबिक, किताब जारी होने के इक्कीस दिनों तक यह सिर्फ़ अमेजन पर उपलब्ध रहनी थी. मतलब यह कि इक्कीस दिनों तक पाठक प्रणब मुखर्जी की यह किताब एक्सक्लूसिव तौर पर इसी वेबसाइट से खरीद सकता था. उसके बाद यह देश भर के पुस्तक विक्रेताओं के पास पहुंचेगी. इसका नतीजा यह हुआ था कि प्री–बुकिंग के दौर में ही महामहिम की किताब लोकप्रियता के लिहाज से चेतन भगत और सचिन तेंदुलकर की किताब के बाद तीसरे पायदान पर पहुंच गई थी. तब भी इस तरह के सवाल उठे थे. ऑनलाइन बिक्री को लेकर अभी हमारे देश में मौजूद नियम–क़ानूनों में कई सुराख हैं, जिनका फ़ायदा इस तरह की कंपनियां उठाती रही हैं और मामले अदालतों में जाते रहे हैं. किताबों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर तो हाल के दिनों में तनातनी काफी बढ़ी है. भारत में किताबों की दुकानें कम होने की वजह से किताबों की ऑनलाइन बिक्री खूब होती है. आनलाइन कंपनियों के खर्च भी कम होते हैं, लिहाजा वे किताबों की दुकानों की तुलना में पाठकों को आकर्षक छूट भी देती हैं.

किताबों के मूल्य भी बिक्री या प्री–बुकिंग के हिसाब से तय किए जाते हैं. जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब की प्री–बुकिंग शुरू हुई थी, तो उस पर छूट कम थी, लेकिन जैसे–जैसे किताब रिलीज होने की तारीख पास आने लगी, तो ऑनलाइन स्टोर ने उसके मूल्य में भी कमी करनी शुरू कर दी थी, ताकि पाठकों को आकर्षित किया जा सके. किताब पर छपे मूल्य 595 रुपये के बजाय प्री–बुकिंग में उसका मूल्य 446 रुपये रखा गया था. रिलीज वाले दिन इस किताब का मूल्य घटाकर 399 रुपये कर दिया गया. यह बिक्री का अपना गणित है और मुनाफ़े का अर्थशास्त्र भी. किताबों की ऑनलाइन खरीद–बिक्री का एक और भी पक्ष है. इस तरह के करार से किताबें भी वहां बिक्री के लिए पहले उपलब्ध होती हैं और बेवसाइट्स को वहां हिट करने वाले एकल ग्राहकों की वजह से हिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं. ऑनलाइन कंपनियों के लिए हिट्स का खासा महत्व है और कंपनी के वैल्यूएशन से लेकर फंडिंग तक में इस आंकड़े का इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से भी वहां रिटेल खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है. कोई भी ग्राहक किसी भी चर्चित किताब की सिर्फ़ एक ही प्रति खरीद सकता है. अगर किसी को दो या उससे अधिक प्रतियां चाहिए, तो उसे उतने ही ग्राहक प्रोफाइल या एकाउंट बनाने होंगे. यह बाज़ार में थोक बिक्री के आसन्न ख़तरे के मद्देनज़र किया गया है. इससे दो फ़ायदे होते हैं. पहला तो यह कि किताबों की बिक्री बढ़ती है और दूसरा यह कि ऑनलाइन स्टोर के मार्फत किताबों की दुकान तक चर्चित कृतियों के पहुंचने पर रोक लगती है.

दरअसल, हमारे देश में ऑनलाइन बिक्री के लिए अभी तक कोई तय प्रक्रिया नहीं है. बीती 10 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने केंद्र सरकार के सात विभागों और फ्लिपकार्ट एवं अमेजन के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बैठक की. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बाबत राज्यों की एक अहम बैठक बुलाई.

उम्मीद है कि ई कॉमर्स को लेकर ठोस दिशा निर्देश तय होने के बाद इस तरह के विवाद नहीं उठेंगे. अब अगर हम देखें, तो ऑनलाइन बुक स्टोर्स पर बढ़ती ग्राहक संख्या और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैट्जी से किताबों की दुकानों की बिक्री पर असर पड़ने लगा है. भारत में कम हो रही किताबों की दुकानों के लिए बिक्री का यह नया प्लेटफॉर्म और एक्सक्लूसिव करार एक गंभीर चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है. बदलाव की इस बयार में ऑनलाइन स्टोर्स की एक्सक्लूसिविटी पुस्तकों की दुकान में पूंजी लगाने वालों को भी हतोत्साहित कर रही है. चेतन और प्रणब मुखर्जी की किताबों की रिलीज के वक्त देश के कई बुक स्टोर्स ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और ऐसा करने वाले प्रकाशकों को उनकी अन्य किताबें न बेचने की धमकी दी थी. उनका तर्क था कि ऑनलाइन कंपनियों के साथ करार करके प्रकाशक पाठकों के साथ छल करते हैं. उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कोई प्रकाशक बेस्टसेलर के लिए ऑनलाइन बुक स्टोर का चुनाव करता है, तो उसे फिर सारी किताबें वहीं बेचनी चाहिए. यह नहीं हो सकता है कि चर्चित शख्सियतों एवं लेखकों की किताबें ऑनलाइन बेची जाएं और कम चर्चित एवं गंभीर किताबें दुकानों के माध्यम से बेची जाएं.

कई पुस्तक विक्रेताओं ने प्रकाशकों को पत्र लिखकर विरोध जताया था और भविष्य में ऐसा न करने की सलाह दी थी. अमिष त्रिपाठी और चेतन भगत की किताबों की मार्केटिंग के बरक्श अगर हम हिंदी प्रकाशन की दुनिया को देखें, तो अब हालात कुछ उत्साहजनक नज़र आने लगे हैं. हिंदी के प्रकाशक अब बाज़ार का इस्तेमाल करने पर विचार करने लगे हैं. कइयों ने अपनी किताबें ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध भी करा दी हैं, लेकिन हिंदी के प्रकाशकों का इन ऑनलाइन बुक स्टोर्स से उस तरह से राफ्ता कायम नहीं हो सका है, जैसा होना चाहिए. हिंदी के प्रकाशकों को बाज़ार के इस खेल में पूरी तरह से शामिल होना पड़ेगा. यह धारणा ग़लत है कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की किताबें नहीं बिकती हैं. एक अनुमान के मुताबिक, चेतन भगत और अमिष त्रिपाठी की किताबों के हिंदी अनुवाद की बिक्री कुल बिक्री का पैंतीस फ़ीसद रही है. इंटरनेट के फैलाव और सरकार के डिजिटल इंडिया स्कीम को प्राथमिकता के बाद इंटरनेट का घनत्व बढ़ेगा. जैसे–जैसे देश में इंटरनेट का फैलाव होगा, ऑनलाइन बिक्री के प्लेटफॉर्म की अहमियत बढ़ती जाएगी.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कला प्रदर्शनी

आम जीवन पर चुटीले व्यंग्य

अरुण तिवारी

आम जिंदगी में लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं. लोगों के आकर्षण का केंद्र भी मानवीय पहलुओं से हटकर भौतिक होता जा रहा है. सिर्फ इतना ही आधुनिक समाज में आते परिवर्तनों ने इंसानों को एक दूसरे से कई मायनों में अलग कर दिया है और कई बार परिस्थितियां काफी अतार्किक होती जाती हैं. मैंने आम जिंदगी में घटने वाले वाकयों को अपनी कृतियों में पिरोने की कोशिश की है. थोड़े हल्के अंदाज में. थोड़े व्यंग्यात्मक लहज़े में. बहुत गंभीर न होकर, जो अपीलिंग हो.

अपनी कृतियों को इसी अंदाज में रखती हैं सताब्दी जेना. बीती 10 से 13 जुलाई तक दिल्ली के इंडिया हैबीटेट सेंटर की ओपन पाम कोर्ट गैलरी में सताब्दी की ग्राफिक्स और मिक्स मीडिया पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी. सताब्दी ने बोस्टन, अमेरिका से पढ़ाई की है. उनकी अमेरिका में इस तरह की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है. सताब्दी ने अपनी इन पेंटिंग्स के जरिये जीवन के उन पहलुओं को छूने की कोशिश की है जिन्हें हम आम तौर पर नज़रअंदाज कर जाते हैं. यह पेंटिंग प्रदर्शनी दूसरी पेंटिंग प्रदर्शनियों से इस मामले में भी अलग थी क्योंकि इसमें सिर्फ चित्रकला के जरिये ही मनोभावों को नहीं व्यक्त किया गया. मिक्स मीडिया पेंटिंग में चित्रकारी के साथ– साथ उपयोगी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है. सताब्दी खुद भी इसे आम चित्रकला से थोड़ा अलग मानती हैं. वे कहती हैं कि ये पेंटिंग्स अपने साथ शब्दों

पूरी पेंटिंग प्रदर्शनी के भीतर भी कई सेक्शन बनाए गए थे जिनके अलग अलग थीम आधारित नाम रखे गए थे. सताब्दी की पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह समाज पर तीखे व्यंग्य करती हैं लेकिन उन व्यंग्य का अंत मुस्कुराहट के साथ होता है. प्रदर्शनी में आए कई लोग पेंटिंग्स को देखने के बाद उसके अर्थों को समझ कर मुस्कुरा रहे थे. मतलब यह कि ये पेंटिंग्स आप को दो तरह से आनंदित कर सकने की क्षमता रखती हैं. ये न सिर्फ आपको गुदगुदाती हैं बल्कि अपने तीक्ष्ण कटाक्ष से सोचने पर भी मजबूर करती हैं. ज्यादातर पेंटिंग्स की थीम आम जन जीवन से ही जुड़ी होने के कारण लोगों को अपने ज्यादा सन्निकट भी महसूस होती हैं.

को भी समेटे हुए हैं. कई जगह ऐसा भी है जहां ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि शब्द ठूंसे गए हैं. बल्कि शब्दों के जरिये चित्रों के मनोभावों को व्यक्त किया गया है. कई जगह शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ शीर्षक देने के लिये किया गया है.

इस प्रदर्शनी में कई ऐसी पेंटिंग्स रहीं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया. लगभग सभी पेटिंग्स सामाजिक परिपेक्ष्य से जुड़े सरोकारों और आधुनिक समाज में आते बदलावों की कहानी कहने में बखूबी कामयाब

होती दिखाई दीं.

पूरी पेंटिंग प्रदर्शनी के भीतर भी कई सेक्शन बनाए गए थे जिनके अलग–अलग थीम आधारित नाम रखे गए थे. सताब्दी की पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह समाज पर तीखे व्यंग्य करती हैं लेकिन उन व्यंग्य का अंत मुस्कुराहट के साथ होता है. प्रदर्शनी में आए कई लोग पेंटिंग्स को देखने के बाद उसके अर्थों को समझ कर मुस्कुरा रहे थे. मतलब यह कि ये पेंटिंग्स आप को दो तरफा आनंदित कर सकने की क्षमता रखती हैं. ये न सिर्फ आपको गुदगुदाती हैं बल्कि अपने तीक्ष्ण कटाक्ष से सोचने पर भी मजबूर करती हैं. ज्यादातर पेंटिंग्स की थीम आम जन जीवन से ही जुड़ी होने के कारण लोगों को अपने ज्यादा सन्निकट भी महसूस होती हैं. अक्सर चित्रकला प्रदर्शनियों में पेंटिंग्स के गूढ़ार्थ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते हैं और यह विद्वानों के मानसिक आनंद का प्रतीक बनकर रह जाते हैं. सताब्दी ने इस बात में एहतियात बरता है. वे पेंटिंग्स को आम जीवन के पहलुओं से जोड़ने की हिमायती हैं और उनके विषय भी इस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूमते हैं. एक सेक्शन की थीम जीवन में मिलने वाली अप्रत्याशित खुशियों पर आधारित थी. इसमें एक पेंटिंग थी जिसमें यह दर्शाया गया है कि जब भी हम घर की आलमारी में पड़े हुए अपने कपड़े धुलने के लिए निकालते हैं तो उनमें से अगर कुछ पैसे निकल आते हैं, तो हमें एक अप्रत्याशित खुशी मिलती है. वहीं एक दूसरी पेंटिंग महिलाओं के जीवन पर आधारित थी जिसमें महिलाओं के कैमरे के सामने बदलते भावों को चित्रित किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे पहले फोटो खिचाने के लिए महिलाओं के एक्सप्रेशन चीज बोलने पर कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं. इसके अलावा शादी पर बनी एक पेंटिंग में यह सवाल पूछ गया कि तलाक का पहला कारण क्या होता है तो नीचे जवाब दिया गया है कि शादी. मतलब अगर शादी न हो तो तलाक की आशंका ही नहीं रहती है.

ऐसी ही हंसाने,गुदगुदाने व सामाजिक मान्यताओं पर चोट करने वाली पेंटिंग्स से सराबोर थी यह प्रदर्शनी. पेंटिंग्स की इस विधा को इस बात के सराहा जाना चाहिए कि यह लोगों को सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती बल्कि अपने भीतर मौजूद निहितार्थों की बदौलत आनंदित भी करती है.■

feedback@chauthiduniya.com

इस यूनिवर्सल की-बोर्ड से एक साथ तीन ब्लूटुथ डिवाइसेज को जोड़ा जा सकता है. इनपुट के समय डिवाइस के बीच में स्विच करने के लिए, लॉजिटेक के480 ब्लूटुथ मल्टी डिवाइस की-बोर्ड में एक आसान स्विच डायल उपलब्ध है. इस फुल साइज की-बोर्ड में शॉर्टकट की से अलग एक इंटिग्रेटेड स्टैंड भी है, इससे यूजर के स्मार्टफोन या टैबलेट को जब वह टाइप कर रहे हों, तब एंगल पर होल्ड किया जा सकता है. यह दो रंगों में उपलब्ध है.

इनफोकस का बेहतरीन फोन है एम810

इनफोकस ने अपना स्मार्टफोन इनफोकस एम810 लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड के वर्जन 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इनफोकस ने इसमें दमदार 2.5 गीगाहर्ट्ज क्वॉड-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 एमएसएम 8974 सी प्रोसेसर दिया है. इस फोन में 2 जीबी रैम दी गई है. इनफोकस एम810 में 5.5 इंच स्क्रीन दी गई है, जो फुल एचडी 1080X1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ ही फोन की इंटरनल मेमोरी 16जीबी है. कनेक्टिविटी की बात करें, इसमें 4जी, वाई-फाई 802.11, एफएम रेडियो, ब्लूटुथ 4.0, माइक्रो यूएसबी, जीपीएस/-जीपीएस, 3.5 एमएम आडियो जैक के आप्शन उपलब्ध हैं. यूजर इसमें पेन ड्राइव भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कंपनी ने इसमें 2600एमएएच की बैटरी दी है. सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. ये स्मार्टफोन एंबिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और मेगनेटोमीटर जैसे फीचर्स के साथ आता है. इस स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपये है. ■

इंटेक्स की पहली एंड्रायड स्मार्ट वॉच

इंटेक्स टेक्नोलॉजी ने देश में पहली एंड्रायड आधारित स्मार्टवॉच लॉन्च करने का एलान किया है. आइरिस्ट ब्रांड नाम की इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें अलग से सिम कार्ड लगाकर फोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह 3जी तकनीक को भी सपोर्ट करेगी. बिना सिम लगाए इसे स्मार्टफोन के एक्सटेंशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आइरिस्ट में कंपनी ने वो सब उपलब्ध कराया है, जो एक एंड्रायड फोन पर उपलब्ध है. इसमे 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. इसमें 4जीबी रोम और 512 एमबी रैम के साथ ही इसकी मेमोरी को 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. आइरिस्ट में 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर है. इस स्मार्टवॉच के लिए इंटेक्स ने एंड्रायड किटकैट 4.4.2 को आपरेटिंग सिस्टम के तौर इस्तेमाल किया है. शुरु में यह ई-बे के जरिए आनलाइन मिलेगी. बाद में कंपनी आइरिस्ट को अपने डीलर नेटवर्क के जरिए बाजार में उपलब्ध कराएगी. 200 घंटे स्टैंडबाई और चार घंटे का टाकटाइम देने वाली इस स्मार्टवॉच के जरिए फोन काल करने से लेकर मैसेज भेजने और इंटरनेट सर्च करने तक के सभी काम किए जा सकते हैं. मैसेज टाइप करने के लिए इसमें वायस और की-बोर्ड दोनों तरह की टाइपिंग व्यवस्था है. कंपनी ने इसकी कीमत 11,999 रुपये रखी है. ■

लॉजिटेक ने लॉन्च किया ब्लूटुथ मल्टी-डिवाइस की-बोर्ड

लॉजिटेक ने ब्लूटुथ मल्टी डिवाइस की-बोर्ड लाजिटेक के480 लॉन्च किया है. कंपनी के अनुसार लॉजिटेक के480 ब्लूटुथ मल्टी-डिवाइस कीबोर्ड पहला डेस्क कीबोर्ड है, जिसे तीन डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बावजूद भी इसका मतलब है कि इसे डेस्कटॉप (विंडोज, मैक या क्रोम ओएस) के अलावा एंड्रायड और आइओएस टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इस यूनिवर्सल की-बोर्ड से एक साथ तीन ब्लूटुथ डिवाइसेज को जोड़ा जा सकता है. इनपुट के समय डिवाइस के बीच में स्विच करने के लिए, लॉजिटेक के480 ब्लूटुथ मल्टी डिवाइस की-बोर्ड में एक आसान स्विच डायल उपलब्ध है. इस फुल साइज की-बोर्ड में शॉर्टकट की से अलग एक इंटिग्रेटेड स्टैंड भी है, इससे यूजर के स्मार्टफोन या टैबलेट को जब वह टाइप कर रहे हों, तब एंगल पर होल्ड किया जा सकता है. यह दो रंगों में उपलब्ध है. इसकी कीमत 2,795 रुपये है.■

ज़ोलो का नया ब्लैक सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च

स्मार्टफोन कंपनी ज़ोलो ने ब्लैक सीरीज नाम से एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में दूसरे जेनरेशन का 64 बिट ऑक्टा कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 615 प्रोसेसर व 2 जीबी डीडीआर3 रैम लगा है. यह फोन हाइव यूजर इंटरफेस (यूआई) के नए संस्करण हाइव एटलस से अपडेट है और एंड्रॉयड के लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस स्मार्टफोन में 16 जीबी का इंटरनल स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन 4जी एलटीई को सपोर्ट करता है, जिसमें ड्यूल सिम स्लॉट है. साथ ही 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जबकि 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 5.5 इंच का फुल डिस्प्ले है, जिसकी पिक्सल डेंसिटी 401 पीपीआई है. कॉर्निया ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी है, जो आगे व पीछे दोनों तरफ लगा है. इसमें 3200 एमएएच की बैटरी है. इस स्मार्टफोन की कीमत 12,999 रुपये है. ■

धूम मचाएगी होंडा की नई जैज़

होंडा कार्स इंडिया ने नई थर्ड जनरेशन होंडा जैज़ को भारतीय बाजार में उतारा है. नई जैज़ को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कॉम्पैक्ट हैचबैक के रूप में विकसित किया गया है. नई जैज़ भारत में डीज़ल और पैट्रोल दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी. डीजल वैरिएंट में 1.5 लीटर आई-डीटीईसी डीजल इंजन को विशेष रूप से भारत के लिए उतारा गया है, जो 20.3 किमी प्रति लीटर की माइलेज देती है. इसमें डबल एयरबैग के साथ-साथ दो यात्रियों और बड़े सामान जैसे आगे के पहिये को हटाने के बाद बाइक को ले जाने के लिए मैजिक सीट को फ्लैट किया जा सकता है. इसके अलावा दो अथवा तीन यात्रियों और लंबे सामान जैसे दूसरी पंक्ति में हाउसप्लांट को ले जाने के लिए मैजिक सीट को फोल्ड किया जा सकता है. सफबोर्ड जैसे बहुत लंबे सामान और दो यात्रियों को ले जाने के लिए मैजिक सीट को फ्लैट करके आगे की सीट को पूरे समय के लिए पीछे किया जा सकता है, साथ ही आराम के लिए आगे की सीट को पूरे सफर के दौरान पीछे मोड़ा जा सकता है. खास बात यह है कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल और डीजल वैरिएंट 5 ग्रेडस-ई, एस, एसवी, वी और वी एक्स में उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त जैज़ एस और वी पेट्रोल वैरियंट में सीवीटी में उपलब्ध होगी. नई जैज़ 7 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी. ■

नई जैज़ भारत में डीज़ल और पैट्रोल दोनों वैरिएंट में उपलब्ध होगी. डीजल वैरिएंट में 1.5 लीटर आई-डीटीईसी डीजल इंजन को विशेष रूप से भारत के लिए उतारा गया है, जो 20.3 किमी प्रति लीटर की माइलेज देती है. इसमें डबल एयरबैग के साथ-साथ दो यात्रियों और बड़े सामान जैसे आगे के पहिये को हटाने के बाद बाइक को ले जाने के लिए मैजिक सीट को फ्लैट किया जा सकता है.

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने लोढ़ा समिति के इस फैसले का स्वागत किया है और लोढ़ा समिति द्वारा की गई कार्रवाई को एक ईमानदार निर्णय बताया है. उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए न्याय की संज्ञा दी और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहला ईमानदार फैसला आया है. लोढ़ा समिति की रिपोर्ट इस दिशा में पहला कदम है.

लोढ़ा क़मेटी का फ़ैसला

एक क़दम स्वच्छता की ओर

लोढ़ा समिति के इस फैसले के बाद आईपीएल के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि उन्होंने गेंद बीसीसीआई के पाले में डाल दी है और कहा है कि बीसीसीआई चाहे तो चेन्नई और जयपुर की फ्रेंचाइजी को समाप्त कर सकता है. जस्टिस लोढ़ा ने एक न्यूज चैनल को बताया कि कमेटी ने दोनों फ्रेंचाइजियों को टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना उनके दायरे के बाहर था. हमें एक अनुशासनात्मक कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएल का क्लॉज 11.3 फ्रेंचाइजी के अनुबंधात्मक दायित्वों को डील करता है. इसके अनुसार एग्रीमेंट का उल्लंघन करने की वजह से बीसीसीआई फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर सकती है.

नवीन चौहान

अब तक देखने में यह आया है कि आईपीएल सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन विवादों की वजह से दो कदम पीछे लौट आता है. एक बार फिर यही वाकया दोहराया गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आईपीएल की दो दिग्गज टीमों चेन्नई सुपर किंग्स(सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स(आरआर) को दो साल के लिए निलंबित कर दिया है. वहीं सीएसके के पूर्व ऑफीशियल और पूर्व बीसीसीआई प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन एवं राजस्थान रॉयल्स टीम के सह–मालिक राज कुंद्रा पर समिति ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है. उच्चतम न्यायालय ने इस साल जनवरी में लोढ़ा समिति का गठन किया था ताकि यह तय किया जा सके कि मयप्पन, कुंद्रा और दो फ्रेंचाइजी, सीएसके की मालिक कंपनी इंडिया सीमेंट लिमिटेड और राजस्थान रायल्स की मालिक जयपुर आईपीएल को कितनी सजा दी जाए. लोढ़ा समिति के इस फैसले के बाद आईपीएल के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि उन्होंने गेंद बीसीसीआई के पाले में डाल दी है और कहा है कि बीसीसीआई चाहे तो चेन्नई और जयपुर की फ्रेंचाइजी को समाप्त कर सकता है. जस्टिस लोढ़ा ने एक न्यूज चैनल को बताया कि कमेटी ने दोनों फ्रेंचाइजियों को टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि ऐसा करना उनके दायरे के बाहर था. हमें एक अनुशासनात्मक कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएल का क्लॉज 11.3 फ्रेंचाइजी के अनुबंधात्मक दायित्वों को डील करता है. इसके अनुसार एग्रीमेंट का उल्लंघन करने की वजह से बीसीसीआई फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट कर सकती है.

अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने कहा कि इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की हरकतों की वजह से खेल की पवित्रता प्रभावित हुई है. इन फ्रेंचाइजियों ने प्रशंसकों के साथ धोखा किया है. खेल की पवित्रता सर्वोपरि होनी चाहिए. इन फ्रेंचाइजियों ने नियमों के साथ खिलवाड़ किया और टीमों को बपौती मानकर मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश की है. इसका खामियाजा खिलाड़ियों, खेल प्रशंसकों और खेल तीनों को पहुंचा है. खिलाड़ी खेलते रहेंगे, बीसीसीआई पैसा कमाती रहेगी, लेकिन प्रशंसकों का जो विश्वास खोया है उसे वापस ला पाना बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. इसलिए इस तरह के कड़े निर्णय लेने की जरूरत थी. कहने को तो टीमों पर बैन लगा है खिलाड़ियों पर नहीं. अभी 13 खिलाड़ियों के नाम वाले उस सील बंद लिफाफे का खुलना बाकी है, जो मुद्गल समिति ने जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था. गैर–आधिकारिक रूप से उन 13 नामों में से कई नामों का जिक्र हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है.

जब न्यायमूर्ति लोढ़ा से बैन की गई टीमों के खिलाड़ियों के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि खेल व्यक्तियों से बड़ा होता है. यदि क्रिकेट व्यक्तियों से बड़ा है, तो खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी को होने वाला वित्तीय नुकसान महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी के अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि लोढ़ा समिति का आदेश बीसीसीआई और संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा. पीड़ित पक्ष जस्टिस टीएस ठाकुर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने अपील कर सकते हैं. इसी बेंच ने जनवरी में फैसला सुनाया था. सीएसके की मालिक इंडिया सीमेंट्स ने समिति के फैसले को चुनौती देने की घोषणा भी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति को तीन काम दिए थे. उनमें से फिलहाल मयप्पन, कुंद्रा, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को सजा सुनाने का काम पूरा हुआ है. तत्कालीन सीईओ सुंदर राजन की भूमिका और बीसीसीआई की सफाई की सिफारिशों पर समिति अभी काम करती रहेगी.

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने लोढ़ा समिति के इस फैसले का स्वागत किया है और लोढ़ा समिति द्वारा की गई कार्रवाई को एक ईमानदार निर्णय बताया है. उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए न्याय की संज्ञा दी और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहला ईमानदार फैसला आया है. लोढ़ा समिति की रिपोर्ट इस दिशा में पहला कदम है. यह अभी समाप्त नहीं हुआ है. इसे एक नई शुरूआत के रूप में लेना चाहिए. ललित मोदी ने हालांकि टीमों के दो वर्ष के निलंबन को मामूली सजा बताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए था. इस पूरे प्रकरण से लीग और खेल की छवि को नुकसान पहुंचा है. टीमें यह कहकर नहीं बच सकतीं कि दोनों दोषियों ने व्यक्तिगत तौर पर काम किए. लोढ़ा समिति द्वारा किए गए निर्णय को कठोर माना जा रहा है, लेकिन हकीकत में कमेटी ने टीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है. हालांकि समिति ने जो कदम उठाए हैं वो नियमों के हिसाब से बहुत कम है.

इस पूरे मसले पर महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, हालांकि कमेटी ने उनके संबंध में कुछ नहीं कहा है, लेकिन धोनी ने मयप्पन के संबंध में मुद्गल समिति के समक्ष बयान दिया था कि मयप्पन क्रिकेट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे. वह केवल उत्साही खेल प्रशंसक थे. ऐसा संभव नहीं है धोनी को मयप्पन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि धोनी इंडिया सीमेंट्स में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, यदि कंपनी का बोर्ड या टीम किसी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है तो महेंद्र सिंह धोनी भी बराबर के जिम्मेदार हैं. चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान होना और इंडिया सीमेंट्स का वाइस प्रेसिडेंट होना भी हितों के टकराव का मुद्दा है. इसलिए उनके खिलाफ भी झूठा बयान दर्ज कराने की कार्रवाई होनी चाहिए.

इस निर्णय से श्रीनिवासन सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे. वह तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष हैं. आईसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि और चेयरमैन भी हैं. हालांकि, उनकी फ्रेंचाइजी और दामाद को सजा दी गई है. इससे उनके विरोधियों, खासकर जगमोहन डालमिया और शरद पवार को ताकत मिलेगी. कमेटी के फैसले के बाद आईसीसी के चेयरमैन पद से श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांगें भी उठने लगी हैं. आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष मुस्तफा कमाल ने श्रीनिवासन के आईसीसी का चेयरमैन बने रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. मुस्तफा कमाल ने आईसीसी की 2014 में हुई मीटिंग का हवाला देते हुए कहा कि आईसीसी की उस सालाना बैठक में श्रीनिवासन से जब आईपीएल फिक्सिंग में चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं या मेरी टीम फिक्सिंग की दोषी साबित होती है तो मैं आईसीसी चेयरमैन के पद से

इस्तीफा दे दूंगा. वहीं स्पॉट फिक्सिंग मामले के याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने लोढ़ा समिति के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि बीसीसीआई को अब आईसीसी में अपने प्रतिनिधि के रूप में एन श्रीनिवासन का नामांकन रद्द कर देना चाहिए. उन्होंने जस्टिस लोढ़ा समिति के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिन लोगों ने खेल को बदनाम किया है बीसीसीआई को उन्हें दूर कर देना चाहिए. मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई एक विशेष समिति का गठन करे और श्रीनिवासन को हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बाहर कर दे. उन्होंने यह भी कहा कि यदि बीसीसीआई ने मेरी मांग स्वीकार नहीं की, तो मैं इस मसले को लेकर अदालत जाऊंगा.

आईपीएल अपने आगाज के समय से ही विवादों में घिरा रहा है. पहले साल कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बाद से लगातार नये विवादों में घिरने की वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में गिरावट भी दर्ज की गई. और अब आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमों पर बैन लगना आईपीएल के लिए बहुत बड़ा झटका है और उसकी ब्रांड वैल्यू पर सबसे बड़ा झटका है. इसका सीधा असर बीसीसीआई की कार्यशैली पर भी पड़ने वाला है. बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा है कि बोर्ड लोढ़ा समिति के फैसले का सम्मान करेगा. बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद पारदर्शी और सर्वसम्मत तरीके से फैसला लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल निलंबित हुई टीमों के 50 खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं. इन खिलाड़ियों में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं, जिनके बारे में सुनील गावस्कर कह चुके हैं कि धोनी के बिना आईपीएल की कल्पना करना मुश्किल है. ऐसे में बीसीसीआई के पास दोनों फ्रेंचाइजियों को टर्मिनेट कर उन टीमों के खिलाड़ियों को नीलामी में उतारने का विकल्प है. तभी इन टीमों के खिलाड़ी दूसरी टीमों के लिए खेल सकेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा. क्योंकि दो साल के प्रतिबंध के खिलाफ ये दोनों टीमें कोर्ट जाने का मन बना चुकी हैं. ऐसे में अपील पर सुनवाई होने तक बीसीसीआई ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, जिससे उसके खुद के लिए परेशानियां खड़ी हों. यदि अपील के बाद उन पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाता है तब भी खिलाड़ियों को लेकर परेशानियां पेश आएंगी. ऐसे में इन टीमों के खिलाड़ियों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी. कोर्ट की प्रक्रिया जितनी जल्दी खत्म होगी खिलाड़ियों को भी उतनी जल्दी राहत मिलेगी.

ऐसे भी आईपीएल के दसवें संस्करण के बाद सभी खिलाड़ियों की एक बार फिर से नीलामी होगी. आईपीएल के नियमों के अनुरूप दस टीमें इस प्रतियोगिता में खेल सकती हैं. पहले भी आईपीएल में आठ से ज्यादा टीमें खेल चुकी हैं, पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स टीमें आईपीएल में आने के बाद वापस भी चली गई हैं, इसलिए दो साल के लिए दो टीमों के निलंबन के बाद भी अगले सीजन में खेलती दिखेंगी. कोच्ची टस्कर्स पहले से ही वापसी करने के लिए तैयार बैठी है. बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हमें इस बात का अंदेशा पहले से ही था. इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों में कई बार चर्चा भी हो चुकी है. अब फैसले को पढ़कर और इस पर बैठक करके आगे की रूपरेखा तय की जाएगी. उनका यह भी कहना है कि अगले साल भी आपको आईपीएल में आठ टीमें ही खेलती नजर आएंगी. कई लोग फ्रेंचाइजी खरीदने के इच्छुक हैं. इस दिशा में भी काम किया जा रहा है.

हाल ही में पूर्व न्यायाधीश आरसी लाहौटी ने रिपोर्ट दी थी कि बीसीसीआई पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स को 550 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में दे. बीसीसीआई ने करार का उल्लंघन करने के कारण 2011 में कोच्चि का करार रद्द कर दिया था. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इसके खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हालिया फैसले के बाद कोच्चि टस्कर्स की बांछें खिल गई हैं. वहीं, कोच्चि के मालिक पहले से ही 550 करोड़ रुपये लेने की जगह बीसीसीआई से उन्हें अगले सत्र आईपीएल में शामिल करने के लिए कह रहे हैं. इसके अलावा इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों की फ्रेंचाइजी बनाने की बातें भी सामने आ रही हैं. ऐसे में अगले सीजन में टीमों की संख्या 6 होने और मैचों की संख्या घटकर 34 होने की जो आशंका जताई जा रही है. उस समस्या से बीसीसीआई को आसानी से निजात मिल जाएगी. यदि बीसीसीआई टीमों की संख्या बढ़ाने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है, तो निलंबन के बाद जब चेन्नई और जयपुर की टीमें वापसी करेंगी तब उन्हें टीम बनाने के लिए फिर से शुरूआत करनी होगी. परेशानी वाला समय जल्दी निकल जाएगा. जहां तक बात निलंबन के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों की है, तो समझौते के तहत खिलाड़ियों को पैसे टीमों को देने ही होंगे. खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान पहले से ही हैं लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे जैसे स्टार खिलाड़ियों को नहीं खेलता देख पाने की टीस प्रशंसकों के मन में बनी रहेगी.

लोढ़ा समिति का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक फैसला है. लेकिन फिक्सिंग होने की बात साबित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब हुई है. बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. जिस तरह कमेटी ने अभी फैसले लिए हैं उनसे आगे भी ऐसे ही निर्णय लेने की आशा है. संभवतः उनके उस फैसले से देश में खेलों की दशा–दिशा सुधर जाएगी. निश्चित तौर पर खेलों में फैले भ्रष्टाचार की सफाई की दिशा में यह पहला कदम है. ■

navinonline2003@gmail.com

DAILY MULTIMEDIA LIMITED
Presents

Hogaya Dimaagh ka Dahi

A FILM BY FAUZIA ARSHI

100% ORIGINAL LAUGHTER RECIPE

5 GREAT COMEDIANS OF THE CENTURY

25TH SEPTEMBER 2015

DIRECTED BY **FAUZIA ARSHI**
STARRING **OM PURI, SANJAY MISHRA, RAAJPAL YADAV, RAZZAQ KHAN, VIJAY PATKAR & KADER KHAN**
CHITRASHI RAWAT, AMITA NANGIA, SUBHASH YADAV, BUNTY CHOPRA, DANISH BHATT, NEHA KARAD, AMIT J.
PRODUCED BY **SANTOSH BHARTIYA & FAUZIA ARSHI**

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

27 जुलाई -02 अगस्त 2015   Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHI/2009/30467

इस बार फिर जातिवाद केवलम्

जाति गणना की रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर राजद सुप्रीमो सड़क पर आ गए और नीतीश कुमार के साथ-साथ जनता परिवार गठबंधन के अन्य दल-कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस-भी उनके साथ हो गए. राजद सुप्रीमो ने इस सवाल पर राजभवन मार्च तो किया ही, मंडल से अधिक तीखा आंदोलन की चेतावनी दी है. इस मसले पर वे 26 जुलाई को एक दिन का उपवास करेंगे.

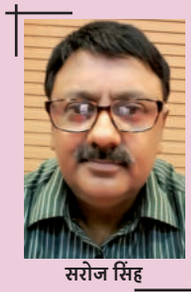

सरोज सिंह

बिहार की राजनीति में, और इस बहाने सड़कों पर भी, जाति का मसला एक बार फिर आक्रामक रूप में उतर आया है. भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति की गणना करवाई थी. जाति को छोड़ कर इस गणना की रिपोर्ट गत दिनों जारी कर दी गई. जाति गणना की रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने पर बिहार में मंडल राजनीति के नायकों-राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने गहरी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि केन्द्र सरकार का मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व पिछड़ा विरोधी है और बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है, लिहाज़ा वह जाति की गणना के आंकड़े नहीं जारी कर रही है. इस मसले को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह कह कर हवा दे दी कि उनकी पार्टी पिछड़ा विरोधी कैसे हो सकती है? उसने देश को पहला पिछड़ा (ओबीसी) प्रधानमंत्री दिया है. हालांकि अमित शाह एचडी देवेगौड़ा को भूल गए होंगे जो इस देश के पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री थे. यह बहुत पुरानी नहीं उन्नीस साल पहले की बात है. हां, यह संभव है कि अमित शाह की कोई राजनीतिक योजना रही हो. जाति गणना की रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग को लेकर राजद सुप्रीमो सड़क पर आ गए और नीतीश कुमार के साथ-साथ जनता परिवार गठबंधन के अन्य दल, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, भी उनके साथ हो गए. राजद सुप्रीमो ने इस सवाल पर राजभवन मार्च तो किया ही, मंडल से अधिक तीखा आंदोलन की चेतावनी दी है. इस मसले पर वे 26 जुलाई को एक दिन का उपवास करेंगे. साथ ही, केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने (वस्तुतः इसे चुनवी मुद्दा बनाने) के लिए 27 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है. नीतीश कुमार अभी तक सड़क पर तो नहीं उतरे हैं, पर वह और उनका दल लालू प्रसाद के साथ है. इस प्रकार जाति का मसला सूबे के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के केन्द्र में फिर आ गया. विकास की बात स्थगित हो गई. बिहार के चुनावों में जाति महत्वपूर्ण घटक रही है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जातियों की गोलबंदी के आधार पर पंद्रह साल तक इस सूबे के भाग्यविधाता बने रहे. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के वीपी सिंह सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया. लालू प्रसाद ने उस दौर में पिछड़ी जातियों को अपने साथ गोलबंद करने के ख्याल से अगड़ी जातियों को निशाने पर लिया था. यह गोलबंदी कुछ ही वर्षों में कमजोर होने लगी, तो उनका सारा जोर माय (मुस्लिम-यादव) के सामाजिक आधार पर हो गया. अब इसमें भी क्षरण साफ-साफ दिख रहे हैं. जदयू सुप्रीमो नीतीश कुमार 05 में सत्ता में आए और कुछ वर्षों के दौरान ही बगैर किसी हल्ला-हंगामा के उन्होंने अपना, भाजपा की छाया से बाहर, सामाजिक आधार तैयार किया. अतिपिछड़ा (राज्य की कोई 33 प्रतिशत आबादी) और महादलित (तेरह प्रतिशत से अधिक आबादी) इसके मुख्य अवयव बने. पर, नीतीश कुमार की राजनीति का मुख्य नारा पिछड़ावाद नहीं, बल्कि न्याय के साथ विकास रहा. इस सिलसिले में महिलाओं, अतिपिछड़ी जातियों व महादलितों के राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण का अपना राजनीतिक एजेंडा उन्होंने लागू किया. इस लिहाज़ से वह अपने बड़े भाई से अलग रहे. पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं करने का दावा करने वाली भाजपा ने गत संसदीय चुनावों में खुल कर जाति की डोर पकड़ी, उसने नरेन्द्र मोदी के अतिपिछड़ा होने को खूब प्रचारित किया और वोट भी बटोरे. हालांकि उन दिनों जाति के साथ-साथ विकास और स्थिर, मगर सक्रिय, सरकार भी महत्वपूर्ण चुनावी मसला था. दिल्ली की सरकार में बदलाव का मतदाताओं ने मन बन लिया था और वही नरेन्द्र मोदी और भाजपा (या एनडीए) के लिए सबसे बड़ा बोट-बटोरू तत्व बना.

फिर बैतलवा डाल पर- बिहार में जाति कार्ड फिर चुनाव में मतदान का बड़ा प्रेरक-तत्व बनता जा रहा है. जाति गणना की रिपोर्ट जारी नहीं कर और प्रधानमंत्री की जाति को चुनावों के दौरान आक्रामक तरीके से सामने रख कर भाजपा ने इस राज्य के मंडल नायकों को सड़क पर उतरने-यों कहें कि राजनीति को पंद्रह साल पुरानी शक्ल में ले जाने-का मौका दे दिया. यह एक वास्तविकता है कि बिहार के ग्रामांचल और पिछड़े विपन्न समाज में भाजपा अब भी बड़े लोगों (जाति और धन से) की पार्टी मानी जाती है. हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा संगठन और नेतृत्व पर अगड़ों की पकड़ कमजोर हुई है और कुछ खास पिछड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ा है. पर, महादलित, दलित, अतिपिछड़े आदि सामाजिक समूहों की पृष्ठभूमि के नेताओं-कार्यकर्ताओं का यहां अब भी अभाव है. बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी की 54 प्रतिशत और मुसलमान की जनसंख्या कोई सोलह प्रतिशत है. महादलित (अब बिहार में सभी दलित समुदायों को इसी श्रेणी में शामिल किया गया है.) की आबादी कोई चौदह प्रतिशत मानी जाती है. बिहार के अगड़े और कुछ पिछड़ों और महादलित समुदायों के बड़े धड़े की गोलबंदी भाजपा के पक्ष में दिख रही है. इधर, माय के साथ कुछ पिछड़े और अतिपिछड़ों के बहुमत धड़े व मुसलमान-समाज का समर्थन जनता परिवार गठबंधन को मिलता दिख रहा है. अब नीतीश-लालू की पूरी राजनीतिक कसरत भाजपा के प्रति सहानुभूतिशील कुछ पिछड़े और कुछ अतिपिछड़े सामाजिक समूहों को जनता परिवार गठबंधन के दायरे में लाने की है. इसके लिए लालू प्रसाद यदि सड़क पर उतर रहे हैं, तो नीतीश कुमार प्रशासनिक स्तर पर एनडीए को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं. बिहार सरकार ने हाल ही वैश्य समुदाय की बड़ी उपजाति तेली और कुशवाहा समुदाय की दांगी को पिछड़ा से अतिपिछड़े की श्रेणी में डाल दिया है. हालांकि इस फैसले का राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, यह कहना कठिन है. पर, इसने एनडीए को असहज जरूर कर दिया है. कुशवाहा की दांगी उपजाति की दक्षिण बिहार में काफी वक़त है, तो तेली उपजाति कई इलाकों में फैली है. इन्हें अतिपिछड़ा घोषित करने की मांग वर्षों से की जाती रही है. जाति-गणना की रिपोर्ट के प्रकाशन की मांग के बहाने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (और इस बहाने जनता परिवार गठबंधन) अपने सामाजिक समर्थक आधार को ज्यादा विस्तार देकर उसे नए सिरे से आक्रामक बनाने की रणनीति को सरजमीं पर उतार रहे हैं. इधर, नरेन्द्र मोदी की जाति को आगे कर इस आंदोलन के समानान्तर पिछड़ावाद का नया पैरोकार बनने को भाजपा बेताब दिखती है. इस अभियान की शुरुआत किसी और ने नहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ही की है. हालांकि यह अनायास नहीं हुआ है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां संस्कृति के चार अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा के प्रकाशन के 58 व 52 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में दिनकर जी की पंक्ति के हवाले से ही जातिवाद को बिहार के विकास का सबसे बड़ा अवरोधक तत्व कहा था. -शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

बिहार भाजपा के नेताओं ने लालू प्रसाद की जातिवादी राजनीति का अनुसरण करते हुए पिछले चार-पांच महीने में सूबे की लगभग सभी प्रमुख जातियों के सम्मेलनों का आयोजन किया है. ऐसे सम्मेलन हाल तक आयोजित किए जाते रहे हैं. शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा की इस रणनीति पर कभी अंगुली तो नहीं उठाई, किसी नेता से यह तो नहीं पूछा गया कि ऐसे जातीय आयोजन क्यों किए जा रहे हैं. जातिवाद को बिहार का कोढ़ बताने वाले नरेन्द्र मोदी तक ने अपनी जाति के निरंतर सार्वजनिक राजनीतिक उपयोग पर कभी कोई आपत्ति तक नहीं की! जाति भाजपा की राजनीति का एक नया चेहरा बनती दिख रही है. इसे बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि गत दो तीन चुनावों के बाद जाति एक बार फिर चुनावी राजनीति के केन्द्र में आ गई है.

एक नज़र
चुनावी हलचल

पार्टी मना रही स्थापना दिवस समारोह

क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी अपना स्थापना दिवस समारोह 9 अगस्त को मना रही है. पार्टी का यह 18 वां स्थापना दिवस वर्ष है. स्थापना दिवस समारोह पटना के दरोगा राय पथ स्थित दरोगा राय स्मारक भवन में आयोजित होगा. उक्त बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्री लाल राय ने बतायी. उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह में आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी, पार्टी यह भी तय करगी कि आगामी विधानसभा चुनाव अपने बल बूते लड़ा जाय या किसी गठबंधन के साथ जाया जाय. साथ में राज्य सरकार के कार्य को उजागर करेंगे. इस अवसर पर केन्द्रीय नेता व दिल्ली प्रभारी शमीर शर्मा, एवं विश्वजीत कुमार बिहार प्रभारी तथा राज्य सचिव सुशीला देवी उपस्थित रहेंगी. इस के अलावा बिहार के विभिन्न जिलों से भी कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिनमें मुख्य रूप से मधुबनी जिले के नागेन्द्र यादव, मनेजर यादव, रामेश्वर महतो, राम नरेश यादव, मुनींद्र झा तथा वैशाली जिले के रामचंद्र राय, देवेन्द्र राय, उषा देवी के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे. *– नसीम रब्बानी*

भाजपा से टिकट की रेस में गीता शंकर आगे

एनडीए ने इसबार सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपना हरेक दाव पेंच लगा दिया है. इसी संदर्भ में धोरैया विधानसभा सीट जो कि जदयू का पुराना गढ़ रह चुका है उसे भी हासिल करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है. महादलित व पिछड़ी अतिपिछड़ी जाति से लैश इस सीट पर पूर्व सांसद भुदेव चौधरी लगातार तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं. वर्तमान में भी ये सीट जदयू के ही पक्ष में है. मनीष चौधरी यहां के विधायक है. मगर इस बार उन्हें शिकस्त देने के लिए भाजपा ने महादलित के साथ-साथ महिला उम्मीदवार उतारने का मन बना रखा है जिसमें की गीता शंकर का नाम सबसे आगे है. गीता ने बताया की वो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश सचिव रह चुकी है एवं पार्टी की तरफ से धोरैया विधानसभा सीट पर मैदान में भी उतारा गया था. अंतत: मार्च 2015 में भाजपा का दामन थाम लिया एवं वर्तमान में वो बांका जिले के महामंत्री भी हैं. यहां सबसे खराब स्थिति शिक्षा की है. लोग कम पढ़े लिखे हैं व जागरूक भी नहीं है स्कूल समय पर नहीं खुलता है व पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती है. वहीं सड़क बिजली पानी की समस्या को भी उन्होंने अहम बताया जिसका निदान विधायक के द्वारा अबतक नहीं किया गया है. *–नमन कुमार चौधरी*

अब नहीं चाहिए नीतीश कुमार

धमदाहा स्थित धर्मशाला परिसर में धमदाहा सीट पर दावेदारी को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर झा आजाद प्रदेश दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हरेराम पासवान, प्रदेश संगठन सचिव निरंजन कुशवाहा, प्रदेश नेत्री उर्मिला पटेल, जुल्फिकार अली समेत रालोसपा के हजारों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए.कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश-लालू के जंगल राज-2 से त्राहिमाम कर रही है. पूरे बिहार में रोज लूट, हत्या, एवं बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं. बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अस्पतालों में मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है लेकिन गांव-गांव में सभी ब्रांड की शराब की बोतलें खुलेआम मिल रही है. जिस तरह देश की जनता ने अपना समर्थन देकर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया इसी तरह से बिहार विधान सभी के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने वाली है और जंगल राज-2 का सफाया होने वाला है वहीं पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव और एनडीए गठबंधन के अन्तर्गत रालोसपा की तरफ से धमदाहा सीट पर दावेदारी रखने वाले निरंजन कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मचा है हाहाकार और नीतीश घर-घर दस्तक देकर कह रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार जबकि जनता उनसे कह रही है कि अब बिहार की जनता हो गई है पहले से ज्यादा होशियार अब बहुत हो गया हमें फिर नहीं चाहिए नीतीश कुमार.■

– नीरज कुमार सिंह

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

अनियमित जीवनशैली से हृदय रोग

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. तरुण शरण
फिजिशियन, नवादा

हृदय रोग होने के कई कारण हैं जिनमें से लोगों की अनियमित जीवनशैली प्रमुख कारण है। पहले लोगों को हृदय रोग कम होता था, क्योंकि उनकी जीवनशैली सरल और स्वस्थ थी। लेकिन आज के बदलते दौर में हमने अपनी जीवनशैली को बहुत जटिल बना दिया है, और आलस से भरी दिनचर्या व भोजन में मिलावट हृदय रोग की दूसरी बड़ी समस्या बन गयी है । इन सारी परेशानियों से सम्बंधित जानकारी दी नवादा के अनुभवी फिजिशियन डॉ तरुण शरण ने उन्होंने बताया कि स्वस्थ्य हृदय स्वस्थ्य शरीर की कुंजी है। हृदय रोग में अक्सर छाती में दर्द होना, हफनी होना थकावट महसूस करना, साँस लेने और सोने में दिक्कत होना है। कुछ नुक्से हैं जिनसे आप स्वस्थ और सरल जीवन जी सकते हैं। डॉ तरुण बताते है कि आपने शरीर के लम्बाई के हिसाब से शरीर का वजन रखे इसके आलावा शारीरिक और मानशिक रूप से सक्रिय रहे, जिन्दगी को सकरात्मक रूप से जीएं इससे आप हृदय रोग जैसी जटिल बीमारी पर रोक लगा सकते हैं। इसमें खान-पान का ध्यान रखना जरूरी है भोजन में हरी सब्जी और फल का सेवन अधिक करना चाहिए मसाले वाली चीजों को न के बराबर प्रयोग करें । डॉ. आगे बताते है कि हृदय दिमाग का दुश्मन होता है । इसलिए दिमागी तनाव न ले ब्लडप्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखे और छः से आठ घंटा रात में नींद अवश्य ले ।■

– रजनीकान्त पाण्डेय

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

गोपालगंज

टिकट के लिए भटकने लगे धनकुबेर

मिथिलेश तिवारी | कृष्ण शाही | पप्पू पांडेय | अनूप तिवारी | दीपक दुबे | ओमप्रकाश सिंह | रानी देवी | रियाजुल हक

अखिलेश मिश्र

कुछ दावेदार तो एक-डेढ़ करोड़ रुपये तक खर्च करने की हवा यूं बना रहे हैं कि कोई आका पैसा ले ले और टिकट गारंटी करा दे. यूं तो अभी गठबंधन में कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी यह तय नहीं, ऐसे में टिकटार्थी हर संभावना पर काम कर रहे हैं . मसलन, गोपालगंज, भोरे और बरौली सीट पर भाजपा का कब्ज़ा है, वहीं बैकुंठपुर, हथुआ और कुचायकोट पर जदयू का कब्ज़ा है. इन लोगों की उम्मीदवारी तय है, भाजपा की नजर बैकुंठपुर, हथुआ और कुचायकोट पर टिकी हैं. उसी प्रकार जदयू कि गोपालगंज, भोरे और बरौली सीट पर नजर है.

गोपालगंज जिले की छह सीटों पर विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के लिए दो दर्जन से अधिक धनकुबेर भटक रहे हैं. कुछ तो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए है तो कुछ ऊपर की सेटिंग से टिकट जुगाड़ करने में लगे हैं. टिकट किसी भी पार्टी से मिले यही पहली कोशिश है. इसके लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार हैं. कुछ दावेदार तो एक-डेढ़ करोड़ रुपये तक खर्च करने की हवा यूं बना रहे हैं कि कोई आका पैसा ले ले और टिकट गारंटी करा दे. यूं तो अभी गठबंधन में कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी यह तय नहीं, ऐसे में टिकटार्थी हर संभावना पर काम कर रहे हैं. मसलन, गोपालगंज, भोरे और बरौली सीट पर भाजपा का कब्ज़ा है वही बैकुंठपुर, हथुआ और कुचायकोट पर जदयू का कब्ज़ा है. इन लोगों की उम्मीदवारी तय है. भाजपा की नजर बैकुंठपुर, हथुआ और कुचायकोट पर टिकी हैं. उसी प्रकार जदयू कि गोपालगंज, भोरे और बरौली सीट पर नजर है. हालांकि गोपालगंज लालू प्रसाद के गृह जिला होने के नाते गोपालगंज, भोरे, हथुआ और बरौली सीट का स्वभाविक दावेदार राजद है. जदयू राजद और कांग्रेस से महागठबंधन होने के बाद नेताओं में खूब उठापटक है. रालोसपा और लोजपा के नेता भी अपने आका को समझाने में लगे हुए हैं कि उनकी भी दावेदारी है. जबकि एनडीए के घटक दलों में खूब हलचल हैं. बैकुंठपुर विधान सभा से भाजपा के टिकट पाने कि रेस में एक दर्जन नेता दिल्ली-पटना एक किए हुए हैं. जिसमे भाजपा के मिथिलेश तिवारी, अनूप कुमार तिवारी, हाल ही राजद छोड़ कर आई पूर्व विधायक देवदत प्रसाद कि पत्नी मनोरमा देवी हैं. हथुआ विधान सभा से भाजपा के टिकट पाने के रेस में दबंग नेता कृष्णा शाही, मकसूदन सिंह, राजद छोड़ कर आये राजेश सिंह और कुचायकोट विधान सभा से रालोसपा नेता चंद्रभूषण सिंह भी टकटकी लगाये हुए हैं, भाजपा से उमेश प्रधान और लोजपा से पूर्व सांसद काली प्रसाद पाण्डेय के पुत्र भी नजर लगाये हुए हैं. कई बार विधान सभा के चुनाव मैदान में रहे राजद नेता रेयाजुल हक़ राजू कि दावेदारी गोपालगंज विधान सभा सीट पर हैं, वहीं जदयू नेता सुनील सिंह को एमलसी के टिकट नहीं मिलने के बाद वे गोपालगंज विधान सभा सीट से जदयू के टिकट पाने के जुगाड़ लगाने में जुटे हुए हैं. गोपालगंज विधान सभा सीट से जिला परिषद् सदस्य ओमप्रकाश सिंह भी अपनी दावेदारी ठोक दी हैं. किस दल से चुनाव मैदान में होगे यह अभी तय नहीं हैं. कुछ पार्टी लाइन पर जीवन खपाने की दुहाई दे रहे हैं तो कुछ अपनी पहुंच के बल पर. पार्टी या गठबंधन में ऊपर तक पहुंच रखने वाले खुद के प्रति आश्वस्त हैं. ऊपर से सीधे चुनावी मैदान में आने को आतुर धनकुबेरों की स्थिति इनसे अलग है. ये मजबूत आका की तलाश में हैं जो हर पार्टी वाले से इनका कनेक्शन जोड़ दे. जिले के छह विधान सभा सीट में कौन एनडीए के किस घटक दल के जिम्मे जाएगा यह अभी अस्पष्ट है.उसी प्रकार महागठबंधन के किस घटक दल के जिम्मे जाएगा यह भी कोई नहीं बता रहा है. एनडीए और महागठबंधन में रहे धनकुबेरों की नजर जिले के छह विधान सभा सीट सीटों पर है, क्योंकि दोनों दल में भारी वेकेंसी है. अभी ये सब अपने-अपने आका के बूते गठबंधन के तहत टिकट पाने के लिए एक किये हुए हैं. ऐसे में इन दिनों राजनीतिक आकाओ की पूछ बढ़ गई है. इन आकाओं के माध्यम से टिकटार्थी अपनी पार्टी के गठबंधन के साथ साथ अन्य घटक दलों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, ताकि अगर सीट अदला-बदली हुई तो भी उन्हें मौका मिले.■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ17का शेष

इस बार फिर जातिवाद केवलम्

पर उसके अगले दिन ही भाजपा के नेताओं ने पटना में वैश्य की एक उपजाति के सम्मेलन में शिरकत करते हुए सत्ता में आने पर उसे हरसंभव सुविधा देने का वायदा किया था. बिहार भाजपा के नेताओं ने लालू प्रसाद की जातिवादी राजनीति का अनुसरण करते हुए पिछले चार-पांच महीने में सूबे की लगभग सभी प्रमुख जातियों के सम्मेलनों का आयोजन किया है. ऐसे सम्मेलन हाल तक आयोजित किए जाते रहे हैं. शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाजपा की इस रणनीति पर कभी अंगुली तो नहीं उठाई, किसी नेता से यह तो नहीं पूछा गया कि ऐसे जातीय आयोजन क्यों किए जा रहे हैं. जातिवाद को बिहार का कोढ़ बताने वाले नरेन्द्र मोदी तक ने अपनी जाति के निरंतर सार्वजनिक राजनीतिक उपयोग पर कभी कोई आपत्ति तक नहीं की! जाति भाजपा की राजनीति का एक नया चेहरा बनती दिख रही है. इसे बिहार का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि गत दो-तीन चुनावों के बाद जाति एक बार फिर चुनावी राजनीति के केन्द्र में आ गई है. वस्तुतः सत्ता के दावेदार इन दोनों राजनीतिक ध्रुवों के पास बिहार के मतदाताओं के सामने परोसने को बहुत कुछ नहीं है- जनता परिवार गठबंधन हो या एनडीए. जनता परिवार गठबंधन के नेता नीतीश

कुमार कहते हैं कि वे काम के आधार पर वोट मांगेंगे और उनके बड़े भाई लालू प्रसाद अपने 1990 के दशक की राजनीति को नए सिरे से एक बार फिर आजमाना चाहते हैं. हालांकि नीतीश कुमार का जनअभियान आरंभ नहीं हुआ है, पर राजद सुप्रीमो की इस नयी आंदोलनकारी रणनीति को नीतीश कुमार का सार्वजनिक समर्थन तो हासिल है ही. ऐसा क्यों हुआ यह कहना कठिन है, पर इतना तो तय है कि गत कुछ समय से बिहार की हालत वह नहीं रही जो 2010 के विधानसभा चुनावों के दौरान थी. गत संसदीय चुनाव के बाद के राजनीतिक घटनाचक्रों ने इस सूबे की हालत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और यह प्रभाव नकारात्मक हैं. सो, नए सिरे से कहने के लिए नीतीश कुमार के पास भी लोक-लुभावन तत्व बहुत अधिक नहीं है. इधर, एनडीए भी इस संदर्भ में संपन्न नहीं है. 2014 के मई के अंतिम हफ्ते में दिल्ली में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी पहली बार इस महीने की पच्चीस तारीख को बिहार आ रहे हैं-एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में. एनडीए के 31 सांसद देने का प्रतिफल अभी तक केन्द्र में बिहार के कुछ मिंयों के अलावा कुछ यदि मिला है, तो वह घोषणाओं की लंबी फेहरिस्त है. ये घोषणाएं केन्द्र में बिहार के मंत्री अपने बिहार दौरे के समय करते रहे हैं. इन्हें लागू करने की तैयारी अब तक शुरू नहीं की गई है या शुरू हुई है भी तो प्रारंभिक स्तर पर ही. हां, इस बीच केन्द्र सरकार ने पुराने घोषित कार्यक्रमों की पैकेजिंग का काम जरूर किया है, विशेषकर सड़क और जल परिवहन के क्षेत्र में. मोकामा में गंगा पर नए रेल पुल के साथ रेल की कुछ योजनाओं की बजट में जरूर घोषणा हुई है. बिहार में एक प्रबंधन संस्थान और एक और एम्स की आम बजट में घोषणा की गई है. लेकिन रोजगार के अवसर पैदा करनेवाली या राज्य के कायाकल्प में भागीदार किसी कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, ऐसा अब तक नहीं लगता. अब प्रधानमंत्री अपनी मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान इस राज्य को कुछ तोहफा दें, तो दीगर है. तोहफे की गुंजाइश बहुत अधिक है, क्योंकि बिहार का चुनाव भाजपा के लिए जीवन-मरण जैसा है. और जीने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यह सामान्य नियम है. ऐसे में जब देने के लिए राजनीति के पास बहुत कुछ नहीं है, तो जाति ही एक मात्र सहारा है. निर्बल के बल राम-कुछ नहीं तो जाति तो है.

बिहार को जातिवाद के अंधेरी सुरंग में कुछ आगे तक ले जाने की एक और तैयारी जोर शोर से जारी है. जातिवाद के इस हमाम में सभी राजनीतिक दल नंगे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

कौन बदलेगा दरभंगा की तस्वीर

कुमार विनोद/ जयशंकर

बिहार की राजनीति और गुटबंदी के कारण किसी भी निवर्तमान विधायक का विधान सभा में पहुंचने का रास्ता इस बार आसान नहीं होगा. महागठबंधन के कारण बिहार के प्रत्येक विधान सभा में जातीय समीकरण अलग कहानी बयान कर रहा है. इस महागठबंधन के होते ही कभी धुर विरोधी रहे नेता आज एक दूसरे के कट्टर समर्थक बन गए हैं साथ ही दोनों के सुर बदल गये हैं. दरभंगा संसदीय क्षेत्र की शहरी विधान सभा संघर्षमय स्थिति में जाती नजर आ रही है. वर्तमान परिस्थिति के द्वारा संकेत मिल रहा है कि भाजपा के हायाघाट के निवर्तमान विधायक 'अमरनाथ गामी' जदयू के टिकट से इस विधानसभा से प्रत्याशी होंगे. ऐसी परिस्थिति में भाजपा प्रत्याशी को अपने दल के पूर्व सदस्य से संघर्ष करना पड़ेगा. प्रत्येक चुनाव में पार्टी के द्वारा विकास की बात की जाती है लेकिन आंतरिक राजनीति जातीयता को लेकर बनती है. लेकिन दरभंगा शहरी विधान सभा के निर्वतमान विधायक संजय सरावगी इस परिपाटी को दरकिनार करते हुए विकास के ही एक मात्र मुद्दे को लेकर जनता के पास जाना चाहते हैं. संजय ने बताया कि दरभंगा की तस्वीर और दरभंगावासियों की तकदीर केवल नीति से नहीं बल्कि साफ नियत से बदलेगी. हमारी पार्टी की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं. उन्होंने इस बात का अफसोस किया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल क्षेत्र को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस योजना के माध्यम से दरभंगा की विशेष पहचान बनती, उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया. दरभंगा में तारा मंडल बनाने की योजना भी थी जिसे वर्तमान सरकार ने अधर में लटका दिया. किसी भी राज्य के मुखिया को इस नीति का पालन नहीं करना चाहिए. आने वाले चुनाव में मिथिलांचल की जनता सरकार की पक्षपात नीति का जवाब जरूर मांगेगी.

उन्होंने बताया कि अपने कार्य काल में इस क्षेत्र के विकास के साथ-साथ एक नई परिपाटी की शुरुआत की है. जनता के प्रतिनिधि का जनता के लिए आसानी से उपलब्ध होना. पहले किसी विधायक से मिलने के लिए चौदह-पन्द्रह दिन प्रयास करना पड़ता था तत्पश्चात कम समय के लिए जनप्रतिनिधि का समय मिल पाता था. अब ऐसा नहीं. किसी मतदाता ने वोट दिया या नहीं दिया. सभी के लिए विधायक के आवास का दरवाजा खुला रहता है. जनता के साथ व्यक्तिगत सहभागिता है. दस साल पहले का दरभंगा और आज के दरभंगा में स्पष्ट रूप से अंतर है. शहर में सड़कों का जाल सा बिछ गया है. मुख्य सड़क के बीच 900 से ऊपर छोटी-बड़ी गली का पीसीसी करवाया गया है. सीएम कॉलेज में स्थित ललित कर्पूरी भवन अर्द्धनिर्मित था, जिसका भव्य रूप से निर्माण किया गया है.

दरभंगा शहरी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की. इस समस्या के समाधान के लिए अत्यधिक प्रयास किया गया लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद भी डीपीआर का निर्माण नहीं हो सका. न्याय यात्रा के समय मिल्लत कॉलेज के प्रांगण में तीस चालीस हजार लोगों के बीच उन्होंने कहा कि तीन माह के अन्दर जल निकासी समस्या को लेकर डीपीआर का निर्माण कर दिया जाएगा. लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी डीपीआर का निर्माण नहीं किया गया है. इतने लोगों के बीच में मुख्यमंत्री ने जनता के सामने झूठ बोला. मुख्यमंत्री को लगता है कि शहरी जनता उन्हें वोट नहीं देती है. अत: शहर की समस्या को यथावत रहने दिया जाए. एक साल से अधिक नीतीश कुमार स्वयं नगर विकास मंत्री रहे फिर भी हमलोगों के आग्रह के बाद जल निकसी का डीपीआर नहीं बनने दिया.

इस चुनाव में सत्ता प्राप्त करने के लिए महागठबंधन किया गया, जिसे जनता भी समझ रही है. लालू प्रसाद यादव का जो पुराना इतिहास है इसलिए उनके साथ विकास की बात या अपराध मुक्त समाज की बात नहीं कही जा सकती है. यह अपवित्र गठबंधन है और जनता इस अपवित्र सम्बंध को अपने से दूर कर देगी. उन्होंने कहा कि पहली बार किसी केन्द्र सरकार ने शहर के विकास की योजना बनाई है केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी को लिए जिस मापदण्ड का निर्धारण किया है. उसमें दरभंगा इस मापदण्ड को पूरा करता है, लेकिन डर यह है कि नीतीश कुमार मिथिलांचल को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं. अत: दरभंगा को स्मार्ट सिटी के रूप में अनुशंसा नही भी करें अगर ऐसा यह सरकार करती है तो इस सरकार के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन यहां की जनता करेगी. दरभंगा के किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अधिकार कानून लागू नहीं किया गया है. बिहार विधान सभा में बार-बार प्रश्न उठाने के बाद भी सरकार ने इस क्षेत्र में कोई पहल नहीं किया है. यह प्राइवेट विद्यालय समाज का शोषण नि:सन्देह रूप से कर रहा है.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के चुने गये प्रतिनिधी का महत्व होता है लेकिन वर्तमान में नीतीश सरकार में अफसर शाही में विकास हुआ है. लोकतंत्र का नामोनिशान नहीं है. भ्रष्टाचार में विकास हुआ है. अपराधियों का बोल बाला हो रहा है. जमीन माफिया के सामने प्रशासन पंगु है. डीएमसीएच दलालों का अड्डा बना है. इस समस्या के लिए बार-बार विधान सभा में आवाज भी उठाया, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की गयी. केन्द्र सरकार ने डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम की शुरुआत की है अगर राज्य सरकार ने इसमें मदद नहीं की तो गरीब का बच्चा आधुनिक नहीं बनेगा. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा.

शहर में सड़क की स्थिति में सुधार को लेकर विपक्षी ने भी सराहना की है इसी विधान सभा के आरजेडी प्रत्याशी सुल्तान अहमद ने सड़क के विकास को स्वीकार किया है लेकिन जल निकासी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया जा सका है इसका अफसोस है विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी समिति के राज्य उपाध्यक्ष रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने कहा कि सड़क का विकास तो दिखायी देता है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या हैं जिसका समाधान आवश्यक है जैसे भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, स्वच्छ समाज का निर्माण. जनता निश्चित रूपसे ऐसे सरकार को चुनेगी जो इन्हें इस प्रकार का समाज दे सके.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : बाजपट्टी विधानसभा

अल्पसंख्यक वोट का अब नहीं होगा बिखराव

वाल्मीकि कुमार

रंजू गीता | उषा किरण | चंद्रजीत यादव | देवेंद्र कुमार यादव | सबीह अहमद

सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक चहलकदमी बढ़ गयी है. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा है. कोई केंद्र सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कर रहा है तो कोई विकास कार्यो की लंबी सूची लेकर दर-दर भटक रहा है. सभी दल को इस वक्त कार्यकर्ता ही भगवान से लेकर तारणहार तक नजर आने लगे है. परंतु इन तमाम राजनीतिक चक्र के बीच मतदाता खामोशी के साथ मूकदर्शक बने है. वही पार्टी कार्यकर्ता भी दलगत व जातीगत झंडे के साथ मालदार आसामी का चुनावी समर में इंतजार कर रहे है.

लगभग पौने 3 लाख मतदाता वाले बाजपटटी विधानसभा क्षेत्र का जहां तक सवाल है तो इस सीट पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है. विधायक डॉ रंजूगीता सूबे की सरकार में बतौर गन्ना उद्योग मंत्री मौजूद है. गैरसरकारी सूत्रों की माने तो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन आधा दर्जन मुस्लिम बाहुल्य पंचायतो को बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया है. बाजपट्टी प्रखंड के 19, बोखड़ा के 7 और नानपुर प्रखंड के 11 पंचायतों को मिलाकर बनाये गये इस क्षेत्र में सर्वाधिक 75 हजार के करीब मुस्लिम मतदाता है. दूसरे स्थान पर वैश्य 45 हजार तो तीसरा स्थान पर यादव तकरीबन 40 हजार के करीब बताया जाता है. 25 हजार के करीब सवर्ण मत बताया जाता है जिसमें भूमिहार व ब्राहमण 10-10 हजार और राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 5 हजार है. शेष 30 से 35 हजार दलित व पिछडा समेत अन्य का वोट की संभावना जतायी जा रही है, जो प्रत्याशियों के लिए काफी महत्व का साबित होता रहा है. जहां तक यादव बिरादरी के विधायक का सीट पर कब्जा का सवाल है तो पिछले चुनाव में जदयू -भाजपा गठबंधन के तहत चुनाव हुआ था. सूत्रों की माने तो विधायक को स्वजातीय वोटों के अलावा भाजपा मतदाताओं का वोट काफी हद तक मददगार साबित हुआ था. साथ ही जदयू के नीतीश कुमार के समर्थक मुसलमानो ने भी जमकर जदयू के पक्ष में मतदान किया था. दलगत व जातिगत वोटों के अलावा चुनाव में वोटों के खरीद-फरोख्त का दौर भी चला था, जिसकी बदौलत विधायक सीट पर कब्जा जमा पाने में कामयाब रही. परंतु अबकी बार पासा पलट गया है. अब जदयू ने भाजपा से नाता तोडकर राजद-कांग्रेस से नई रिश्तेदारी जोड ली है. इस नये रिश्ते को लेकर क्षेत्र में चुनावी समीकरण में भी बदलाव का संकेत आने लगा है. यादव बिरादरी के मतदाता जहां लालू प्रसाद के साथ होने के कारण जदयू गठबंधन में मतदान को लेकर विवश नजर आने लगी है, वही अल्पसंख्यक मतदाता क्षेत्र में अपने अधिकार व हक को लेकर एकजुट होने लगे है. चल रही चर्चा पर भरोसा करे तो इनका कहना है कि अधिक आबादी के बाद भी दलगत राजनीति का मुसलमानों ने समर्थन किया है. परंतु इस बार दलगत व जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ कर बिरादरी के प्रत्याशी को ही सदन में भेजना है. कहते है कि गैर मुसलमान मतदाताओं को भी अल्पसंख्यक हित में एक मौका देने से परहेज नहीं करना चाहिए.

चुनाव में अभी देर है, मगर संभावित प्रत्याशियों का चेहरा क्षेत्र के चौक-चौराहे व गांव की गलियों में नजर आने लगे हैं. जदयू की विधायक डॉ रंजूगीता हर घर दस्तक से लेकर दावते इफ्तार और कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुनावी रीढ़ को मजबूत करने में लगी हैं. वहीं राजद से युवा राजद जिलाध्यक्ष चंद्रजीत प्रसाद यादव भी पार्टी नेताओं के इस वयान को लेकर मतदाताओं की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं कि आसन्न चुनाव में युवा सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जायेगी. इनका दावा है कि पार्टी नेतृत्व युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी.

चुनाव में अभी देर है, मगर संभावित प्रत्याशियों का चेहरा क्षेत्र के चौक -चौराहा व गांव की गलियों में नजर आने लगा है. जदयू की विधायक डॉ. रंजूगीता हर घर दस्तक से लेकर दावते इफ्तार और कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुनावी रीढ़ को मजबूत करने में लगी है. वही राजद से युवा राजद जिलाध्यक्ष चंद्रजीत प्रसाद यादव भी पार्टी नेताओं के इस बयान को लेकर मतदाताओं के दहलीज पर दस्तक दे रहे है कि आसन्न चुनाव में युवा सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जायेगी. इनका दावा है कि पार्टी नेतृत्व युवाओं के साथ नइंसाफी नहीं होने देगी. राजद के ही कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव भी अपनी दावेदारी को लेकर मतदाताओं के चौखट पर अपनी हाजीरी लगा रहे है. उनको भरोसा है कि युवा श्रेणी में इनका नाम भी शामिल है. इनके अलावा पूर्व सांसद सीताराम यादव की पुत्र वधु सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उषा किरण की दावेदारी को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है. राजद खेमा में चल रही चर्चा के मुताबिक पार्टी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी हो रही है. वैसे चुनाव में विलंब है. दल से संभावित प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा से इंकार नहीं किया जा सकता है. उधर भाजपा-लोजपा - रालोसपा गठबंधन ने भी इस सीट पर कब्जा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है. चल रही चर्चा के अनुसार इस सीट पर भाजपा गठबंधन से लोजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में सबीह अहमद चुनाव मैदान में ताल ठोक सकते है. लंबे अर्से से पार्टी के लिए कार्य कर रहे सबीह लगातार क्षेत्र में मतदाताओं के बीच हाजरी लगा रहे है. अब तक इस क्षेत्र से एकमात्र अल्पसंख्यक प्रत्याशी होने के कारण जहां बिरादरी में इनकी चर्चा जोरो पर है, वही दूसरी ओर लोजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पिछडा व दलित मतदाता भी उनके पक्ष में खडा दिखाई दे रहा है. बताया जाता है कि जदयू का कब्जे के बावजूद कुछ पार्टी कार्यकर्ता अपनी दावेदारी को लेकर योजना बनाने में लगे है. वैसे अब तक किसी ने सार्वजनिक तौर पर नाम का खुलासा नहीं किया है, परंतु चुनाव करीब आने के साथ ही कुछ नाम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है.

अब गन्ना मंत्री के क्षेत्र का चुनावी कोल्हू इस बार किस दिशा में घूमेगा इसका अभी सभी को इंतजार है. चुनाव में वक्त के कारण फिलहाल प्रत्याशियों की स्थिति के संदर्भ में विशेष कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा. परंतु इतना तो साफ है कि अबकी बार का चुनावी समीकरण का मिठास किसकी थाली में सजेगा कहा नही जा सकता है. कारण कि अल्पसंख्यक वोटों का विखराव की संभावना कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. वैसे सभी संभावित प्रत्याशी इस सीट से अपना जुगाड़ करने में लगे है.■

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी हलचल

समीक्षा बैठक का आयोजन

सीतामढ़ी शहर के राजेंद्र भवन में जदयू के हर घर दस्तक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. मौके पर पार्टी के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे. कार्यक्रम के दौरान प्रशांत ने बताया कि यह कार्यक्रम सीएम नीतीश कुमार की सोच है. कार्यकर्ता हर घर दस्तक देने में कामयाब होंगे तो सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है. जिलाध्यक्ष रामजीवन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री डॉ रंजूगीता, पूर्व सांसद डॉ अर्जुन राय, विधायक गुड्डी देवी, सरफुद्दीन, विधान पार्षद राज किशोर कुशवाहा, वरीय नेता राजेश चौधरी, राणा रंधीर सिंह चौहान, अरुण कुशवाहा, बब्लू मंडल, संजय सिंह पप्पू, खलील अंसारी, शंकर बैठा, प्रो. अमर सिंह, शोभा देवी व किरण गुप्ता समेत अन्य थे. *– आदित्यानंद*

गीतकार गीतेश को सम्मान

समस्तीपुर शहर के कृष्णा हॉल में पिछले 21 जून को भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सूबे के विभिन्न जिलों के दर्जनों साहित्यकारों को सम्मानित किया गया. सीतामढ़ी जिले के साहित्यकार गीतकार गीतेश को गोपाल प्रसाद व्यास राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान 2015 पूर्व आईएएस अधिकारी सह पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्य द्वारा दिया गया. गीतकार को हास्य – व्यंग्य के क्षेत्र में चर्चित पुस्तक हंसी अप गम डाउन के लिए शॉल, प्रशस्ति पत्र व सरस्वती प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया. समारोह में मौजूद प्रख्यात साहित्यकार डॉ नरेश विकल ने गीतेश की पुस्तक को हास्य-व्यंग्य के क्षेत्र का माइल स्टोन बताया. वहीं सीतामढ़ी जिले के साहित्यकार सत्येंद्र मिश्र, बच्चा प्रसाद विहवल, मुरलीधर झा मधुकर, राम किशोर सिंह चकवा, सुरेश वर्मा, संगीता चौधरी, सुरेश लाल कर्ण, डॉ आनंद प्रकाश वर्मा, डॉ प्रो राज कुमार गुप्ता व पृथ्वीराज राणा समेत अन्य ने बधाई दी है. *– ब्रजेश*

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. शिवहर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित उपवास सह धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रभारी अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने की. मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष मो असद ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है. इस सरकार की गलत नीतियों का कांग्रेस विरोध करती रहेगी. उन्होंने कहा कि बिहार के साथ नाइंसाफी करने वाली सरकार को आम आवाम माफ नहीं करेगी. कार्यक्रम को मुरली मनोहर सिंह, बालदेव प्रसाद, मनोज कुमार, शिव शंकर सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, प्रमोद राय समेत अन्य थे. *– विकास*

क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी का स्थापना दिवस

क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी आगामी नौ अगस्त को स्थापना दिवस समारोह मना रही है. स्थापना दिवस समारोह पटना के दरोगा राय पथ स्थित दरोगा राय स्मारक भवन में आयोजित होगा. उक्त बातें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रीलाल राय ने बतायी. इन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह में आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष चर्चा होगी. पार्टी यह भी तय करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव अपने बल बूते लड़ेगी या किसी गठबंधन के साथ जाएगी. इस मौके पर केन्द्रीय नेता व दिल्ली प्रभारी समीर शर्मा, एवं विश्वजीत कुमार बिहार प्रभारी तथा राज्य सचिव सुशीला देवी उपस्थित रहेंगी. इसके अलावा बिहार के विभिन्न जिलों से भी कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिनमें मुख्यरूप से मधुबनी जिले के नागेन्द्र यादव, मैनेजर यादव, रामेश्वर महतो, राम नरेश यादव, मुनींद्र झा तथा वैशाली जिले के रामचंद्र राय, देवेन्द्र राय, उषा देवी के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहेंगे.■

एक नज़र
चुनावी हलचल

समर्थ फाउंडेशन ने लगाया मेडिकल मेगा कैम्प

समर्थ फाउंडेशन तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किनारी पंचायत भवन में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पटना के कई जाने माने चिकित्सकों ने भाग लिया. कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महाबीर कैंसर अस्पताल की निदेशिका डॉ. मनीषा सिंह एवं डॉ. अरुण ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया. चार हजार लोगों का सफल इलाज इस शिविर में किया गया. शिविर में कई दवा के काउंटर से लोगों ने मुफ्त दवा प्राप्त की. वहीं डेढ़ हजार मरीजों का नेत्र चिकित्सकों द्वारा आंख का इलाज किया गया. वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिलाषा शांडिल्य ने महिलाओं को स्वस्थ रहने का उपाय बताया. इस मौके पर हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉ. अमूल कुमार,जेनरल फिजीशियन डॉ. मानवेन्द्र कुमार तथा नेत्रालय के चार चिकित्सकों ने भाग लेकर लोगों का इलाज किया. इसके अलावा डॉ. ओमप्रकाश कुमार ने हड्डी एवं नस रोगों के बारे में विशेष जानकारी दी. इस मौके पर अंचलाधिकारी नीरज कुमार, समाज सेवी संजय कुमार, संस्था की सचिव नूतन कुमारी, अध्यक्ष नीरज कुमार, कार्यकर्ता शेखर कुमार, नागेन्द्र प्रसाद, शशि शर्मा, सुधीर कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे. *–भारती*

बिहार की जनता भाजपा के साथ : वरुण

बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है. जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह ने कहा है कि एनडीए ने 14 सीट जीत कर यह दिखा दिया है कि जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन पर भाजपा गठबंधन भारी है. इस चुनाव को राज्य में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था. आगे वरुण सिंह ने यह भी बताया कि 14 सीट जीत कर यह साबित हो गया कि बिहार की जनता भाजपा के साथ है. वरुण ने नीतीश को अहंकारी बताते हुए कहा कि बिहार में शिक्षकों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है और नीतीश जी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं. ईद में अल्पसंख्यक टीचर अपने बाल-बच्चों को कपड़े और सेवईयां देने की जगह बहलाने का काम कर रहे हैं. साथ में उन्होंने कहा कि बिहार के किसानों की छह-सात महीने पहले धान खरीद हुई जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई जिससे नाराज सूबे के शिक्षक और किसान आने वाले विधानसभा चुनाव में विधान परिषद के चुनाव से भी खराब स्थिति महागठबंधन का कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन कायम करते हुए बिहार में सरकार बनाएगी. *– रजनीकांत पाण्डेय*

सामाजिक एकता का प्रतीक है पर्व : विधायक

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर की जदयू विधायक गुड्डी देवी ने कहा कि पर्व-त्योहार सामाजिक एकता का प्रतीक है. सामाजिक सद्भाव व आपसी भाईचारा का पैगाम लेकर प्रति वर्ष पर्व हर घर के दहलीज पर दस्तक देता आया है. पर्व के दौरान समाज के सभी तबके के लोगों में एक दूसरे के लिए विश्वास व अपनेपन का एहसास होता है. पिछले दिनों रमजान के दौरान रुन्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित अपने आवास एवं नानपुर प्रखंड के इस्लामपुर गाव में आयोजित दावत ए इफ्तार के मौके पर विधायक ने उपस्थित लोगों से सामाजिक एकता कायम रखने की अपील की. मौके पर वरीय जदयू नेता राजेश चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र सिंह, राम किशोर सिंह, विनोद सिंह, रेयाज खान, नजरे आलम, मेराज आलम, मो बारिक, मो कयूम, भारत भूषण सिंह, मुकेश कुमार व मुकेश शाही समेत अन्य मौजूद थे.■ *– विभा*

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न

सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari

16. |100 यदि $(8)^n$ से पूर्णतः विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा ?
A) 23 B) 22 C) 24 D) 32

17. वह छोटी संख्या क्या है जिसमें लगातार या क्रमागत रूप से क्रमशः 7, 9, तथा 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 और 3 बचे?
A) 847 B) 798 C) 879 D) 897

18. किसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है और प्राप्त भागफल में 13 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। पुनः प्राप्त भागफल में 7 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 है तो संख्या क्या है ?
A) 2489 B) 2499 C) 2500 D) 2371

19. किसी संख्या में लगातार क्रमशः 4, 7 और 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2,3 तथा 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या में भाजक का क्रम बदलकर भाग दें तो शेष क्रमशः क्या होगा।
A) 4,2,2 B) 2,2,4 C) 2,4,2 D) 2,1,4

20. $(6^{133} \times 7^{222} \times 8^{111})$ में अभाज्य गुणनखण्डों की संख्या क्या है ?
A) 820 B) 822 C) 821 D) 823

21. $(40)^{20} \times [50]^{40} \times (60)^{50} \times (7)^{33}$ में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है ?
A) 334 B) 433 C) 343 D) 431

22. विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, भागफल का 3 गुणा तथा शेषफल का 6 गुणा है। तदनुसार, यदि शेष 2 है तो भाज्य क्या है ?
A) 48 B) 36 C) 28 D) 50

23. $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{1}{a-b}$ हो तो $a^3+b^3=?$
A) 2 B) 0 C) -1 D) 1

24. यदि $a-b=3$ तथा $a^3-b^3=117$ हो तो $(a+b)=?$
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9

25. जब n को 6 से भाग दिया जाए तो शेष 4 आता है। जब 2n को 6 से भाग दिया जाय तो शेष क्या आयेगा।
A) 1 B) 2 C) 0 D) 4

26. कोई घड़ी 9 बजे टन-टन करने में 9 सेकेण्ड लेती है तो 11 बजे टन-टन करने में कितना समय लेगी ?
A) 10 से. B) 11 से. C) 11.25 से. D) 10.80 से.

27. यदि कोई घड़ी प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे तो यह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी।
A) 300 B) 156 C) 68 D) 78

28. (-5) X (5E) + (-3) X (3C) = ?
A) 34 B) 35 C) 16 D) -34

29. $a+b+c=15$, $a^2+b^2+c^2=82$ हो तो $a^3+b^3+c^3-3abc=?$
A) 200 B) 180 C) 190 D) 210

30. $\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{72}+\frac{1}{90}=?$
A) $\frac{7}{20}$ B) $\frac{1}{10}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{5}{20}$

सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रथम दस विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा। SMS द्वारा उत्तर 8002817092 पर भेजें
शेष अगले अंक में

विकास के मुद्दे पर होगा चकाई का चुनाव

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बसपा द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी होते ही चकाई में बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. बसपा ने प्रदेश महासचिव पृथ्वीराज हेम्ब्रम उर्फ पौलूश हेम्ब्रम को चकाई विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पृथ्वीराज हेम्ब्रम पिछले चुनाव में भी बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे और 18हजार से अधिक मत लाकर चौथे स्थान पर रहे .बसपा द्वारा उम्मीदवार घोषित किये जाने के बाद पृथ्वीराज हेम्ब्रम ने बताया कि चकाई की जनता लम्बे समय से परिवारवाद की चक्की में पिस रही है. आज तक चकाई की जनता के विकास के लिए पूर्व विधायकों ने कुछ नहीं किया. आज भी चकाई की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जबकि वर्तमान विधायक चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात कर रहे हैं. वे पहले चकाई बाजार की सड़कों की मरम्मत तो करा लें. आज तक चकाई बाजार स्थित निजी बस पड़ाव, शौचालय एवं चापाकल के लिए तरस रहे हैं. साथ ही साथ नाले के अभाव में चकाई नर्क बन गया है. इन सबके बावजूद चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बात वे किस मुंह से करते हैं यह समझ से परे है. आजादी के लम्बे समय बीत जाने के बावजूद भी यहां की जनता को उसका वाजिब हक नहीं मिला है, जिसके लिए यहां के राजनीतिक लोग जिम्मेदार हैं. अब चकाई की जनता जाग चुकी है और वह वशंवाद तथा जाति एंव धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी. पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए हेम्ब्रम ने कहा कि नरेंद्र सिंह नहीं चाहते हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़े. लेकिन मैं घर-घर जाकर सारी बातों से लोगों को अवगत कराऊंगा. यह पूछे जाने पर कि आप चकाई का विकास किस प्रकार करेंगे? उन्होंने बताया कि यदि चकाई की जनता ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं चकाई के लिए वो सब करूंगा जिसके लिए चकाईवासी आज तक तरस रहे हैं.मैं हर घर तक बिजली,स्वच्छ पेयजल तथा हर खेत को पानी दूंगा. साथ ही साथ उद्योग-धंधे के विकास के लिए कार्य करूंगा ताकि चकाई का विकास हो सके. चकाई में अब तक विकास की किरण तक नहीं पहुंच पाई है जबकि यहां के राजनेता लम्बे चौड़े वादे कर अब तक लोगों को बरगलाने में सफल हो गये हैं. लेकिन इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा. मुझे विश्वास है कि चकाई की जनता मुझे विधानसभा में भेजेगी और अगर यहां की जनता ने ऐसा किया तो मैं सूद सहित जनता को वो सब ढूंगा जिसके वे हकदार हैं.■

बोधगया विधानसभा क्षेत्र

लगातार विधायक बनने का कोई रिकॉर्ड नहीं

सुनील सौरभ

पूरी दुनिया में बौद्ध धर्मावलम्बियों के आस्था स्थल तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रुप में प्रसिद्ध बोधगया विधानसभा क्षेत्र से पिछले चार दशक में लगातार किसी व्यक्ति के विधायक होने का कोई रिकार्ड नहीं रहा है. इस बात को माना जाये तो बोधगया के भाजपा के वर्तमान विधायक श्यामदेव पासवान का भविष्य ठीक नहीं कहा जा सकता है. ऐसे राजनीति और बिहारी मतदाताओं के रुख का पता लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है. बोधगया अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र लगातार रहा है. 1977 में यहां जनता पार्टी के टिकट पर राजेश कुमार जीते थे. 1980 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बालिक राम तो 1985 में पुन: लोकदल के टिकट पर राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी. 1990 में फिर भाकपा के बालिक राम बोधगया के विधायक बने. 1995 में निर्दलीय मालती देवी विधायक बनी. 2000 में जीतन राम मांझी राजद से विधायक बने. फरवरी 2005 में राजद के ही फूलचंद मांझी विधायक बने. लेकिन अक्टूबर 2005 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा के हरि मांझी तथा नवंबर 2010 में भाजपा के ही श्यामदेव पासवान विधायक बनें. इस प्रकार किसी एक व्यक्ति को लगातार विधायक बनने का बोधगया के इतिहास भी श्याम देव पासवान को दोबारा विधायक बनने के सवाल पर संशय खड़ा करता है. बोधगया विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक चौकानें वाली चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रिमों जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को भाजपा प्रत्याशी बना सकती है. इस प्रकार यहां भाजपा अपने ही दल के कार्यकर्ताओं के परस्पर विरोधी शिकवा-शिकायतों में उलझी है. ऐसी परिस्थिति में राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी का मुकाबला कठिन जरूर होगा. गठबंधन मे यह सीट राजद के खाते में जा सकती है.

जितेन्द्र कुमार 2000 के चुनाव में फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रुप मे चुनाव लड़ चुके हैं. फिलहाल ये प्रदेश युवा राजद के महासचिव है और पूर्व मंत्री राजद विधायक डा0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव का समर्थन प्राप्त है. रविदास जाति से आने कें कारण राजद गंठबंधन में जितेन्द्र कुमार अपनी मजबूत स्थिति का दाबा कर रहे हैं.

राजद से टिकट के लिए लोजपा छोड़ चुके पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार के पूर्व विधायक पुत्र कुमार सर्वजीत तथा कांग्रेस छोड़ कर राजद में आ चुके जितेन्द्र कुमार का नाम मुख्य रूप से आ रहा है. जितेन्द्र कुमार 2000 के चुनाव में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप मे चुनाव लड़ चुके हैं. फिलहाल ये प्रदेश युवा राजद के महासचिव है, और पूर्व मंत्री राजद विधायक डा. सुरेन्द्र प्रसाद यादव का समर्थन प्राप्त है. रविदास जाति से आने के कारण राजद गंठबंधन में जितेन्द्र कुमार अपनी मजबूत स्थिति का दाबा कर रहे हैं. वहीं दुसरी ओर पूर्व विधायक कुमार सर्वजीत लोजपा छोड़कर राजद कर हाथ थामने और लोजपा को सबक सिखाने के लिए राजद से टिकट मिलने पर मजबूत समीकरण के कारण अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. यहां से इनके पिता स्व. राजेश कुमार दो-दो बार विधायक तथा गया सांसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं. उपचुनाव में खुद कुमार सर्वजीत भी जीत कर विधायक बन चुके हैं. ऐसी स्थिति में राजद से यदि टिकट मिला तो अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रहे हैं. उनका दावा है कि यदि राजद ने उन्हें बोधगया क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया तो इसका लाभ गया जिले के सभी दस विधानसभा क्षेत्र पर पड़ेगा. क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोट पासवान जाति का है. और मगध में पासवान जाति के लोग पूर्व सांसद स्व. राजेश कुमार को मानते रहे थे. ऐसा कुमार सर्वजीत के समर्थकों का कहना है. बोधगया विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल प्रत्याशी के मामले में दोनों गठबंधनो की तस्वीर साफ नहीं है. लेकिन इतना तय है राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन सें कोंई प्रत्याशी आये भाजपा प्रत्याशी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा.■

मतदाताओं ने कोई मौका नही दिया. 2009 मे जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हरि मांझी गया के सांसद हो गये तो उन्होनें विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था. तब हुए उपचुनाव में पूर्व सासंद स्व.राजेश कुमार के पुत्र कुमार सर्वजीत लोजपा के टिकट पर विधायक बने थे. लेकिन 2010 के चुनाव मे वे हार गये. पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति बहुल बोधगया सुरक्षित क्षेत्र से संभावना है कि भाजपा अपना प्रत्याशी बदल दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा. इसका मुख्य कारण है कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ता विधायक श्यामदेव पासवान के कार्यकलाप से नाराज है. ऐसे में यदि सिटिंग के नाम पर श्यामदेव पासवान को टिकट मिल भी गया तो राजद-जदयू-कांग्रेस गंठबंधन से मुकाबला करना काफी कड़ा होगा. वहीं दूसरी ओर बोधगया विधानसभा क्षेत्र का

feedback@chauthiduniya.com

सीवान में चढ़ने लगा चुनावी पारा

विधायकों ने अपनी मद से आधा दर्जन पानी टंकी का निर्माण, दहा नदी पर छह बड़े पुल, सोना नदी में चनुर, भंटापोखर व मकरियार में कई छोटे पुलों का निर्माण करवाया गया. इसके अलावा शहर के बीचों-बीच आधुनिक पार्क का निर्माण, चारों तरफ बिजली की चमकती रोशनी तथा जनता के सभी सुख-दुख में उपलब्ध रहने को ही विधायक अपनी प्राथमिकता मानते है. विरोधियों का कहना है कि विधायक राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी सीवान सदर अस्पताल के लिए कुछ खास नहीं कर सके. कुछ विरोधियों का कहना है कि शहर में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों पर विधायक अंकुश नहीं लगा सके.

शम्भू प्रसाद अभय

भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व मौलाना मजहरूल हक की जन्मस्थली सीवान जिले का नाम वैसे तो विभिन्न रूपों में विश्व स्तर पर चर्चा में रहता है, वहीं राजनीतिक शह व मात के खेल में भी सीवान देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है. अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गयी है तो, इसकी गड़गड़ाहट से सीवान भला कैसे अछूता रहेगा? यहां भी चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ने लगी है. सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र जिसमें की शहरी इलाका आता है, यहां यह सरगर्मी काफी बढ़ने लगी है. इस सीट पर कभी जनता पार्टी, कभी कम्युनिस्ट, कभी कांग्रेस तो कभी जद, भाजपा, राजद आदि का दबदबा रहा, इस बार इस सीट पर पिछले एक दशक से भाजपा का कब्जा है. ब्यासदेव प्रसाद इसके पहले इसी सीट से जीते तो वे राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद्भार संभाला. इस बार भी वे विधायक निर्वाचित हुए, लेकिन मंत्रीमंडल में स्थान नहीं मिल सका. प्रसाद का यह दूसरा कार्यकाल है. इसके चलते जनता को भी इनसे काफी उम्मीदें है. सीवान विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 227240 है. विगत चुनाव में भाजपा, जदयू गठंबंधन के उम्मीदवार ब्यासदेव प्रसाद को 51,637 मत मिला था, वहीं राजद के उम्मीदवार व पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी को 39,096 मत मिला. इस प्रकार 12541 मतों के अंतर से प्रसाद विजयी हुए थे. लेकिन इस बार राजनीतिक गणित कुछ बदला-बदला सा दिख रहा है. भाजपा के पुराने साथी जदयू का गठबंधन टूट चूका है तथा राजद व जदयू का गठजोड़ हुआ है, जिसके चलते विभिन्न वोटों के बिखराव के आसार दिख रहे है. बावजूद इसके, भाजपा, लोजपा व रालोसपा गठबंधन की ओर से निवर्तमान विधायक ब्यासदेव प्रसाद के अलावा कई अन्य नेता चुनाव लड़ने के मूड में है. कई नेता तो टिकट के जुगाड़ के लिए दिल्ली, पटना का दौड़ लगा रहे है. वहीं राजद, जदयू गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री सह जदयू नेता अवध बिहारी चौधरी, राजद नेता लीलावती गिरी, कांग्रेसी नेता हरेन्द्र दूबे, जदयू नेता विनोद सिंह कुशवाहा, के अलावा विभिन्न दलों के विभिन्न नेता टिकट के लिए हाथ-पैर मार रहे है. कांग्रेस नेता हरेन्द्र दूबे का कहना है कि हमको टिकट मिले न मिले हम जनता के आशीर्वाद व सहयोग से चुनाव लड़ेगें. मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूं, चुनाव लड़ूंगा. उन्होनें कहा कि वर्तमान विधायक द्वारा क्षेत्र में लकड़ी दरगाह पानी टंकी को नहीं चालू करवाया जा सका, मनवर टोला, त्रिलोका हाता के अलावा अन्य कई गांवो में विद्युतिकरण कार्य नहीं किया गया. दूबे नें कहा कि जनता इस बार सही समय पर जवाब देगी. पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी का कहना है कि जनता मालिक है, सब देख रही है, जवाब देगी. विधायक द्वारा कुछ वैसे विकास कार्यो को करवाया गया जिसकी प्रतीक्षा वर्षो से थी. विधायक ने अपने मद से आधा दर्जन पानी टंकी का निर्माण, दहा नदी पर छह बड़े पुल, सोना नदी में चनुर, भंटापोखर व मकरियार में कई छोटे पुलों का निमार्ण करवाया गया. इसके अलावे शहर के बीचों-बीच आधुनिक पार्क का निर्माण, चारों तरफ बिजली की चमकाती रोशनी तथा जनता के सभी सुख-दुख में उपलब्ध रहने को ही विधायक अपनी प्राथमिकता मानते है. विरोधियों का कहना है कि विधायक राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी सीवान सदर अस्पताल के लिए कुछ खास नहीं कर सके. कुछ विरोधियों का कहना है कि शहर में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों पर विधायक अंकुश नहीं लगा सके.

वही, विधायक ब्यासदेव प्रसाद का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए चार करोड़ रूपये की अनुशंसा की गई, 1.17 करोड़ में पंचमंदिरा पोखरा का सौकरण, 1.14 करोड़ में गांधी मैदान पोखरा का सुंदरीकरण, दो करोड़ में दहा नदी पर छ: बड़े पुल का निर्माण करवाया जा सका. इसके अलावा विधायक द्वारा कई अन्य छोटी-बड़ी योजनाओं को भी पूर्ण किया गया. उन्होनें कहा कि विधानसभा में 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 95 सवाल भी किये. उन्होनें कहा कि मैं हमेशा जनता के बीच रहा तथा जनता के सुख-दुख में शामिल रहा, जनता मेरे साथ है.

बहरहाल विधान परिषद के चुनाव में भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार टुन्नाजी पांडेय की जीत के बाद भाजपा गठबंधन सेमी-फाइनल मान कर जश्न मनाते हुए विधानसभा के चुनाव में अपने जीत का दावा ठोक रही है. वहीं राजद, जदयू गठबंधन के उम्मीदवार विनोद जयसवाल के पराजय के बाद राजद व जदयू विधानसभा के चुनाव को लेकर अपनी सजगता व सक्रियता को बढ़ाते हुए विभिन्न पहलुओं पर चिंतन शुरू कर दिया है. अब देखना यह है कि किस दल के किस महारथी को चुनावी समर में उतारा जा रहा है. मतदाता तो काफी चलाखी के साथ सभी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है.■

feedback@chauthiduniya.com

बंद पड़ी चीनी मिल को चालू कराने का मामला बनेगा मुद्दा

विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट से एक बार फिर बंद पड़ी हथुआ चीनी मिल को चालू करने की मांग उठने लगी है. लगभग 20 वर्षो से बंद चीनी मिल के कई कर्मी मौत के मुंह में जा चूके है. मिल चालू होने की राह देखते कई कर्मियों की आंखे पथरा गयी, लेकिन मिल चालू नहीं हो सकी. वर्ष 2005 की एक चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार नें चीनी मिल को चालू करने की घोषणा की और यहां तक कह दिया कि सत्ता में आने के बाद मिल को चालू किया जाएगा. चुनाव भी बीत गये और नीतीश कुमार सत्ता में भी आए, लेकिन बंद हथुआ चीनी मिल चालू नहीं हो सकी. इस बात का मामला सबसे ज्यादा मिलकर्मियों व गन्ना कास्कारों को है, जिनका अभी भी करोड़ों रूपये बकाया है. वर्ष 1996-97 के मार्च माह में मिल में तालाबंदी हुई. इसके बाद मिल कर्मी लगातार आर्थिक तंगी से मौत के शिकार बनते गये. आज हालात यह है कि 1600 कर्मियों की जगह पर महज 32 ही कर्मी कार्यरत है. हथुआ अनुमंडल सहित यूपी से भी गन्ना की आपूर्ति इस मिल को की जाती थी. आज मिल विरान है. रोज चोरी की घटनाएं होती है. लेकिन सूबे की सरकार इसकी सुधी तक नहीं ले रही. इसका कारण मिल में लगे करोड़ो रूपये की मषीन जंग खा रही है. मिल का आवासीय परिसर भी टुट चुका है. जिसमें कुछ कर्मी रहते है. मिल के बंद होने के कारण इस क्षेत्र के किसान गन्ना की खेती तक करना छोड़ दिया है. लगभग 20 सालों से बंद चीनी मिल का दंश झेल रहे कर्मी व किसान इस बार इस मुद्दे को चुनाव में पुरजोर ढंग से उठाने का मुंड बना लिया है. मिल के चालू नहीं होने से जनता गुस्से में है जो इस बार राजनेताओं को झेलनी पड़ेगी. आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मुद्दे को विपक्ष के नेाओं नें भी गंभीरता से नहीं उठाया. जिससें सरकार को घेरा जा सके. अब मौका आ गया है लेागों के सामने नेताओं के आने का.

- ओमप्रकाश मिश्र

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

27 जुलाई –02 अगस्त 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

कानपुर में अमित शाह का विरोध, स्थानीय सांसद समेत कई लोग सम्मेलन में नहीं आए

दिल नहीं जीता, यूपी कैसे जीतेंगे

अंशुमान प्रांजल

पूरा प्रदेश जीत लेने का दावा ठोकने वाले अमित शाह अपने वरिष्ठ नेताओं का दिल जीत नहीं पा रहे हैं. कानपुर में पार्टी का सम्मेलन हो और कानपुर का सांसद सम्मेलन में शरीक न हो, यह भाजपा के लिए कम चिंता का विषय नहीं है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कुछ अन्य राजनीतिक दलों का विरोध झेलना पड़ा, यह अलग बात है, लेकिन कानपुर के सांसद और भाजपा के अत्यंत वरिष्ठ नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी बिना किसी वजह के सम्मेलन से गैरहाजिर रहे, यह पार्टी में अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है. भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक कमजोरियां धीरे-धीरे कुल कर सामने आ रही हैं. पार्टी में विद्रोह का तानाबाना बुना जा रहा है. सम्मेलन में नहीं पहुंचने वालों में अकेले डॉ. मुरली मनोहर जोशी ही नहीं, बल्कि गैरहाजिर सांसदों में वरुण गांधी, मेनका गांधी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं. जबकि उत्तर प्रदेश से चुने गए भाजपा के सभी सांसदों को इस बैठक में शामिल होने को कहा गया था.

मुरली मनोहर जोशी तो कानपुर से ही सांसद हैं. फिर भी वे शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं आए. मेनका पीलीभीत से और वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं. महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हैं. डॉ. जोशी कई मौकों पर भाजपा और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर अपनी नाखुशी जता चुके हैं. कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी उन्होंने घेरा था. उन्होंने गडकरी की नदियों में जहाज चलाकर कारोबार को बढ़ावा देने की स्कीम की भी जमकर खिल्ली उड़ाई थी. हद तो यह भी हो गई जिस संजय जोशी के नाम पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बुखार आ जाता है, उन संजय जोशी को पार्टी की मुख्य धारा में वापस लाने की खुले तौर पर मांग की गई. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिशन-2017 लेकर कानपुर तो पहुंचे, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं के विरोध से मुखातिब होना पड़ा. सम्मेलन के पहले ही अमित शाह के खिलाफ आवाज उठी और कुछ लोगों ने तो मोदी और शाह के पोस्टर पर कालिख पोत दी. कार्यक्रम स्थल पर ही कुछ कार्यकर्ताओं ने शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पूर्व संगठन मंत्री संजय जोशी की भाजपा में वापसी की मांग की. पोस्टर पर कालिख पोते जाने की घटना को अमित शाह ने निंदनीय करार देते हुए कहा कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे कुकृत्य करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मिशन-2017 के तहत महासम्पर्क अभियान की समीक्षा करने पिछले दिनों कानपुर आए थे. सम्मेलन में भाजपा ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली पर समाजवादी सरकार को खूब लताड़ा और शाहजहांपुर में पत्रकार और बाराबंकी में महिला को जिंदा जला कर मार डालने की घटना को इंतिहा बताया. अमित शाह ने अपने स्वागत भाषण में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, गुंडों का राज है. भाजपा अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पांच सदस्यीय जांच कमेटी के गठन का ऐलान भी किया, जिसमें बिहार के सांसद अश्विनी चौबे, पार्टी के प्रवक्ता एमजे अकबर, राजस्थान के सांसद अर्जुन मेघवाल और दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को शामिल किया गया है. टीम अपनी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपेगी.

अमित शाह प्रदेश में भाजपा के सदस्यता अभियान की उपलब्धि पर खुशी जताई और कहा कि पार्टी ने देशभर में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था लेकिन सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के पास पहुंच गई. भाजपा दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन गई है. भाजपा की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने प्रदेश में एक करोड़ 86 लाख सदस्य बनाए. भाजपा नेता ने स्थानीय सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नहीं आने के सवाल को टाल दिया. बैठक में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा साक्षी महाराज, जगदम्बिका पाल समेत कई नेता मौजूद थे. समीक्षा बैठक को इतना गुप्त रखा गया था कि उद्घाटन सत्र में फोटो खींचने के लिये प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के केवल कैमरामैनों को अंदर बुलाया गया था. दस मिनट बाद फोटो खींचने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया. केवल एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत दी गई, जो शाह के साथ ही आया था.

सम्मेलन के ठीक पहले कानपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टरों पर स्याही पोती हुई पाई गई. भाजपा के शहर अध्यक्ष सुरेन्द्र मैथानी ने कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने माल रोड, वीआईपी रोड, जाजमऊ तथा शहर के अन्य इलाकों में लगाए गए प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो वाले पोस्टरों और होर्डिंगों में से कई पोस्टरों और होर्डिंग्स पर स्याही पोत दी. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कानपुर पहुंचने पर गंगा पुल पर भव्य स्वागत किया गया, लेकिन उनके स्वागत कार्यक्रम में भी भाजपा की जिला इकाई की गुटबाजी साफ दिखाई दी. शाह के स्वागत के लिए जिला कमेटी ने जाजमऊ में मंच बनाया था. पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्र और भाजपा विधायक सतीश महाना समेत कई नेता विराजमान थे. दूसरे गुट के विवेकशील शुक्ला वगैरह ने शाह के काफिले को गंगा पुल से पहले ही रोक लिया और वहीं पर शाह का स्वागत कर दिया.

इसके बाद शाह का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुआ, तो कानपुर शहर में मोतीझील के पास संजय जोशी के समर्थन में भाजपाइयों ने खूब नारेबाजी की. ये लोग संजय जोशी की पार्टी में सम्मानजनक बहाली की मांग कर रहे थे. इसके बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह होटल कान्हा गैलेक्सी पहुंचे और वहां भाजपा का महासंपर्क अभियान का समीक्षा कार्यक्रम शुरू हो सका. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी वगैरह मौजूद थे. कार्यक्रम स्थल के बाहर सपा और आप के कार्यकर्ताओं ने झाड़ू और झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

सम्मेलन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही पार्टी के नेतृत्वकारी चेहरे होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी. माथुर बोले कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के तहत यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के किसी एक शख्स का चेहरा नहीं होगा, बल्कि पूरा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा. यूपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही आगे होगा. यूपी में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा. भाजपा के लाखों कार्यकर्ता मोदी के विकास कार्यों को घर-घर तक पहुंचाएंगे. प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है. अब यूपी में भाजपा को अगली सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यपाल को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को पद से हटाने संबंधी अपीली याचिका खारिज कर दी है. इसमें कहा गया था कि नाईक ने पिछले साल दिसंबर में संवैधानिक पद पर रहते हुए अयोध्या में मंदिर बनाने की वकालत की थी, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है. इसलिए वे पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. एनजीओ सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी ने इससे पहले जनवरी में यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि इस पर सुनवाई उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यपाल के पद पर बने रहने के मामले की रिट की जांच नहीं की जा सकती.

अमित शाह ने दी खुली धमकी

मिशन यूपी की शुरुआत करने कानपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जब विरोध और पोस्टरों पर कालिख की करतूतों से रूबरू होना पड़ा, तो उनकी नाराजगी छुप नहीं पाई. सांसदों की अनुपस्थिति भी उन्हें गहराई से रुष्ट कर रही थी. शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की जमकर क्लास ली और उनके सामने हर हाल में जीत हासिल करने का लक्ष्य रख दिया. शाह ने यह साफ किया कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे. मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया जाएगा. बैठक में शाह ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के पार्टी सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को कसा और कहा कि यहां जितने भी सांसद बैठे हैं, सभी इससे पहले चुनाव हारे हुए हैं. इस बार जीते हैं, तो मोदी की छवि के कारण. इसलिए प्रधानमंत्री की गुड लिस्ट में रहना है, तो पंचायत चुनाव में दल, बल और बाहुबल, सब लेकर मैदान में कूद पड़ना होगा. कुछ भी करें, लेकिन चुनाव में जीत लाकर दिखाएं वरना अपना परिणाम समझ लें. शाह ने कहा कि पार्टी के सांसद और विधायक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे. बैठक के दौरान कुछ सांसदों ने ना-नुकुर करने की कोशिश की, तो शाह ने सख्त लहजे में कहा कि चुनाव में जीतकर सांसद, विधायक आप लोग बनेंगे और जनता की बीच डंडा खाने कोई दूसरा जाएगा. ऐसा कतई नहीं चलेगा. अमित शाह बोले कि हर सांसद का हिसाब-किताब लिया जाएगा. यदि किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो हाथ उठाए. जब किसी सांसद ने हाथ नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि डर की वजह से हाथ नहीं उठा रहे हैं या मन में कुछ और करने का इरादा है. शाह के तेवर देख कर हॉल में सन्नाटा पसरा रहा. शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि एक अकेले नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में रात दिन घूमकर इतनी भारी संख्या में जनाधार इकट्ठा किया, तो क्या हम उन्हें अपनी तरफ से आने वाले चुनाव में जीत का तोहफा नहीं दे सकते? हमको यह तोहफा देना ही होगा. ■

चार बने एमएलसी, पांच लटके

समाजवादी पार्टी की ओर से नामित चार विधान परिषद सदस्यों ने 15 जुलाई को विधान परिषद सदस्यता की शपथ ली. इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती को वर्जिनिटी टेस्ट कराने की आपत्तिजनक सलाह देने वाली उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा भी शामिल हैं. विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडेय ने लीलावती कुशवाहा, एसआरएस यादव, रामवृक्ष यादव और लालू प्रसाद यादव के समधी जीतेंद्र यादव को विधान परिषद की सदस्यता की शपथ दिलाई. लीलावती कुशवाहा ने कहा था कि मायावती को अपना कौमार्य (वर्जिनिटी) परीक्षण कराकर यह साबित करना चाहिए कि वे श्रीमती हैं या कुंवारी. लीलावती ने मायावती को यह नसीहत मुलायम सिंह के उस बयान के बाद दिया था, जिसमें मुलायम ने कहा था कि मुझे पता नहीं मैं मायावती को श्रीमती कहूं या कुमारी? उन्होंने यहां तक कह डाला कि दुनिया को मालूम है, मायावती कुंवारी नहीं हैं. उनके इस बयान की चौतरफा निंदा हुई थी. शपथ ग्रहण समारोह विधान भवन में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत मंत्री और विधायक मौजूद थे. विधान परिषद में बीते 25 मई से विधान परिषद की नौ सीटें खाली हैं. सपा के कोटे से विधानपरिषद में नौ सदस्य चुने जाने थे, लेकिन राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधान परिषद सदस्यों के नौ नामों की लिस्ट में से पांच नाम वापस लौटा दिये थे. राज्यपाल ने सिर्फ चार नाम पर अपनी सहमति जताई थी. शेष पांच नाम काफी विवादास्पद रहे हैं. पांच नामों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है. ■

संघ की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम कम जुटे

उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा इफ्तार पार्टी दी गई, लेकिन उसमें रोजेदार कम जुटे. संघ की इकाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से लखनऊ में यह इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी. आयोजक महिरज ध्वज सिंह की ओर से दावा किया गया था कि यूपी में इस पहली इफ्तार पार्टी में करीब डेढ़ सौ लोग जुटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पार्टी में महज 50 लोग शामिल हुए होंगे. संघ की इफ्तार पार्टी में सिर्फ तीन मौलाना हामिद अली जैदी, मौलाना शबाब और मौलाना सैयद शारिब नकवी शरीक हुए. मौलाना हामिद अली ने कहा कि यदि कोई प्यार से बुलाए तो इंकार नहीं करना चाहिए.

17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मामला

अखिलेश वोट की राजनीति कर रहे हैं

एसआर दारापुरी (पूर्व आईपीएस)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा. इसके पूर्व कैबिनेट की एक उप समिति बनाई गई थी, जिसने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने सम्बन्धित पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के केंद्र सरकार से सिफारिश की. इस पर बसपा और भाजपा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए उप समिति बनाए जाने का विरोध किया था और विधानसभा से बहिर्गमन भी किया था. दोनों पार्टियों का कहना था कि सरकार मामले को लटकाने के लिए उपसमिति बना रही है. लेकिन आखिरकार प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण उपलब्ध है. अतः इसे डॉ. छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पिछड़ी जातियों को तीन हिस्सों में बांट कर उपलब्ध आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में बांटना अधिक न्यायोचित होगा. इससे अति पिछड़ी जातियों को अपने हिस्से के अंतर्गत आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा.

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मुलायम सिंह की सरकार ने 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची तथा तीन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए शासनादेश जारी किया था जिसे अम्बेडकर महासभा तथा अन्य दलित संगठनों द्वारा न्यायालय में चुनौती देकर रद्द करा दिया गया था. 2007 में सत्ता में आने पर मायावती ने भी इसी प्रकार से 16 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी थी. इस पर केंद्र सरकार ने इसके औचित्य के बारे में सूचनाएं मांगी थीं. केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया था.

अब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसी प्रस्ताव को केंद्र के पाले में डाल दिया है. स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा, दोनों पार्टियां इन पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कराकर उन्हें आरक्षण का लालच देकर उनका वोट प्राप्त करने की राजनीति कर रही हैं. राजनीतिक दल अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने अथवा उसे सूची से निकालने का अधिकार केवल संसद को है. राज्य सरकार औचित्य सहित केवल अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को भेज सकती है. इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से परामर्श के बाद संसद के माध्यम से किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है. संविधान की धारा-341 में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करके संसद द्वारा कानून पास करवा कर इस सूची में किसी जाति को शामिल करा सकता है. इसमें राज्य सरकार को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है. वास्तव में यह पार्टियां अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेज कर उनके माथे ठीकरा फोड़ कर अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं. यह केवल अति पिछड़ी जातियों को गुमराह करके वोट बटोरने की राजनीति है, जिसे अब शायद वे जातियां भी बहुत अच्छी तरह से जान गई हैं.

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव की सपा सरकार अथवा मायावती की बसपा सरकार द्वारा जिन अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में डालने की जो संस्तुति पहले की गई थी अथवा अब की गई है, वह मान्य इसलिए नहीं होगी, क्योंकि यह जातियां अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करतीं. यदि सपा सरकार इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ वास्तव में देना चाहती है (जो वर्तमान में उन्हें पिछड़ों में समृद्ध जातियों यादव, कुर्मी और जाट आदि के कारण नहीं मिल पा रहा है) तो इन जातियों की सूची को दो या तीन हिस्सों में बांट कर उनके लिए 277 के आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में बांट देना चाहिए. देश के अन्य कई राज्य बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है. मंडल आयोग में भी इस प्रकार की संस्तुति की गई थी.

उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में 1975 में डॉ छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा आयोग गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी थी. लेकिन इस रिपोर्ट पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. साथी आयोग ने पिछड़े वर्ग की जातियों को तीन श्रेणियों में निम्न प्रकार से बांटने तथा उन्हें 29.57 आरक्षण देने की संस्तुति की थी.

अ श्रेणी में उन जातियों को रखा गया था जो पूर्ण रूपेण भूमिहीन, गैर-दस्तकार, अकुशल श्रमिक, घरेलू सेवक हैं और हर प्रकार से ऊंची जातियों पर निर्भर हैं. इनको 177 आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी.

ब श्रेणी में पिछड़े वर्ग की वह जातियां शामिल हों, जो कृषक या दस्तकार हैं. इनको 107 आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी. .

स श्रेणी में मुस्लिम पिछड़े वर्ग की जातियां हों, जिनको 2.57 आरक्षण देने की संस्तुति की गई थी.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए 277 आरक्षण उपलब्ध है. अतः इसे डॉ. छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पिछड़ी जातियों को तीन हिस्सों में बांट कर उपलब्ध आरक्षण को उनकी आबादी के अनुपात में बांटना अधिक न्यायोचित होगा. इससे अति पिछड़ी जातियों को अपने हिस्से के अंतर्गत आरक्षण मिलना संभव हो सकेगा. इन अति पिछड़ी जातियों को यह भी समझाना होगा कि सपा सरकार इन अति पिछड़ी जातियों को इस सूची से हटा कर अपनी समृद्ध जातियों यादव, कुर्मी और जाट के लिए आरक्षण बढ़ाना चाहती है और उन्हें अनुसूचित जातियों से लड़ाना चाहती है. अतः उन्हें सपा और बसपा की इस चाल को समझाना चाहिए और उनके झांसे में न आकर डॉ. छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अपना आरक्षण अलग कराने की मांग उठानी चाहिए. इसी प्रकार कुछ जातियां जो वर्तमान में अनुसूचित जातियों की सूची में हैं, लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में होना चाहिए, उन्हें सपा सरकार से एक आयोग बना कर उनकी स्थिति का आकलन करवा कर भारत सरकार को सिफारिश भेजने की मांग उठानी चाहिए, तभी इन जातियों को भी उचित न्याय मिल सकेगा वरना वे इन पार्टियों द्वारा झूठे आश्वासन के द्वारा इसी तरह ठगे जाते रहेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

अस्पृश्यता का आधार तलाशना अव्यवहारिक

आरक्षण के मुद्दे पर गोरखपुर में हाल ही में हिंसक हो गए निषाद आंदोलन को लेकर फिर से सरगर्मी शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है. निषाद समेत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव एक बार फिर केंद्र सरकार के समक्ष भेज दिया गया है. [illegible]

– सूफी बाबावर

अब दिल्ली घेरने की तैयारी

अखिल भारतीय मछुआ महासंघ 29 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहा है. यानी, आंदोलन को तीव्र गति देने की पूरी तैयारी है. [illegible] चाहिए. दलित समाज के लोगों के पास तो पक्के घर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मछुआरों की एक नहीं, हजारों ऐसी बस्तियां हैं, जहां पर एक भी पक्का मकान नहीं है. आजादी के 60 साल बाद भी उनकी स्थिति यही है. इन जातियों के लोगों का आज भी पूरे प्रदेश में एक भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी नहीं है और सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या मात्र 0.01 प्रतिशत है.

रेणुका रावत ने दी इफ्तार पार्टी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लेकर अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने का काम किया है. धर्मनगरी हरिद्वार में हरीश की धर्मपत्नी रेणुका रावत की इफ्तार पार्टी में धर्मगुरुओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री हरीश रावत इफ्तार पार्टी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. उन्होंने सभी रोजेदारों को रमजान की मुबारकवाद देते हुए कहा कि दुआ करो कि सब में कौमी एकता एवं भाईचारा बना रहे, और सब प्रेम और मोहब्बत से एक अच्छा प्रदेश बनाएं. उन्होंने रोजा इफ्तार कार्यक्रम में आए सभी सम्प्रदायों के लोगों का रोजा इफ्तार पार्टी में शरीक होने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मौका सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर कौमी एकता बनाने का है. उन्होंने कहा कि यही वह महीना है, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हमे कुरान शरीफ जैसा पवित्र धर्म ग्रन्थ दिया. यह महीना हमें ऐसा माहौल देता है जिसमें हम एक दूसरे के दिल में प्यार और मोहब्बत को और मजबूत बना सकते हैं. उन्होंने सभी से अच्छा हरिद्वार बनाने की अपील की. इस अवसर पर कार्यक्रम की आयोजक रेणुका रावत ने सभी रोजेदारों को रमजान की मुबारकवाद देते हुए कहा कि कौमी एकता एवं आपसी भाईचारे का यह पर्व सभी को सौहार्द, आपसी सद्भाव एवं प्रेम का संदेश देता है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

हरेला के अवसर पर 19 मिनट में एक लाख से अधिक पौधे लगाए

हरीश रावत सरकार ने पौध रोपड़ कार्यक्रम को जिस तरह सामाजिक सरोकार से जुड़े पर्व हरेला से जोड़ कर इसे जन अभियान का रूप दिया है, उनकी यह कोशिश रंग ला रही है. उत्तराखंड के कुमाऊं में बेशक हरेला वीक मनाया गया हो. हर जगह पौधे लगाने के लिए अभियान चल गए हों, लेकिन 130 इन्फैंट्री बटालियन ने 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरेला मनाकर 19 मिनट में 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर अपनी इस उपलब्धि को लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है. बटालियन ने यह कारनामा विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, कैमलिन इंडिया संस्था और वन विभाग के सहयोग से पिथौरागढ़ के निकट ग्यारदेवी में कर दिखाया.

वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी इन्फैंट्री ने आवेदन किया है. बटालियन अब एक दिन में 10 लाख पौधे रोपने की तैयारियों में जुटी हुई है. कासनी सैन्य छावनी स्थित बटालियन ऑफिस में कमान अधिकारी कर्नल नंदु कुमार बीएन ने पत्रकारों को ग्यारदेवी मंदिर के सामने वाली पहाड़ी में किए गए पौधरोपण को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की जानकारी दी.■

चौधरी अजीत सिंह ने फिर छेड़ा यूपी बंटवारे का राग

मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा प्रदेश

दीनबंधु कबीर
feedback@chauthiduniya.com

चौधरी अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का फिर से राग छेड़ा है. अजीत सिंह ने सीधे नहीं कहा कि अखिलेश यादव से यूपी जैसा बड़ा राज्य संभल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने यह साफ-साफ कहा कि सत्ता का बटेर ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गया है, जिसकी सोच सैफई और अधिकतम मैनपुरी तक ही जाती है. स्पष्ट है कि चौधरी अजित सिंह ने यह बात अखिलेश यादव के लिए ही कही है.

प्रदेश की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी उत्तराखंड बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश का और बंटवारा नहीं चाहती. लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश को टुकड़ों में विभाजित करने की मांग दोहराती रही हैं. अब जबकि यूपी में भी विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो चौधरी अजीत सिंह का लखनऊ आकर उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों में बांटने की मांग दोहराना और उसके लिए आंदोलन को मजबूत करने का ऐलान करना महत्वपूर्ण है. कानून व्यवस्था के फ्रंट पर ध्वस्त समाजवादी सरकार के सामने अब प्रदेश को और छोटा करने की मांग परेशान करेगी, क्योंकि अब आम लोगों को भी लगने लगा है, कि प्रदेश और छोटा होगा तो कानून व्यवस्था से लेकर अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं अधिक सुचारू हो पाएंगी.

लखनऊ के सहकारिता भवन के चौधरी चरण सिंह सभागार में राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले दिनों राज्य पुनर्गठन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया. राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे. चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग आज की नहीं है. जब उत्तरांचल और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे तभी से विकास की दृष्टि से राज्य के पुनर्गठन की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि 1912 में बंगाल बिहार ओड़ीशा एक राज्य हुआ करता था. 1936 में बिहार से अलग हुआ और महाराष्ट्र से गुजरात बना. इतना ही नहीं, तेलंगाना की लड़ाई 50 वर्षों से हिसंक और अहिंसक दोनों तरीकों से चली, जिसमें कई जानें भी गई. उस समय तेलंगाना राज्य गठन के विरोधी गांव में नहीं घुस पाते थे. चौधरी अजीत सिंह ने छोटे राज्यों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि छोटे राज्यों के गठन से तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और शासक और शासित के बीच सीधा संवाद सम्भव हो जाता है. इससे प्रजातंत्र का अर्थ साबित होता है. उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर देश में गणना की जाए तो उत्तर प्रदेश विश्व का पांचवा देश होगा. चौधरी ने कहा कि प्रदेश के पुनर्गठन के लिए सभी समूहों से बात करके समन्वय समिति बनाकर काम करना होगा. पूरे प्रदेश में एक साथ सभी वर्गों व सहयोगियों को साथ लेकर जन आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत है. सम्मेलन के बाद प्रदेश की राजनीतिक-प्रशासनिक स्थिति को लेकर चौधरी अजीत सिंह ने राज्यपाल राम नाईक से भी मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया.

सम्मेलन में बुन्देलखंड बनाओ संगठन की समन्वय समिति के संयोजक डॉ. बाबूलाल तिवारी, पूर्वांचल राज्य बनाओ समिति के अध्यक्ष डॉ. सुधाकर पांडेय एवं पूर्वांचल राज्य बनाओ आन्दोलन के संयोजक रमाशंकर यादव, पूर्वांचल बनाओ मंच के संयोजक पत्रकार सुरेश पाठक तथा बुन्देलखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री रवींद्र कुरेले सहित पूर्वांचल, बुन्देलखंड एवं हरित प्रदेश की मांग कर रहे अन्य कई संगठनों के अध्यक्षों एवं समितियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन का संचालन राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश(मध्य) के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मुन्ना ने किया. सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों सहित अन्य संगठनों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

बुन्देलखंड बनाओ संगठन की समन्वय समिति के संयोजक डॉ. बाबूलाल तिवारी ने चौधरी अजीत सिंह को राज्यों के पुनर्गठन का प्रेरणाश्रोत बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के चारों राज्यों (मांगाधीन) में न तो सम्पदा की कमी है और न ही प्रतिभा और क्षमता की. बुन्देलखंड के लाल बुन्देखंड में सरकार चलाने में सक्षम हैं. हम सभी आज चौधरी अजीत सिंह से सरकार की चाभी मांगने आये हैं. उन्होंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा में बुन्देलखंड अत्यंत पिछड़ा है, लेकिन सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं. राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बुन्देलखंड सहित हरित प्रदेश और पूर्वांचल बनाने की मांग को लेकर सबको एक साथ लड़ना है. उन्होंने यह नारा दोहराया कि हरी भरी सब धरती हो, बंजर भूमि न परती हो और कहा कि बुन्देलखंड से 600 अरब रुपये राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन सरकारें उसका चौथाई हिस्सा भी विकास के लिए व्यय नहीं करती हैं. बुन्देलखंड में पौराणिक स्थल हैं, खनिज सम्पदा का अम्बार है और इतनी बिजली पैदा होती है कि बिजली उत्पादन से ही बुन्देलखंड का विकास हो सकता है, लेकिन सरकार अपना स्वार्थ देख रही है. बुन्देलखंड का इतिहास चौदहवीं सदी से है. इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताजमहल और मथुरा जैसी प्रसिद्ध नगरी है. इसके अलावा अगर गन्ने के उद्योग पर ध्यान दें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश साबित होगा. उन्होंने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कहा कि यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारी के पास ढाई किलो हीरा बरामद होता है, जबकि किसी दुकानदार के घर ढाई किलो जीरा नहीं मिलता. प्रदेश में तमाम नौकरियों की भर्तियों में घोटाला ही घोटाला है.

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि छोटे राज्यों की वकालत सिर्फ चौधरी अजीत सिंह ने की और किसी ने नहीं की. वर्तमान समय में छोटे राज्यों का मुद्दा अहम मुद्दा है, क्योंकि यह मुद्दा रोजगार, विकास और किसानों की सिचाई से जुड़ा है. छोटा राज्य होगा तभी खुशहाल राज्य होगा. तेलंगाना के समय चौधरी अजीत सिंह ने अपना मंत्री पद त्याग दिया था. चौधरी चरण सिंह ने विकास की दृष्टि से प्रदेश के बंटवारे की बात उठाई थी. उन्होंने कहा था कि एक आदमी इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई नहीं चला सकता, इसलिए प्रदेश का पुनर्गठन जरूरी है. डॉ. सुधाकर पांडेय ने कहा कि छोटे राज्य में निश्चित तौर पर विकास के रास्ते खुलते हैं. पूर्वांचल में 28 चीनी मिलें हैं जिनमें 14 बन्द पड़ी हैं, लेकिन सरकारें किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं. इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के करीबी सुल्तानपुर जिला के युवक कांग्रेस पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. बलराम सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की.

सम्मेलन को पूर्वांचल राज्य बनाओ के संयोजक रमाशंकर यादव, बुन्देलखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री रवींद्र कुरेले, पूर्वांचल बनाओ मंच के संयोजक सुरेश पाठक, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. मसूद अहमद, राष्ट्रीय लोकदल विधान मंडल दल के नेता ठाकुर दलबीर सिंह, विधान परिषद के नेता चौधरी मुस्ताक अहमद, चौधरी सत्पाल सिंह, राममेहर सिंह गुर्जर, संतोष कुमार मिश्रा, चक्रपाणि यादव, बुन्देलखंड के नेता अशोक निरंजन, ओंकार सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया. सम्मेलन में रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे, शिवकरन सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुंशीराम पाल, विधायक वीरपाल राठी, त्रिलोकीराम दिवाकर, भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, पूरन प्रकाश, पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह बालियान, रामबाबू शास्त्री रामप्यारे सिंह पटेल, डॉ. सुरेश यादव, संतोष यादव, युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र सिंह पटेल, प्रदेश महासचिव डॉ. अनिल चौधरी, प्रो. यज्ञदत्त शुक्ल, हाजी वसीम हैदर, राजेन्द्र सिंह चिकारा, भोपाल सिंह गूर्जर, रामेन्द सिंह परमार, मंजीत सिंह, चौधरी भूपाल सिंह, आरिफ महमूद, मंजू चैधरी, किरन सिंह, देवप्रकाश राय, राजकुमार त्यागी, रजनीकांत मिश्रा, देव प्रकाश राय, सुरेश अग्रहरि, सर्वानंद तिवारी, प्रमोद यादव, ज्योति अग्रवाल, राममेहर राठी, रघुनाथ सिंह, बीएल प्रेमी, बृजेश सोनी, शैलेन्द्र सिंह सहित सैकड़ों प्रतिनिधि उपस्थित थे.■

मायावती और चौधरी में मौलिक फर्क है: अनिल दुबे

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि मायावती या अन्य हवा में उड़ने वाले नेताओं और चौधरी अजीत सिंह में मौलिक फर्क है. यह पूछने पर कि मायावती भी उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में विभाजित करने की बातें करती रही हैं, फिर चौधरी और मायावती में क्या फर्क है? अनिल दुबे ने कहा कि मायावती जब राज्यों के पुनर्गठन की बात कहती हैं तो वह सिर्फ राजनीति करती हैं, लेकिन जब चौधरी पुनर्गठन की बात कहते हैं तो वे लोगों की पीड़ा और त्रासदी देख कर उनकी जरूरतों की बात करते हैं. मायावती ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात तो की, लेकिन जब उनके पास बहुमत की सरकार थी, तब विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं भेजा? मायावती ने केवल पत्र लिखने की औपचारिकता कर दी थी. उनके पास तो संख्या बल भी था, वो चाहतीं तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पाले में गेंद डाल सकती थीं. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. रालोद के पास संख्या बल कम है, लेकिन राज्य के पुनर्गठन के लिए जमीन पर आंदोलन करने में सबसे आगे रालोद ही रहा है. चौधरी ने कहा भी है कि चारों राज्यों के निर्माण की मांग कर रहे संगठनों को एक साथ मिला कर संघर्ष को एकीकृत किया जाएगा. इसके लिए संयुक्त समन्वय समिति का गठन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. चारों राज्यों (मांग वाले) में बैठकों और सम्मेलनों का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है, जिससे व्यापक जनमत तैयार हो सके. उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की मांग करके चौधरी अजीत सिंह ने क्या भविष्य में समाजवादी पार्टी से किसी तालमेल की संभावना को नकार दिया है, क्योंकि सपा तो उत्तर प्रदेश के विभाजन पर कतई तैयार नहीं है? दुबे ने कहा कि चुनाव की रणनीति और प्रदेश के पुनर्गठन की जरूरत दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं, इसे आपस में तालमेल नहीं किया जा सकता है. चुनाव के समय तालमेल और गठबंधन की क्या स्थिति बनेगी, इस बारे में अभी कहा नहीं जा सकता. लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में पुनर्गठित करने की मांग पर राष्ट्रीय लोकदल अडिग है.■

आठ फीट से ऊंची कांवड़ और डीजे पर होगा प्रतिबंध

राजकुमार शर्मा

धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के प्रारम्भ होते ही कावड़ियों का भारी जमावड़ा होने लगता है. हजारों की संख्या में शिवभक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए हर की पौड़ी पहुच कर गंगा जल से कांवड़ भरते हैं. डाक कांवड़ की परम्परा भी रोचक है. वाहन सजा कर, गाजा बाजा के साथ पैदल शिवभक्त गंगोत्री से गंगा जल लेकर अपने अराध्य को अपनी मान्यतानुसार अर्पित करते हैं. इन अवसरों पर भगवा वेश में सजी कांवड़ के साथ लोगों की भीड़ चलती है. एक अगस्त से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सीसीआर में चार राज्यों के अधिकारियों ने मंथन किया. यातायात नियंत्रण, चेकिंग, कानून व्यवस्था का मिलकर पालन कराने पर सहमति बनी. कांवड़ मेला के अंतिम दिनों में डाक कांवड़ का जोर रहता है. सैकड़ों वाहनों में लाखों शिवभक्त हरिद्वार आते हैं और जलभरकर अपने गंतव्यों को रवाना होते हैं. इन डाक कांवड़ों का समय निर्धारित होने की वजह से वाहनों में आगे निकलने की होड़ रहती है. अधिकारियों का मानना है कि इसी वजह से अंतिम दिनों में अव्यवस्था फैलती है और जाम की समस्या उत्पन्न होती है. इसे देखते हुए इस बार डाक कांवड़ों में समय सीमा का प्रतिबंध बंद कराया जाएगा.

कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नुकीली चीजें बड़े त्रिशूल, तलवार, हॉकी, डंडे आदि लाने से भी शिवभक्तों को रोका जाएगा. आठ फीट से ऊंची कांवड़ और डीजे प्रतिबंध होगा. प्रशासन ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी रूप में नहीं होने दिया जाएगा. अगर कोई यातायत नियमों उल्लंघन करता है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी. जिनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी, उनके वाहनों का नंबर नोट कर चालान घर भेजे जाएंगे. शिवभक्तों को परिचय पत्र अपने साथ रखना होगा और जलाभिषेक के लिए गोमुख जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होगी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे गढ़वाल के कमिश्नर सीएस नपलच्याल ने बताया कि कांवड़ मेला की व्यवस्थाओं को लागू कराने में सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा. मेले से जुड़े उत्तराखंड सहित पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों का ग्रुप बनाया जाएगा. इससे शिवभक्तों की मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जाएगी. किसी भी क्षेत्र से भीड़ अधिक बढ़ने पर आगे तुरंत इसकी सूचना पहुंचाई जाएगी. कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ोसी राज्यों सहित समस्त जनपदों के नोडल अधिकारी तैनात होंगे, जो कांवड़ मेले के लिए उत्तरदायी होंगे.

कमिश्नर ने जुलाई के अंत तक कांवर मेला से संबंधित पानी, बिजली, सड़क की तैयारियां पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया जाएगा. कांवड़ यात्रा में एनजीटी के आदेश के तहत पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा. कांवड़ मेला को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है. पूरा प्लान दो चरणों में बनाया गया है. इस बार दिल्ली-हरिद्वार हाईवे को मेला के दौरान पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा. एक से सात अगस्त तक हाईवे छोटे वाहन और रोडवेज बसों के लिए खुला रहेगा, जबकि आठ अगस्त से वन वे व्यवस्था लागू होगी. भारी वाहन वाया बिजनौर हरिद्वार आएंगे, आठ अगस्त से इनके हरिद्वार में प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. दिल्ली सहित, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नैनीताल, देहरादून आदि क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई गई है. एसएसपी हरिद्वार स्वीटी अग्रवाल ने ट्रैफिक प्लान पेश किया.

एक से सात अगस्त तक सभी स्थानों से रोडवेज बसें अपने निर्धारित रूट से आएंगी. आठ अगस्त से दिल्ली, मेरठ, मुजफरनगर से आने वाली बसें मीरापुर, बिजनौर होते हुए नीलधारा पार्किंग पहुंचेंगी. यहीं से वापसी होगी. हरियाणा, पंजाब, सहारनपुर से आने वाली बसों को छुटमलपुर से देहरादून होकर मोतीचूर पार्किंग तक लाया जाएगा. इनकी वापसी भीमगोड़ा बैराज से चीला होते हुए होगी. कुंभ के बाद हरिद्वार के सबसे बड़े स्नान पर्व कांवड़ मेला के लिए पहली बार शासन से बजट मिलेगा. स्थानीय प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है. इस साल कांवड़ मेला में करीब तीन करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. हर साल कांवड़ मेला में हजारों श्रद्धालु आते हैं. इसके लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं की जाती थी. पुलिस सहित संबंधित विभागों को अपने संसाधनों पर ही पूरी व्यवस्था संभालनी पड़ती है. संसाधनों के अभाव में विभागों को हर बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बीते कुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए डीजीपी ने बजट के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता करने का आश्वासन दिया था. इस संबंध में कांवर मेला से संबंधित विभागों ने बजट का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है. जल्द ही बजट स्वीकृत होने की उम्मीद जताई जा रही है. संबंधित विभागों द्वारा बजट का प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि करते हुए एसए मुरुगेशन, मेलाधिकारी हरिद्वार ने कहा कि पुलिस, नगर निगम कुछ विभागों ने कांवड़ मेला के लिए बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजा है. इस संबंध में शासन स्तर पर फैसला होना है. कांवड़ मेले को शुरू होने में मात्र 17 दिन शेष हैं. मेले को लेकर अधिकारी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. अब तक कांवड़ पटरी की हालत सुधारने के लिए कोई गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए गए हैं. जबकि कांवड़ पटरी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है. कई स्थानों पर सड़क ही धंसने लगी है. धर्मनगरी हरिद्वार में कांवर मेला को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है. अधिकारियों की ओर से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण कांवड़ मेला संपन्न कराने के दावे किए जा रहे हैं. जिस कांवड़ पटरी पर शिवभक्तों को चलना है, इसकी स्थिति सुधारने की दिशा में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है. डामकोठी से पुल जटवाड़ा तक जगह-जगह कांवड़ पटरी खस्ताहाल है. जगह-जगह गहरे गड्ढे हो चुके हैं. बरसात में मिट्टी कीचड़ में तब्दील होती जा रही है. इतना ही नहीं ऋषिकुल में पुल के पास नहर पटरी का धंसाव शुरू हो गया है, जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है. कई स्थानों पर बिजली के खंभे भी जर्जर हाल में हैं. शंकराचार्य चौक के निकट भी कांवड़ पटरी मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है. संजय गुज्याल का कहना है कि कांवड़ मेला के कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा. मेला प्रारंभ होने से पूर्व कांवड़ पटरी मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त करने का प्रयास कियाद एगा.■

पहाड़ों पर भू-स्खलन का खतरा बढ़ा

ग्लोबल वार्मिंग के कारण सरक रहे ग्लेशियरों की वजह से उत्तराखंड की मध्य हिमालयी रेंज में झीलें बनने का क्रम तेज हो गया है, जो उत्तराखंड के लिए किसी भी समय खतरे का सबब बन सकता है. आपदा के बाद पहाड़ों पर बनने वाली झीलों पर नजर रखी जा रही है. झीलों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है, जिससे इनकी मॉनीटरिंग हो सके. मध्य हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में अभी तक ग्लेशियरों के आसपास और दूसरे स्थानों पर झीलें चिन्हित की गई हैं. अलकनंदा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चार सौ ग्लेशियर हैं. ये पांच से 10 मीटर पीछे खिसके हैं. वाडिया भूगर्भ संस्थान ग्लेशियरों के खिसकने की वजह से बनने वाली झीलों पर काम कर रहा है. सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अभी तक 1265 झीलें चिन्हित की गईं. इसके बाद इनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है.

ग्लेशियरों के पीछे खिसकने से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की नदियां विकराल रूप ले रही हैं. नदियों के दोनों किनारों पर कटान बढ़ रहा है. इससे नदी किनारे के दोनों तरफ के पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा अधिक हो गया है. तेज बारिश में यह खतरा और भी बढ़ जाएगा. यह चेतावनी जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई) ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर दी है. जीएसआई पहले ही चेता चुका है कि हिमालयी क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन के असर से ग्लेशियरों का मिजाज बदला है. इसकी वजह से नदियों की गतिविधियों में भी परिवर्तन आ रहा है. नदियों में पानी बढ़ेगा और वे तेजी से अपने रास्ते भी बदल सकती हैं. भूगर्भ के अंदर चल रही टेक्टोनिक गतिविधियां, ऊंचा उठता हिमालय और पीछे खिसकते ग्लेशियर एक हिमालयी क्षेत्र के वातावरण के लिए एक खतरनाक त्रिकोण बना रहा है.■

सपा के रोजा इफ्तार में लजीज़ भोजन और अजीज़ अमर पर हुई चर्चा

अमर की आमद, आज़म नदारद

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी का इस बार का रोजा इफ्तार सचमुच सियासी रहा. कार्यक्रम में अमर सिंह ससम्मान मौजूद रहे और आजम खान बाइज्जत गैरहाजिर रहे. अमर के विरोधी रहे सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव भी सपा के रोजा इफ्तार में शरीक नहीं हुए. इस हाजिरी और गैर-हाजिरी के गंभीर राजनीतिक निहितार्थ तो हैं ही. रोजा इफ्तार में कांग्रेसी सांसद प्रमोद तिवारी का अतिरिक्त उत्साह भी कई सियासी मायने बखान कर रहा था. रोजा इफ्तार के बहाने एक बड़े मुस्लिम जनसमूह के समक्ष अमर सिंह का स्वागत बिना कुछ कहे ही काफी है. फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा की विधान परिषद में आमद की कवायद को अमर-स्वागत-भाव के त्वरित उत्पाद के बतौर देखा जा रहा है. जयाप्रदा का ड्राइविंग लाइसेंस अमर सिंह के लखनऊ के पते पर बनने का भी तो कुछ मतलब होता है!

बहरहाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 14 जुलाई को अपने सरकारी आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और सपा के पूर्व महासचिव अमर सिंह एक साथ एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. लेकिन वरिष्ठ नेता आजम खान नहीं पहुंचे. लोग काफी देर तक आजम खान को तलाशते रहे और उनकी गैरमौजूदगी के मायने समझते रहे. अमर सिंह ने सुबह ही मुख्यमंत्री आवास जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. दोनों के बीच तकरीबन एक घंटे तक गुफ्तगू होती रही. इसके बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव खुद अमर सिंह के गोमती नगर स्थित आवास पर गए और वहां करीब दो घंटे उनके साथ रहे. इस मुलाकात में पूर्व सांसद जयाप्रदा भी मौजूद थीं.

अमर सिंह अब मुलायम के खासे करीब आ चुके हैं. अभी हाल ही में मुलायम और लालकृष्ण आडवाणी के बीच हुई मुलाकात में अमर सिंह भी शामिल थे. इसके पहले भी मुलायम कई बार सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि उन्हें अमर सिंह की कमी खलती है. वे नेताओं मंत्रियों को यह उलहना भी दे चुके हैं कि कोई भी नेता अमर सिंह सरीखा परिणाम देने वाला (रिजल्ट-ओरिएंटेड) नहीं है. जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर अमर ने मुलायम के साथ मंच साझा किया था, तो काफी सरगर्मी फैली थी, अब इस तरह की साझेदारी आम हो चुकी है. धीरे-धीरे अमर सिंह की वापसी का रास्ता खुद ब खुद सरल होता जा रहा है. कुछ ही दिन पहले वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव भी कह चुके हैं कि अमर के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हैं. ऐसे में मुलायम द्वारा अमर सिंह का हाथ पकड़ कर नजदीक लाना नजदीकियों पर मुहर लगाने वाला साबित हुआ. अखिलेश के रोजा इफ्तार में मुलायम ने अमर सिंह को सहारा देकर मंच पर चढ़ाया. अमर सिंह सहारे के लिए छड़ी लिए हुए थे. पैर में तकलीफ के कारण उन्हें चलने में दिक्कत थी. मंच पर चढ़ने को हुए तो मुलायम सिंह यादव ने पीछे मुड़कर अमर को अपना सहारा दिया.

रोजा इफ्तार की दावत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से दी गई थी, जिसमें कई मुस्लिम धर्मगुरु और भारी तादाद में रोजेदार शामिल हुए. सभी अतिथियों का स्वागत अखिलेश, मुलायम और अमर ने साथ-साथ किया, तो वहां का सियासी परिदृश्य स्पष्ट रूप से एकबारगी ही पलट गया. कुछ समय बाद मुख्यमंत्री आवास से मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह साथ-साथ ही बाहर आए.

अखिलेश यादव की रोजा इफ्तार पार्टी में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की उत्साहपूर्ण मौजूदगी भी खासी चर्चा में रही. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रोजा इफ्तार भोज में मुलायम के शरीक नहीं होने से अधिक चर्चा में रहा प्रमोद तिवारी का सपा के रोजा इफ्तार में शरीक रहना. सोनिया की इफ्तार पार्टी में सपा का कोई नेता नहीं गया, लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सपा के रोजा इफ्तार में शरीक हुए. पिछले ही दिनों प्रमोद तिवारी अपनी बिटिया आराधना मिश्रा उर्फ मोना मिश्रा के साथ मुख्यमंत्री से मिले थे. सपा नेता कहते हैं कि प्रमोद तिवारी का अपनी बिटिया के साथ मुख्यमंत्री से मिलना निरुद्देश्य तो नहीं ही माना जा सकता. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सपा के समर्थन से ही राज्यसभा तक पहुंचे हैं.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रोजा इफ्तार भोज में बड़ी संख्या में शिया एवं सुन्नी समाज के रोज़ेदार शरीक हुए. इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, वरिष्ठ मंत्री अहमद हसन, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, शिव कुमार बेरिया, शाहिद मंजूर, महबूब अली, पारसनाथ यादव, ओम प्रकाश सिंह, अम्बिका चौधरी, गायत्री प्रसाद प्रजापति, अभिषेक मिश्रा, सांसद धर्मेन्द्र यादव, नदवा कॉलेज के प्रिंसिपल हजरत मौलाना सईदुर्रहमान आजमी, नायब सदर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और सज्जादा नशीन ख्वाजा मखदूम फखरूद्दीन अशरफ, लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, टीले वाली मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुर्रहमान वायजी, इमाम-ए-ईदगाह उजरियांव गोमतीनगर मौलाना सईद साहब, दादा मियां दरगाह के सज्जादा नशीन सबाहत हसन, दरगाह शामीना शाह के राशिद अली मिनाई, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मौलाना तारिक, मौलाना शाहिद नदवी, मस्जिद नदवा कॉलेज के शाही इमाम मौलाना फरमान नदवी, मुस्लिम मसाइल बोर्ड के सदर हाफिज सगीर, अमीर-ए-जमात के मौलाना अमानुल्लाह नदवी, खानकाये रशीदिया जौनपुर के सज्जादा नशीन मोहम्मद जिलानी, इमाम साहब शहर टांडा अम्बेडकरनगर के मौलाना मुख्तार सहित प्रदेश की कई दरगाहों के सज्जादा नशीन और मदरसों के उलेमा भी इफ्तार में शामिल हुए.

रोजा इफ्तार पार्टी में प्रदेश के अपर महाधिवक्ता जफ़रयाब जीलानी, करामत डिग्री कालेज की प्रधानाचार्या रुखसाना लारी, तालीमगाह निसवां की प्रधानाचार्या तबस्सुम किदवई, हुसैनिया कॉलेज जौनपुर के मौलाना तौफीक, वाराणसी यूनिवर्सिटी के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. ए. अहमद अंसारी, वाराणसी यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के प्रोफेसर नसीम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. मुश्ताक अली, शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास, नाजमिया अरबिक कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य मौलाना फरीदुल हसन, मजलिस-ए-उलेमाये हिन्द के मेम्बर मौलाना इंतिजाम हैदर, चार्टर्ड मरकेंटाइल बैंक के एमडी रजा हैदर, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. नैय्यर जलालपुरी, अम्बालिका इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉ. कमर अब्बास, आईईटी के रजिस्ट्रार डॉ. तनवीर ताहिर, आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रो. हुसैन अब्बास, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ के सदस्य मौलाना यासूब अब्बास, शिया पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य एमएस नक़वी, प्रो. टीएस नक़वी एवं वीर शहीद अब्दुल हमीद की धर्मपत्नी श्रीमती रसूलन बी और उनके पोते भी इस मौके पर मौजूद थे. अखिलेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और अफसरों के साथ-साथ मुख्य सचिव आलोक रंजन और पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

अमर सिंह के घर के पते से बना जयाप्रदा का ड्राइविंग लाइसेंस

फिल्म अभिनेत्री व रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा का ड्राइविंग लाइसेंस अमर सिंह के लखनऊ स्थित घर के पते से बना है. अमर सिंह का घर गोमती नगर के विपुल खंड में है. आरटीओ दफ्तर का कहना है कि जयाप्रदा का लाइसेंस बनने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. जयाप्रदा के लिए लखनऊ आरटीओ दफ्तर में पिछले दिनों खास इंतजाम किया गया था. उन्हें रात को दफ्तर बुलाया गया, वहां महज कुछ मिनटों में उनका बायोमेट्रिक टेस्ट लिया गया, आनन-फानन बाकी औपचारिकताएं पूरी की गईं और उन्हें लाइसेंस दे दिया गया. जयाप्रदा को रात में आरटीओ दफ्तर बुलाए जाने पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आरटीओ का कहना था कि जयाप्रदा को लेकर कोई कानून व्यवस्था की गड़बड़ी न हो, इसके लिए यह इंतजाम किया गया था.

मुलायम के सलाहकार की भूमिका में हैं अमर सिंह

अमर सिंह सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सलाहकार की भूमिका में आ गए हैं. समाजवादी पार्टी के कई अहम निर्णयों में अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रह रही है. अमर सिंह ही पिछले दिनों मुलायम को लालकृष्ण आडवाणी से मिलवाने ले गए थे. सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी अमर सिंह नेपथ्य से सलाह और सुझाव देते रहते हैं. अमर सिंह ने ब्रिटिश राजदूत को अखिलेश यादव से मिलवाया था. विदेशों में अखिलेश यादव के कार्यक्रमों के आयोजनों के पीछे भी अमर सिंह की सक्रिय भूमिका बताई जाती है.

विकास के काम में बाधा नहीं डालती सेना: रक्षा मंत्री

अखाड़ा नहीं बनेंगी सैन्य छावनियां

अखिलेश्वर पांडेय

केंद्रीय रक्षामंत्री मनोहर परिकर पिछले दिनों लखनऊ में थे. रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सदस्य भी हैं. लिहाजा, उन्होंने लखनऊ को प्रमुखता देते हुए यहां से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने सेना के साथ-साथ छावनियों के आधुनिकीकरण की योजनाएं बताईं तो एक रैंक-एक पेंशन के मसले पर भी कहा कि सैन्यकर्मियों को शीघ्र ही खुशखबरी मिलेगी. रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह सांकेतिक संदेश भी दिया कि विकास के किसी भी कार्य में सेना बाधा नहीं डालती. अखिलेश यादव ने कुकरैल फ्लाईओवर को लेकर कहा था कि सेना विकास के कार्य में बाधा डाल रही है. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सैन्य छावनियों को अखाड़ा न बनाया जाए. रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपनी रक्षा करना जानते हैं. पाकिस्तानी रक्षामंत्री के परमाणु हथियार की चेतावनी की बात पर उन्होंने कहा कि म्यांमार जैसा ऑपरेशन गोपनीय तरीके से किया जाता है, इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. स्थानीय बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) में मध्य कमान की 25 छावनियों के पार्षदों, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ व डीईओ के साथ दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर परिकर ने कहा कि आम जनता और सेना के बीच अखाड़ा बनते जा रहे छावनी क्षेत्रों को विकास में बाधक नहीं बनने दिया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा न हो तो छावनी किसी भी प्रोजेक्ट में बाधक बनने के बजाय देश के विकास में अहम योगदान देगा. उन्होंने कहा कि विधायक या सांसद बनने और उसका काम करने में खास समस्या आड़े नहीं आती. लेकिन छावनी के सदस्यों को उनके काम और क्षमताओं की जानकारी के लिए यह ओरिएंटेशन कार्यक्रम आवश्यक है. इससे छावनी क्षेत्रों में विकास के काम करने में आसानी होगी.

मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए रक्षामंत्री परिकर ने कहा कि देश के अंदर सेना और सिविलियंस का सबसे ज्यादा सामना छावनियों में होता है. लेकिन अनदेखी की वजह से वहां पर दोनों के बीच तनाव पैदा होता जा रहा है. इसके पीछे उन्होंने छावनी परिषदों के सदस्यों को उनकी क्षमताओं की जानकारी न होने और व्यवस्थित अप्रोच की कमी को बताया. उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा टकराव जिन बिंदुओं पर है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में दूर कर लिया जाएगा. कैंटोन्मेंट एक्ट-2006 में जरूरी बदलाव किये जाएंगे. साथ ही कैंटोन्मेंट डेवलपमेंट प्लान लाकर छावनी क्षेत्रों के विकास का खाका खींचा जाएगा. रक्षामंत्री के अलावा कार्यक्रम में मध्य कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जीएस शेरगिल, रक्षा संपदा के डीजी मध्य कमान रविकांत चोपड़ा के अलावा मध्य कमान की 25 छावनियों के नव निर्वाचित सदस्य मौजूद रहे. परिकर ने कहा कि छावनी परिषद के सदस्यों के साथ हुई बातचीत व अधिकारियों से चर्चा के आधार पर मंत्रालय को सात मुद्दे ऐसे लगे हैं जिनका दूर होना आवश्यक है. इनमें सड़कों के बंद होने, कैंटोन्मेंट एक्ट में बदलाव, संपत्तियों व जमीनों को लीज पर देने, लीज रिन्यूवल और खाली पड़ी जमीनों के लैंड कनवर्जन की समस्या है. जिनकी वजह से रक्षा विभाग को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और लोगों को समस्या भी हो रही है. उन्होंने कहा कि छावनी परिषदों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए रक्षा मंत्रालय से सीधे फंड आवंटन पर विचार हो रहा है. मैट्रो योजना के लिए छावनी की जमीन बाधा नहीं बनेगी. राज्य सरकार अगर छावनी से होकर मेट्रो निकालना चाहती है, तो वह प्रस्ताव पर बिना देर किए कार्रवाई करेंगे. परीकर ने कहा कि लखनऊ छावनी में तीन साल से लटके पीएनजी मामले को हरी झंडी जल्द मिलेगी. अन्य छावनियों में भी पीएनजी के लिए आ रही बाधा जल्द ही दूर होगी. उन्होंने पार्षदों की मांग पर उत्तर प्रदेश के महानगरों में कैंट क्षेत्र में भी मैट्रो रेल सेवा के विस्तार पर सहमति जताई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास के किसी भी काम पर सेना अड़चन नहीं बनती है. रक्षामंत्री ने कहा कि सीवेज के लिए इस साल के लिए कैंटोन्मेंट मास्टर प्लान लागू होने जा रहा है. मंत्रालय ऐसी पॉलिसी बना रहा है, जिसकी मदद से छावनियों में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं बेहतर होंगी. सेना और छावनी परिषदों के बीच जमीन का विवाद भी खत्म होगा. फिलहाल मंत्रालय सात बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे रहा है. परीकर ने आतंकवाद बढ़ने का मुख्य कारण देश के आर्थिक पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी को माना. रक्षा मंत्री ने प्रदेश के छावनी परिषद के अधिकारियों तथा पार्षदों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द निस्तारण पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया. परीकर ने देश की सेना को मजबूत बनाने की सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि पांच से सात वर्ष के भीतर देश में निर्मित अत्याधुनिक हथियारों की बदौलत दुश्मनों से मोर्चा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश में एंटी टैंक गन का निर्माण चल रहा है. इसके अलावा जल्द ही वायुसेना से मिग 20-21 को रिटायर कर दिया जाएगा. इनके स्थान पर तेजस या फिर उससे भी आधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना में शामिल होगा. रक्षामंत्री ने बताया कि बोफोर्स तोपें खरीदे जाने के बाद से अब तक तोपें नहीं खरीदी गई हैं. जरूरतों के हिसाब से तोपें खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उत्तर पूर्व व कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसी हल्की तोपें भी ली जाएंगी, जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके. सेना में तीन हजार तोपों की जरूरत है.

जल्द आ सकती है वन रैंक-वन पेंशन स्कीम

वन रैंक-वन पेंशन पर जल्द अच्छी खबर आने की बात कहते हुए रक्षामंत्री मनोहर परिकर ने कहा कि मंत्रालय का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे अमल में लाया जा सकता है. रक्षामंत्री ने वन रैंक-वन पेंशन को अंतर विभागीय मुद्दा बताते हुए कहा कि जहां तक रक्षा मंत्रालय की बात है, तो हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है. कुछ अन्य कारणों से अभी इसमें समय लग रहा है लेकिन मैं कह सकता हूं कि जल्द ही अच्छी खबर होगी. समान रैंक के लिए समान पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक पिछले महीने से ही केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक रैंक एक पेंशन की को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पहले ही जता चुके हैं. वर्तमान में सेवानिवृत्त सैनिकों का पेंशन वेतन आयोग की समय-समय पर होने वाली अनुशंसाओं पर आधारित है. वर्तमान में 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए सैनिकों को उन्हें अपने कनिष्ठ सहयोगियों की तुलना में कम पेंशन मिल रहा है. ओआरओपी योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक रैंक और समान अवधि तक सेवा देने वाले सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को एकसमान पेंशन मिले और इसका उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से संबंध न हो.

देश की सुरक्षा करने में हम सक्षम हैं

रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है. आप आश्वस्त रहें, पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी काफी कम हुई है. हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान जिसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि वह हमले की सूरत में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे, इसपर परिकर ने कहा कि दूसरे के बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं है. भारतीय रक्षा मंत्रालय का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करने का है और वह अपने काम को बखूबी जानते हैं. हर काम को बेहद संजीदगी व सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है.

सरल व सधे अंदाज में दिया जवाब

गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए और रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद कई तेज तर्रार बयान देने वाले रक्षा मंत्री मनोहर परिकर अब सवालों का जबाव बेहद ही संजीदगी से सरल व सधे अंदाज में देने लगे हैं. यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में चीन ने लखवी के मामले में पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो उस पर रक्षामंत्री का सधा जवाब था कि यह विदेश, गृह मंत्रालय और प्रधामंत्री के स्तर का मामला है. ऐसे में रक्षा मंत्री के तौर पर वे इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते. पिछले दिनों पूर्वोत्तर राज्य में हुई क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई को लेकर जब उनसे पाकिस्तान में भी ऐसी कार्रवाई करने के बाबत पूछा गया, तो परिकर ने इस पर भी कुछ कहने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने बाद में सीधे तौर पर कहा कि जो काम करना होता है उसके बारे में सार्वजनिक स्थान पर कुछ भी कहना उचित नहीं होता.

सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

रक्षा मंत्री ने सेना भर्ती मेलों में होने वाली अनियमितताओं और अव्यवस्था खत्म करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने को अधिक व्यवहारिक बताया. इससे अब केवल पंजीकृत युवाओं को ही शारीरिक टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com